

4.1 किसी अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश की प्रक्रिया ऐसे वित्तीय ढांचे के चारों ओर संगठित की जाती है जिससे आर्थिक वृद्धि सुकर होती है। एक सुव्यवस्थित वित्तीय प्रणाली बचतों के कारगर संग्रहण तथा, या तो केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाकर या विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाकर या दोनों के समन्वयन से, सर्वाधिक उत्पादक उपयोगों में उनके आबंटन द्वारा वृद्धि का संवर्धन करती है। प्रतिरूपी तौर पर, कम विकसित पूंजी बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाएं एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाती हैं, जिसके द्वारा वित्तीय मध्यस्थ बचतकर्ताओं से संसाधन जुटाकर उन्हें उधारकर्ताओं को आबंटित करते हैं। परंपरागत तौर पर, बैंकों ने वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है क्योंकि वे एक वित्तीय प्रणाली में लेनदेन की लागतों तथा वित्तीय प्रणाली में सूचना की असममितियों के साथ अधिक उपयुक्त तौर पर निपटने में सक्षम हैं। वित्तीय बाजार विकसित होने के साथ लेनदेन की लागत तथा सूचना की असममितियां कम होती हैं, बचत-निवेश प्रक्रिया के मार्गदर्शन के लिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का महत्व भी बढ़ जाता है, तथा अतिरिक्त संसाधन वाले परिवार पूंजी बाजार लिखतों में अधिकाधिक निवेश करते हैं। ऐतिहासिक अनुभव यह दर्शाता है कि बाजार मध्यस्थता वाली अर्थव्यवस्थाओं सहित वस्तुतः सभी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों ने संसाधन संग्रहण तथा वृद्धि की प्रक्रिया के समर्थन में केंद्रीय भूमिका अदा की है, तथा यह कि बैंकों और अन्य मध्यस्थों का विकास होने से वित्तीय बाजारों का विकास स्वयं सुकर हुआ है।

4.2 संसाधन संग्रहण की प्रक्रिया में बैंकों की भूमिका की उत्पत्ति उन फर्मों में निहित है, जो वित्त के बाह्य स्रोतों पर, विशेष तौर पर अपने निर्माण की अवस्थाओं में, अत्यधिक निर्भर रहते हैं। विशेष तौर पर बैंकों ने अपने विकास के महत्वपूर्ण चरणों में 'टेक-ऑफ' के अभियंत्रण में बेल्जियम, जर्मनी, इटली तथा जापान जैसी कई अर्थव्यवस्थाओं में निवेश प्रयासों के समन्वयन में प्रमुख भूमिका निभाई है। बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण आर्थिक विकास के 'प्रेरक' के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। इन अर्थव्यवस्थाओं के 'टेक-ऑफ की अवस्था' में, बड़े तथा सशक्त बैंक आरंभ में कुछ संस्थापकों के पूंजी अंशदान पर निर्भर रहे तथा उसके बाद औद्योगिक उधार संबंधी उनके संविभाग के बढ़ने पर, उन्होंने निधियों के प्रमुख स्रोत के रूप में जमाराशि का आश्रय लिया। बाजारों का विकास होने के साथ, उधार भी बैंकों की निधियों का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया।

4.3 ऐतिहासिक रूप से, भारत में बैंकों द्वारा की गई वित्तीय मध्यस्थता ने, विशेष तौर पर 1960 के दशक के उत्तरार्ध में 14 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, बचत आस्तियां जुटाकर वृद्धि की

प्रक्रिया के समर्थन में केंद्रीय भूमिका अदा की है। बैंक घरेलू क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख अधिशेष क्षेत्र है, से जमाराशियां जुटाने में विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं, जिसने बदले में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत बढ़ाने तथा इस प्रकार समग्र बचत दर बढ़ाने में मदद की है। वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण तथा अन्य विभिन्न बचत लिखतों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के बावजूद, बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय मध्यस्थता में प्रमुख भूमिका निभाते जा रहे हैं। ब्याज दर के अविनियमन ने प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने में बैंकों के लिए नए क्षेत्र खोल दिए हैं। इसके अलावा, सभी वित्तीय लेनदेनों के लिए समाशोधन एवं निपटान का अंतिम प्लेटफार्म होने के नाते बैंक अन्य क्षेत्रों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थकों को लेखा तथा संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

4.4 हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन में सुदृढ़ वृद्धि हुई है तथा बैंकों ने अपेक्षित मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाई है। वृद्धि की प्रक्रिया बनाए रखने के लिए, बैंकों को बड़े पैमाने पर निधि प्रदान करना जारी रखना होगा। भारत में ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बचत की काफी संभाव्यता मौजूद है। साथ ही भारत में देशी बचत का काफी बड़ा भाग अनुत्पादक भौतिक आस्तियों में अवरुद्ध है। अब तक अदोहित क्षेत्रों से बचत के संग्रहण तथा भौतिक बचतों को वित्तीय बचतों में रूपांतरित करने से ऐसे उपयुक्त प्रोडक्ट शुरू करना आवश्यक होगा जो बचतकर्ताओं की मांग के अनुकूल हो। बैंक वस्तुतः ऐसा करने की आदर्श स्थिति में हैं क्योंकि जमाराशियों में सुरक्षा और तरलता जैसी कुछ अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं।

4.5 जमाराशि जुटाने के अलावा, संसाधन संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए बैंक देश तथा विदेश दोनों में गैर जमा संसाधनों पर भी निर्भर रहते हैं। गैर जमा संसाधनों का एक हिस्सा उधार से आता है, जो बैंकों की निधि संबंधी जरूरतें तुरंत बढ़ाने में मदद करता है। तथापि, ब्याज दर तथा विनिमय दर संबंधी संभाव्य जोखिमों के बीच उनकी उपलब्धता तथा उधार की लागत के प्रबंधन की भी चुनौती होती है। इस प्रकार, उधार के कारगर उपयोग के लिए बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन की उपयुक्त प्रणाली अपेक्षित है।

4.6 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में संसाधन संग्रहण की विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है तथा वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में और भारत में आर्थिक वृद्धि के समर्थन में बैंकों के सामने उपस्थित गुंजाइश और चुनौतियों का पता लगाया गया है। इस अध्याय को छः खण्डों में संगठित किया गया है। खण्ड II में बैंकों की मध्यस्थता की भूमिका के बारे में सैद्धांतिक समर्थन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड III

में, भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह पर आधारित संसाधन संग्रहण में वित्तीय मध्यस्थकों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका का विश्लेषण करने के बाद, भारत में बैंकों द्वारा जमा संग्रहण की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की ब्यौरेवार जांच की गयी है। बैंकों की देयता संबंधी संरचना में जमाराशियों के महत्व की भी चर्चा इस खण्ड में की गयी है। खण्ड IV में, उपयुक्त सीख लेने की दृष्टि से वित्तीय रूप से उदारीकृत तथा वैश्वीकृत वातावरण में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका संबंधी विभिन्न देशों के अनुभवों को शामिल किया गया है। खण्ड V में, भारत स्थित बैंकों के सामने उपस्थित उभरते मुद्दों तथा चुनौतियों की पहचान की गयी है और संसाधन संग्रहण की चुनौती को कारगर तरीके से पूरा करने के लिए भावी उपाय के तौर पर सुझाव दिए गए हैं। खण्ड VI में, इस अध्याय को समाप्त किया गया है।

II. सैद्धांतिक समर्थन

4.7 परंपरागत साहित्य के अनुसार, देशी वित्तीय प्रणाली तीन विभिन्न अवस्थाओं से होकर विकसित होती है, अर्थात् (क) बैंक-उन्मुख चरण, (ख) बाजार-उन्मुख चरण तथा (ग) सुदृढ़ तौर पर बाजार-उन्मुख चरण। बैंक-उन्मुख चरण में, जमाराशियों के रूप में बैंकों के जरिए अर्थव्यवस्था की बचत के बड़े भाग की मध्यस्थता की जाती है तथा उसे उधारकर्ताओं को अंतरित किया जाता है। इस प्रकार बैंक अधिशेष आर्थिक इकाइयों (बचतकर्ताओं) से घाटे वाली आर्थिक इकाइयों (उधारकर्ताओं) को संसाधन पुनरावंटित करने में वित्तीय मध्यस्थकों के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे इस विशेष भूमिका का निर्वाह करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है जो सूचना संबंधी असममितियों तथा अंतर-कालिक लेनदेन लागतों को, जो वित्तीय प्रणाली की अपूर्णताओं का केंद्रीय स्रोत है, सुधारने में कारगर हैं। जोखिम पूंजी प्रतिधारित लाभ तथा सीधे प्रवर्तकों से प्राप्त की जाती है, जिनकी संख्या थोड़ी होती है। बाजार-उन्मुख चरण में, फर्म वित्तीय मध्यस्थकों के बजाय अधिकाधिक बाह्य निधियों पर, पूंजी बाजारों के जरिए अंतिम बचतकर्ताओं से जुटायी गयी जोखिम पूंजी सहित, निर्भर रहते हैं। सुदृढ़ रूप से बाजार-उन्मुख चरण में, बैंक वित्तीय तथा पूंजी बाजारों के जरिए जुटायी गयी निधियों पर भी अधिकाधिक निर्भर रहते हैं तथा यहां नये वित्तीय-जोखिम-बचाव बाजार सामने आते हैं (रिब्लजिब्सकी, 1985)।

4.8 हाल के साहित्य में अग्रिम यह दर्शाते हैं कि परंपरागत बहस, अर्थात् बैंक आधारित वित्तीय संरचना अथवा बाजार आधारित वित्तीय संरचना आर्थिक वृद्धि का समर्थक होती है, वर्तमान संदर्भ में असंगत हो सकती है (लेवाइन, 2000)। विकास अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत वृद्धि के बैंक आधारित दृष्टिकोण में यह नोट किया जाता है कि विकास के चरण में निवेश के लिए कंपनी वित्तपोषण इक्विटी के बजाय बैंकों से ऋण के रूप में प्रमुख तौर पर जुटाया जाता है। वृद्धि के पोषण में बैंकों की तुलना में बाजारों की भूमिका के बारे में यह दृष्टि निराशावादी है। बदले में परंपरागत कंपनी वित्त बैंक, बांड तथा इक्विटी वित्तपोषण को

एवजियों के रूप में देखता है। बैंक निवेशकों की ओर से जानकारी प्राप्त करने और उसे प्रोसेस करने की लागत को कम करते हैं तथा इस प्रकार अनुलिपि और मुक्त राइडर की समस्याओं को टाल देते हैं। बैंक प्रतिवर्गीय तथा अंतर-कालिक जोखिम साझेदारी दोनों को भी समर्थ बनाते हैं। वे अलग-अलग एजेंटों से बचत संग्रहण से जुड़ी लेनदेन लागतों को कम करके तथा बचतकर्ताओं को अपनी बचतों का प्रस्ताव करने में सुखद अनुभव कराकर सूचना संबंधी असममितियों को जीतकर वित्तीय बचतों के संग्रहण को भी सुकर बनाते हैं। बचत का संग्रहण प्रभावी तौर पर करके वित्तीय मध्यस्थ न सिर्फ पूंजी के संचय को आसान बना देते हैं, बल्कि बड़े पैमाने की किफायतों के लाभ की अनुमति देकर संसाधन आबंटन में भी सुधार लाते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार बैंक आधारित वित्तीय प्रणालियां - विशेष रूप से आर्थिक विकास के आरंभिक चरणों में - आर्थिक वृद्धि के संवर्धन में बेहतर होती हैं। दूसरी ओर, बाजार आधारित दृष्टिकोण में जानकारी प्राप्त करने, कंपनी नियंत्रण लागू करने तथा कस्टम डिजाइन वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए निवेशकों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने में अच्छी तरह कार्य कर रहे प्रतिभूति बाजारों के महत्व पर बल दिया जाता है।

4.9 1990 के दशक से उभर रहा तीसरा दृष्टिकोण यह है कि बैंक तथा बाजार पूरक अथवा उसी तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय सेवा संबंधी दृष्टिकोण में इस बात का विश्लेषणात्मक महत्व है कि वित्तीय सेवा के कारगर प्रावधान के लिए किस प्रकार बैंक और बाजार दोनों आर्थिक वृद्धि के संवर्धन के लिए वित्तीय सेवाएं कारगर तौर से प्रदान करने हेतु सुदृढ़ प्रणाली तैयार करते हैं। वित्तीय प्रणालियां संभाव्य निवेश अवसरों का आकलन करती हैं, निधीयन संबंधी परियोजनाओं के बाद कारपोरेट नियंत्रण प्रदान करती हैं, चलनिधि जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन को सुकर बनाती हैं तथा बचत संग्रहण को आसान बनाती हैं। विधिक-आधारित दृष्टिकोण नामक एक और दृष्टिकोण, जिसका उदय 1990 के दशक में हुआ, वित्तीय सेवा संबंधी दृष्टिकोण का विस्तार करता है तथा बैंक-आधारित बनाम बाजार-आधारित बहस को बेशर्त अस्वीकार करता है और यह दलील देता है कि वित्त संविदाओं का एक सेट है जिसे विधिक अधिकारों तथा प्रवर्तन प्रक्रियाओं द्वारा कमोबेश कारगर बनाया जा सकता है। तदनुसार, विधिक प्रणाली द्वारा यथानिर्धारित वित्तीय सेवाओं के समग्र स्तर और गुणवत्ता से संसाधनों के कारगर आबंटन तथा आर्थिक वृद्धि में सुधार आता है। अतः, इसने इस बात पर बल दिया कि बैंक-आधारित अथवा बाजार-आधारित प्रणालियों की गुणवत्ता पर बहस करने के बजाय एक सुदृढ़ विधिक वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विभिन्न देशों के आंकड़े भी यह दर्शाते हैं कि जिन देशों में अधिक मात्रा में वित्तीय विकास हुआ है - जिसकी माप बैंक विकास तथा बाजार विकास के समग्र उपायों द्वारा की जाती है - वे दीर्घावधि वृद्धि के साथ सुदृढ़ रूप से जुड़े होते हैं। इसके अलावा, बाहरी निवेशकों के कानूनी अधिकारों तथा विधिक

प्रणाली की दक्षता द्वारा स्पष्ट किया गया वित्तीय विकास का घटक दीर्घावधि वृद्धि के साथ सुदृढ़ एवं सकारात्मक रूप में जुड़ा होता है। विधिक प्रणाली वित्तीय क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बदले में दीर्घावधि वृद्धि को प्रभावित करती है। इस प्रकार, बाजारों तथा बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना दीर्घावधि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः नीतिनिर्माताओं को बाहरी निवेशकों के विधिक अधिकारों तथा संविदा के प्रवर्तन की समग्र दक्षता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नीतिगत साधनों को बैंकों अथवा बाजारों के पक्ष में 'लेवल प्लेइंग फील्ड' को नहीं झुकाना चाहिए तथा इसके बजाय उन्हें संपत्ति के अधिकारों के रूप में मूलभूत तत्वों को सुदृढ़ करने तथा इन अधिकारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

4.10 बैंकों के लिए निधियों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख परिवर्ती केंद्रीय बैंक की नीति है जो बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित निधियों की कुल मात्रा को बदल देती है। परंपरागत साहित्य में किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जमा की स्थिति में परिवारों की पूर्ववचनबद्धता तथा कीस-प्रकार के 'दृढ़ मूल्यों' की मौजूदगी की स्थितियों के तहत, एक केंद्रीय बैंक उधार न ली गयी आरक्षित निधियों के अप्रत्याशित अंतर्वेश के जरिए बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित निधियों की मात्रा को बदल सकता है तथा इस प्रकार 'चलनिधि प्रभाव' का सृजन कर सकता है। इन मॉडलों में यह कल्पना की गयी है कि परिवार मौद्रिक नीति में अप्रत्याशित परिवर्तन के प्रतिसाद में अपनी तरल आस्ति धारिताओं, विशेष रूप से अपनी बैंक जमा की स्थिति, में तुरंत समायोजन नहीं लाते। बाद के मॉडलों में बांड जैसी वैकल्पिक लिखतें आरंभ कर, जिसके द्वारा परिवारों द्वारा फर्मों/ उधारकर्ताओं के प्रत्यक्ष वित्तपोषण की अनुमति दी गयी, इस ढांचे के प्रतिबंधों को शिथिल किया गया। इससे बैंक उधार के जरिए वित्तपोषित किये जा रहे कार्यशील पूंजी ऋण को प्रतिचक्रिय स्वरूप प्राप्त हुआ। यह मानकर कि बांड तथा बैंक जमाराशियां अपूर्ण एवजी हैं क्योंकि सभी फर्मों के पास बांड जारी करने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करने वाली क्वालिटी रेटिंग नहीं होती तथा इसलिए उन्हें बैंक उधार का आश्रय लेना पड़ता है, इन मॉडलों को और अधिक विकसित किया गया। तथापि, जमा बाजार समाशोधन के रूप में सतत प्रतिबंधों तथा मुद्रा आघात के पहले निर्धारित की जाने वाली जमा दर ने चलनिधि के प्रभाव की दृढ़ता को उत्पन्न किया। बांड बाजार के अभाव में, परिवारों को बैंक जमाराशियों के रूप में तरल आस्ति धारिता सहित मौद्रिक आधार के अवशोषण हेतु विवश किया जाता है, इस प्रकार वास्तविक मुद्रा शेष की मांग को अपेक्षाकृत अधिक रखा जाता है तथा धीरे-धीरे मूल्य समायोजन लाया जाता है। बांड बाजार की उपलब्धता से परिवारों को एक ऐसी बचत आस्ति मिलती है जो उनकी आय को मुद्रास्फीति से बचाने में मदद करती है। अतः मौद्रिक आघात के प्रतिसाद में बांडों की मांग बढ़ती है, इस प्रकार वास्तविक मुद्राशेष

की मांग कम होती है और कीमतों में उछाल को उनके दीर्घावधि संतुलन मार्ग की ओर प्रेरित किया जाता है। फलस्वरूप तीव्रतर आरंभिक मूल्य समायोजन के फलस्वरूप सांकेतिक ब्याज दरों में निम्नतर प्रत्याशित मुद्रास्फीति प्रीमियम मिलता है जो धीरे-धीरे गायब हो जाता है। इस प्रकार, परिवारों द्वारा जमा की स्थिति के प्रति पूर्व वचनबद्धता के रूप में सूचना के घर्षण तथा मौद्रिक (आरक्षित निधि आघात) वचनबद्धता के पूर्व बैंकों द्वारा जमा दरों के पूर्व निर्धारण से चलनिधि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तथापि, जब दोनों मान्यताएं परिचालित होती हैं, मॉडलों से उपभोग तथा निवेश में अत्यधिक अस्थिरता आती है। तथापि, जब परिवारों द्वारा जमाराशियों की पूर्व वचनबद्धता न्यूनतम होती है, यथा मूल प्रतिबंध पूर्व निर्धारित जमा दर होती है, चलनिधि प्रभाव तब भी मौजूद होती है, बैंक की मध्यस्थता प्रतिचक्रिय होती है, तथा उपभोग और निवेश का व्यवहार वास्तविक अनुभव के अनुरूप चक्रिय स्वरूप का होता है। यह बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही ब्याज दर नीति की तीन विशेषताएं सामने लाता है। पहला, लेनदेन खातों पर बैंक जमा दरें काफी धीमी गति से चलती हैं क्योंकि वे सीमांत दरों के बजाए औसत दरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, प्रबंधित देयताओं पर प्रदत्त ब्याज दरें बाजार दरों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। तथापि प्रबंधित देयताएं जमा निधियों के एक अंश का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तीसरा, फर्मों को दिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज दरें सामान्यतः ऋण व्यवस्थाओं के साथ संबद्ध की जाती हैं। ये सभी मुद्दे बैंक उधार की चक्रिय विशिष्टताओं को, और इसलिए वास्तविक अर्थव्यवस्था को मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय संप्रेषित करने की इसकी भूमिका को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही ब्याज दर नीतियों, विशेष रूप से जमा दर नीतियों पर हाल के वर्षों में क्रमिक रूप से अधिक ध्यान दिया जा रहा है (इनार्सन तथा मार्किव्स, 2003)।

4.11 परंपरागत तौर पर, स्थानीय बाजार की स्थितियां बैंकों की जमा मूल्यन नीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस संदर्भ में, यह पाया गया कि बैंक प्रतिरूपी तौर पर अधिक संकेंद्रित बाजारों में जमाराशियों पर कम ब्याज दरें देते हैं तथा ऋणों पर अधिक ब्याज दरें रखते हैं (बर्गर तथा हन्नान, 1989)। परंपरागत साहित्य के अनुसार, बैंक जमा दरें औसत बैंक आकार में तीव्र वृद्धि होने से प्रभावित नहीं होंगी, बशर्ते स्थानीय बाजार का संकेंद्रण अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित बना रहे। तथापि, हाल के बैंकिंग समेकन का अनुभव यह दर्शाता है कि स्थानीय बाजार संकेंद्रण को प्रभावित न करनेवाली बैंकों के औसत आकार में हुई वृद्धि ने स्थानीय बाजार की स्थितियों को बदल दिया है तथा ब्याज दरों के निर्धारण को प्रभावित किया है। बैंक के आकार में वृद्धि जमा दरों को प्रभावित कर सकती है यदि क्षेत्रीय अथवा बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन छोटी, स्थानीय संस्थाओं की तुलना में उस समय भी अलग रूपों में स्पर्धा करें जब विभिन्न संगठनों के पास उसी प्रकार की स्थानीय बाजार साझेदारी हो। इसके अलावा,

यद्यपि बैंकिंग बाजार सामान्यतः स्थानीय स्वरूप के होते हैं, हाल के वर्षों की गतिविधियों का साक्ष्य यह दर्शाता है कि प्राथमिक तौर पर स्थानीय बाजार में परिचालित बैंकों की तुलना में बहु-बाजार बैंक अलग रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। 1988 से 2004 तक की अवधि में समेकन प्रक्रिया के फलस्वरूप अमरीका में जमा दरों पर आकार की संरचना के प्रभाव ने प्रतिरूपी तौर पर एक विपरीत-V आकार के पैटर्न का अनुसरण किया। वर्ष 2000 तक बैंकों के विलय से, जिसके कारण जमाराशियां बड़े बैंकों के पास चली गईं, जमा दरें नीचे आईं क्योंकि बड़े बैंक छोटे बैंकों की तुलना में कम आक्रामक प्रतिस्पर्धी थे। इसे आंशिक रूप से, परंतु पूर्णतः नहीं, इस तथ्य द्वारा प्रतिबलित किया गया कि बहु-बाजार बैंकों में अधिक आक्रामक प्रतिस्पर्धी होने की प्रवृत्ति होती है। बाद की अवधि में प्रवृत्ति बदल गई जिससे यह दिखाई दिया कि बड़े बैंक अधिक आक्रामक प्रतिस्पर्धी बन गए जिसके कारण जमा दरें बढ़ गईं। ये अंतर्निहित प्रवृत्तियां जमा मूल्यन की कई विशिष्टताएं सामने लाती हैं। पहला, बैंकों के बड़ा होने के साथ जमा से इतर अधिक देयताओं तक उनकी पहुंच हो जाती है। प्रतिरूपी तौर पर, इससे जमाराशियों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करने की उनकी इच्छा कम हो जाती है। दूसरा, जैसे-जैसे बैंक बड़े होकर अनेक बाजारों में परिचालन करते हैं, वे स्थानीय बाजारों की स्थितियों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। तीसरा, चूंकि बैंक छोटे आकार के अन्य बैंकों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, बहु-बाजार वाले बड़े बैंकों की उपस्थिति बढ़ने से उनके बीच अधिक आक्रामक प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है जिससे ब्याज दरें बढ़ जाती हैं (रोशन,आर.जे.,2007)।

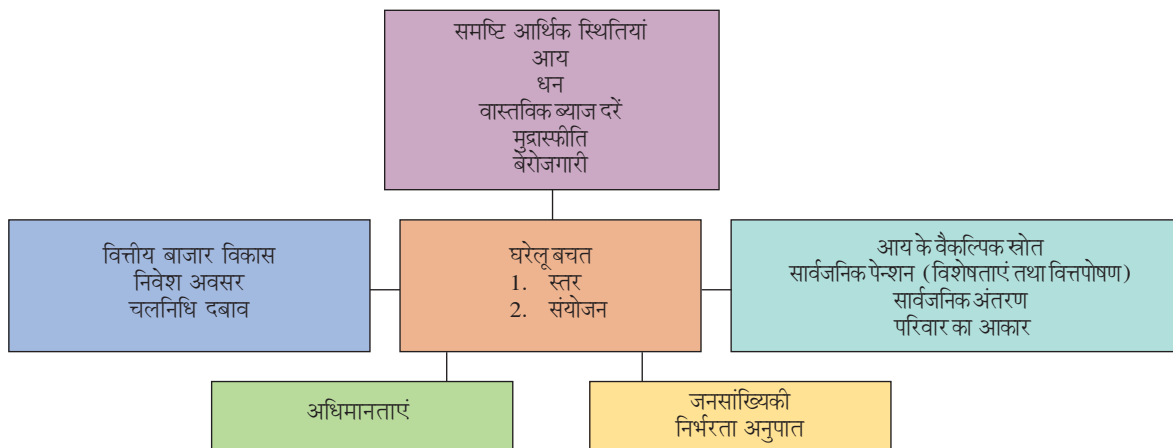
4.12 अंत में, चूंकि घरेलू बचतें बैंकों द्वारा मध्यस्थता के लिए संसाधनों का एक संभाव्य भंडार हैं, घरेलू बचतों के निर्धारकों में विकसित हो रही गतिशीलता का संसाधन संग्रहण संबंधी बैंकों के प्रबंधन में उन

पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जहां संसाधनों तक बैंकों की पहुंच घरेलू बचतों के बढ़ते हुए स्तर के अनुरूप बढ़ने की संभावना है, उसका वास्तविक आश्रय बचतों की उनकी संविदा संरचना के बारे में परिवारों के निर्णयों पर निर्भर होगा। बदले में, घरेलू बचतों का स्तर और उसकी संरचना समष्टि आर्थिक स्थितियों, वित्तीय बाजार की गतिविधि और विनियमन, वैकल्पिक आय स्रोतों, जनसांख्यिकी तथा घरेलू क्षेत्र की तरजीहों द्वारा प्रभावित होती है (प्रदर्श 1)। घरेलू तुलनपत्रों की आस्ति संरचना संबंधी देश भर के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि गैर वित्तीय आस्तियां उन देशों में, जहां आवास क्षेत्र की गतिविधियों ने निवेश के नए अवसर खोले हैं, कुल आस्तियों का एक प्रमुख हिस्सा हैं। दूसरी ओर, सुविकसित वित्तीय बाजारों वाले देशों में संरचनात्मक बदलाव वित्तीय आस्तियों के पक्ष में होता है, जो अंशतः अपेक्षाकृत सस्ते आवास तथा निजी पेंशन योजनाओं पर व्यापक निर्भरता द्वारा सुसाध्य होता है। वित्तीय आस्तियों के भीतर, अधिकांशतः बैंक जमाराशियों के रूप में रखी गई तरल आस्तियों को बैंकिंग में सार्वजनिक विश्वास के लंबे इतिहासवाले देशों में अधिक पसंद किया जाता है, जो एक सीमा तक भूसंपदा एवं पूंजी बाजारों में विश्वास की कमी द्वारा भी प्रभावित होता है (डेविस आदि, 2007)।

III. भारत में बैंकों द्वारा जमा संग्रहण

4.13 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण की पहली घटना से, वित्तीय मध्यस्थ, विशेषतर बैंक, भारत में वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया के मूल में हैं। उन्होंने घरेलू क्षेत्र की बचतों का एक बड़ा हिस्सा जुटाया है तथा उन्हें घाटे के क्षेत्रों अर्थात् निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाया है, इस प्रकार वृद्धि की प्रक्रिया का समर्थन किया गया है। इस खंड में निजी प्रवाह संबंधी आंकड़ों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों

प्रदर्श IV.1: घरेलू बचतों को प्रभावित करनेवाले कारक



स्रोत: तुलाधर, ए.(2007)

के नियमित आंकड़ों का उपयोग कर बैंक जमाराशियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि निजी प्रवाह संबंधी आंकड़े काफी समय पुराने (अर्थात् नवीनतम आंकड़े 2000-01 की अवधि के लिए उपलब्ध हैं) हैं, वे बैंकिंग क्षेत्र बनाम अन्य क्षेत्रों की सापेक्ष स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी दे सकते हैं।

निजी प्रवाह

4.14 अधिशेष इकाइयों से घाटे की इकाइयों में संसाधनों का प्रेषण भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी प्रवाह खातों में छः क्षेत्रों अर्थात् घरेलू, कंपनी, सरकार, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं (ओएफआइ) तथा शेष विश्व क्षेत्र में दिखाई दिया। घरेलू क्षेत्र, जो हमेशा अधिशेष क्षेत्र रहा है, ने सार्वजनिक एवं निजी कंपनी क्षेत्रों के घाटे काफी सीमा तक, तथा शेष विश्व क्षेत्र के घाटे एक सीमित मात्रा में पूरे किए। घाटे के क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए निधियां या तो प्रत्यक्षतः (प्राथमिक निर्गम) अथवा बैंक एवं ओएफआइ जैसे वित्तीय मध्यस्थों (द्वितीयक निर्गम) के जरिए प्रदान की गईं। दावों के क्षेत्रीय वितरण की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि द्वितीयक निर्गमों का हिस्सा 1970-71 के 39.7 प्रतिशत से सामान्यतः बढ़कर 1990-00 में 47.1 प्रतिशत हो गया तथा प्राथमिक निर्गमों के हिस्से में तदनुरूप गिरावट आई। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में निधि प्रवाह प्रक्रिया में वित्तीय मध्यस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी (सारणी 4.1)। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निधि प्रवाह संबंधी आंकड़े, जिनके लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और साधनों में वित्तीय लेनदेन संबंधी व्यापक जानकारी की उपलब्धता अपेक्षित है, काफी देरी से जारी किए जाते हैं। इस खंड में 2000-01 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसे सितंबर 2007 के रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था।

4.15 विभिन्न क्षेत्रों द्वारा वित्तीय दावों का सापेक्षिक महत्व साल-दर-साल घटबढ़ दर्शाता है। वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में बैंकिंग प्रणाली की प्रमुखता है। कुल दावों में सभी वित्तीय संस्थाओं के दावों का हिस्सा 36.3 प्रतिशत और 47.1 प्रतिशत के दायरे में था; 1994-95 से 2000-01 तक की अवधि के दौरान इसका औसत 42.2 प्रतिशत था। बैंकिंग क्षेत्र के जरिए वित्तीय प्रवाह 1994-95 के 1,16,217 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000-01 में 1,88,495 करोड़ रुपए हो गया तथा वित्तीय मध्यस्थ क्षेत्र के माध्यम से हुए कुल प्रवाहों में बैंकों के माध्यम से हुए वित्तीय प्रवाहों का हिस्सा कुल मिलाकर 1994-95 के लगभग 62 प्रतिशत से बढ़कर 2000-01 में लगभग 64 प्रतिशत हो गया। कुल दावों में बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा 28.3 प्रतिशत से घटकर 24.2 प्रतिशत हो गया, जबकि ओएफआइ का हिस्सा 17.2 प्रतिशत से घटकर इस अवधि के दौरान 13.6 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.2)। सरकार तथा एक सीमा तक निजी कंपनी क्षेत्र की अगुवाई में गैर वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा इस अवधि में बढ़ गया।

सारणी 4.1 : प्राथमिक और द्वितीयक निर्गम

(करोड़ रुपए)

वर्ष	द्वितीयक निर्गम	प्राथमिक निर्गम	जिसमें से		कुल निर्गम
			देशी प्राथमिक निर्गम	शेष विश्व के निर्गम	
1	2	3=4+5	4	5	6
1970-71	2,336 (39.7)	3,541 (60.3)	3,479 (59.2)	62 (1.1)	5,877 (100.0)
1975-76	6,733 (42.8)	8,999 (57.2)	8,125 (51.6)	874 (5.6)	15,732 (100.0)
1980-81	14,731 (40.7)	21,452 (59.3)	21,408 (59.2)	44 (0.1)	36,183 (100.0)
1985-86	30,558 (42.1)	42,006 (57.9)	43,698 (60.2)	-1,692 (-2.3)	72,564 (100.0)
1990-91	71,016 (42.4)	96,508 (57.6)	1,03,558 (61.8)	-7,050 (-4.2)	1,67,524 (100.0)
1991-92	1,06,386 (44.6)	1,31,916 (55.4)	1,24,664 (52.3)	7,252 (3.0)	2,38,302 (100.0)
1992-93	95,790 (45.7)	1,13,990 (54.3)	1,17,511 (56.0)	-3,521 (-1.7)	2,09,780 (100.0)
1993-94	1,42,897 (47.3)	1,59,200 (52.7)	1,40,079 (46.4)	19,121 (6.3)	3,02,097 (100.0)
1994-95	1,86,675 (45.5)	2,23,512 (54.5)	2,08,448 (50.8)	15,064 (3.7)	4,10,187 (100.0)
1995-96	1,40,337 (36.3)	2,46,614 (63.7)	2,39,849 (62.0)	6,765 (1.7)	3,86,951 (100.0)
1996-97	1,85,638 (45.5)	2,22,351 (54.5)	193,502 (47.4)	28,849 (7.1)	407,989 (100.0)
1997-98	2,40,884 (40.0)	3,62,009 (60.0)	3,42,359 (56.8)	19,650 (3.3)	6,02,893 (100.0)
1998-99	2,77,498 (43.1)	3,67,061 (56.9)	3,50,075 (54.3)	16,986 (2.6)	6,44,559 (100.0)
1999-00	2,73,759 (47.1)	3,07,956 (52.9)	2,93,354 (50.4)	14,602 (2.5)	5,81,715 (100.0)
2000-01	2,94,765 (37.8)	4,84,461 (62.2)	4,34,573 (55.8)	49,888 (6.4)	7,79,226 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल दावों में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खाते, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, सितंबर 2007।

4.16 बैंकों के लिए निधियों के विभिन्न स्रोतों, जैसाकि भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खातों में दिखाई देता है, में काफी घटबढ़ दिखायी दिया। तथापि, इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि जमाराशियां बैंकों के लिए निधियों का सबसे बड़ा स्रोत बनी रहीं। वाणिज्य बैंकों के लिए कुल स्रोतों में जमाराशियों का हिस्सा 1994-95 के 85 प्रतिशत से निरंतर बढ़कर 2000-01 में लगभग 97 प्रतिशत हो गया। 1994-95 तथा 2000-01 के बीच प्रदत्त पूंजी तथा उधार के हिस्से में तेजी से गिरावट हुई (सारणी 4.3)। जहां जमाराशियां प्राथमिक तौर पर घरेलू क्षेत्र से जुटायी गयीं, बैंक जमाराशियों में कंपनी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया। वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा 1994-95 से 2000-01 की अवधि में लगभग 70 प्रतिशत बना रहा, जबकि निजी कंपनी क्षेत्र का हिस्सा 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया। शेष विश्व का हिस्सा 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, वाणिज्य बैंकों की

संसाधन संग्रहण का प्रबंधन

सारणी 4.2 : क्षेत्रों द्वारा वित्तीय प्रवाह

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंकिंग	1,16,217 (28.3)	73,495 (19.0)	87,585 (21.5)	1,40,616 (23.3)	1,77,055 (27.5)	1,54,433 (26.5)	1,88,495 (24.2)
2. अन्य वित्तीय संस्थाएं	70,458 (17.2)	66,842 (17.3)	98,054 (24.0)	1,00,268 (16.6)	1,00,443 (15.6)	1,19,327 (20.5)	1,06,270 (13.6)
3. सभी वित्तीय संस्थाएं (1 + 2)	1,86,675 (45.5)	1,40,337 (36.3)	1,85,638 (45.5)	2,40,884 (40.0)	2,77,498 (43.1)	2,73,759 (47.1)	2,94,765 (37.8)
4. निजी कंपनी कारोबार	1,11,876 (27.3)	1,36,244 (35.2)	91,633 (22.5)	1,06,850 (17.7)	1,32,745 (20.6)	79,674 (13.7)	1,82,126 (23.4)
5. सरकार	71,801 (17.5)	84,985 (22.0)	83,675 (20.5)	2,10,145 (34.9)	1,89,962 (29.5)	1,77,612 (30.5)	2,20,669 (28.3)
6. शेष विश्व	15,064 (3.7)	6,765 (1.7)	28,849 (7.1)	19,650 (3.3)	16,986 (2.6)	14,602 (2.5)	49,888 (6.4)
7. घरेलू	24,771 (6.0)	18,620 (4.8)	18,194 (4.5)	25,365 (4.2)	27,367 (4.2)	36,067 (6.2)	31,778 (4.1)
8. सभी गैर-वित्तीय संस्थाएं (4 से 7)	2,23,512 (54.5)	2,46,614 (63.7)	2,22,351 (54.5)	3,62,009 (60.0)	3,67,061 (56.9)	3,07,956 (52.9)	4,84,461 (62.2)
9. कुल निर्गमित दावे (3+8)	4,10,187 (100.0)	3,86,951 (100.0)	4,07,990 (100.0)	6,02,893 (100.0)	6,44,558 (100.0)	5,81,715 (100.0)	7,79,225 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल दावों में हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खाते, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, सितंबर 2007।

जमाराशियों में वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 6.9 प्रतिशत से घटकर 2.7 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र से बैंक जमाराशियों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय प्राधिकारियों

तथा सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा धारित जमाराशियां शामिल हैं। बैंकों के पास स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा रखी गयी जमाराशियों में वृद्धि एक उल्लेखनीय विशेषता थी। वाणिज्य बैंकों

सारणी 4.3 : वाणिज्य बैंकों के लिए निधि प्रवाह खाते

(करोड़ रुपए)

स्रोत	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8
1 प्रदत्त पूंजी	5,195 (6.1)	708 (1.3)	-777 (-1.2)	3,530 (3.4)	-568 (-0.5)	611 (0.5)	1,133 (0.9)
2 जमाराशियां	72,651 (85.0)	46,859 (84.4)	49,347 (73.7)	98,187 (94.3)	1,03,181 (94.1)	1,03,816 (91.1)	1,15,441 (96.6)
क) सहकारी बैंक	2,331	-131	5,109	2,831	2,156	2,445	2,253
ख) अन्य वित्तीय संस्थाएं	5,024	85	4,166	134	260	3,499	3,079
ग) निजी कंपनी कारोबार	416	-222	4,594	4,469	4,595	5,040	4,387
घ) सरकार	7,433	4,715	4,906	16,258	11,494	12,925	11,771
जिसमें से : केंद्र तथा राज्य सरकार	2,897	3,898	-544	5,122	3,552	3,969	3,579
स्थानीय प्राधिकारण	2,533	1,855	2,755	7,337	4,809	5,447	5,018
वाणिज्यिक उपक्रम	2,003	-1,038	2,695	3,799	3,133	3,509	3,174
ड) शेष विश्व	6,047	9,694	-10,137	9,570	14,876	7,076	13,071
च) देशी	51,400	32,718	40,709	64,925	69,800	72,831	80,880
3 उधार	7,249 (8.5)	9,893 (17.8)	10,773 (16.1)	-7,159 (-6.9)	4,697 (4.3)	8,553 (7.5)	854 (0.7)
क) बैंकिंग	5,839	6,956	3,509	-6,681	4,048	4,457	-313
i) भारतीय रिजर्व बैंक	5,785	6,979	3,150	-6,435	3,755	4,228	-36
ii) सहकारी संस्थाएं	54	-23	359	-246	293	229	-277
ख) अन्य वित्तीय संस्थाएं	790	3,107	2,637	220	1,938	3,738	957
ग) शेष विश्व	620	-170	4,627	-698	-1,289	358	210
4 देय बिल	1,712 (2.0)	-1,713 (-3.1)	5,566 (8.3)	4,177 (4.0)	7,201 (6.6)	19 (0.0)	3,572 (3.0)
5 अन्य	-1,372 (-1.6)	-235 (-0.4)	2,010 (3.1)	5,427 (5.2)	-4,889 (-4.5)	965 (0.8)	-1,444 (-1.2)
कुल	85,435 (100.0)	55,512 (100.0)	66,919 (100.0)	1,04,162 (100.0)	1,09,622 (100.0)	1,13,964 (100.0)	1,19,556 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े वाणिज्य बैंकों के कुल निधि स्रोतों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खाते, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, सितंबर 2007।

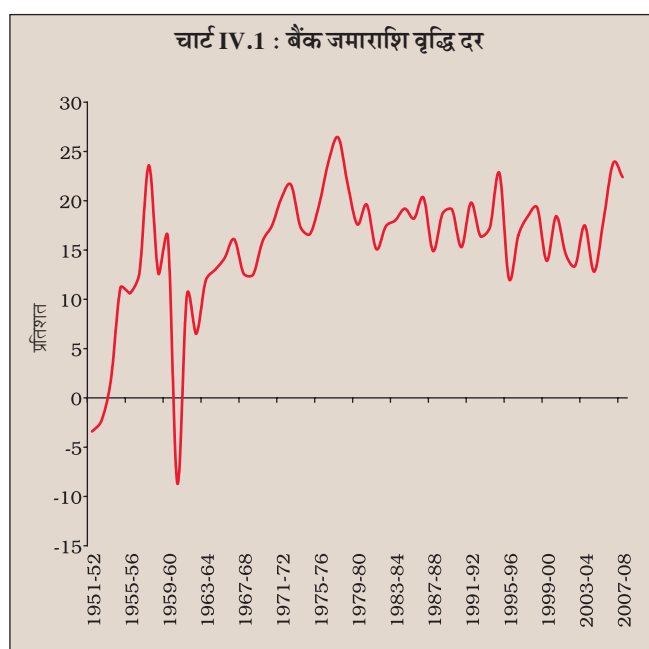
के लिए निधियों के स्रोत के रूप में उधार रिजर्व बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा शेष विश्व क्षेत्र से ली गयी उधार राशियों द्वारा चालित थे। रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त सुविधाओं का युक्तियुक्तकरण, जिसके द्वारा निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा को छोड़कर अन्य पुनर्वित्त सुविधाओं को हटा लिया गया था, के कारण बैंकों ने रिजर्व बैंक से उधार का आश्रय कम लिया। 2000-01 में वित्तीय संस्थाएं बैंकों के लिए उधार के रूप में निधियों का मुख्य स्रोत थीं, जिसके बाद शेष विश्व क्षेत्र का स्थान था।

बैंक जमाराशियां

4.17 जमाराशियों के रूप में बचतों का संग्रहण कर बैंकिंग क्षेत्र ने वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समस्त जमाराशियों में वार्षिक वृद्धि, जो 1951-52 से 1960-61 की अवधि के दौरान अत्यधिक अस्थिर थी, उसके बाद स्थिर हो गयी (चार्ट IV.1)।

4.18 बैंकिंग क्षेत्र के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की एक प्रमुख घटना है - जुलाई 1969 में निजी क्षेत्र के 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक जमाराशि वृद्धि को मोटे तौर पर चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् चरण I (1969-1984); चरण II (1984-1995); चरण III (1995-2005); तथा चरण IV (2005-08) (सारणी 4.4)।

4.19 पहले चरण में, एससीबी की समस्त जमाराशि वृद्धि राष्ट्रीयकरण के पहले के चरण (1951-1969) के 9.5 प्रतिशत की तुलना में 1969-1984 के दौरान 19.2 प्रतिशत के औसत पर काफी



सारणी 4.4 : बैंक जमाराशियों में वृद्धि (वार्षिक औसत)

(प्रतिशत)

अवधि का औसत	मांग	आवधिक	सकल
1	2	3	4
1951-52 से 1968-69	7.1	13.1	9.5
1969-70 से 1983-84	13.3	22.7	19.2
1984-85 से 1994-95	19.5	18.2	18.4
1995-96 से 2004-05	12.6	16.4	15.7
2005-06 से 2007-08	22.5	21.3	21.4

स्रोत : हैडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी।

तेज थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद 1970-71 में एक वर्ष में घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचतों (वित्तीय देयताओं को घटाकर) में 49.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई। फलस्वरूप, घरेलू क्षेत्र की भौतिक बचतों में 1970-71 में 8.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। 1969 में निजी क्षेत्र के 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद विशेषतः ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए व्यापक शाखा विस्तार का भी बैंकों की जमाराशि वृद्धि पर उल्लेखनीय सकारात्मक असर पड़ा। 1980 में निजी क्षेत्र के छह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे दौर में शाखा नेटवर्क का और विस्तार हुआ तथा इससे जमाराशि की वृद्धि तेज करने में मदद मिली। ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों की संख्या 1969 के क्रमशः 1,443 तथा 3,337 से बढ़कर 1985 में क्रमशः 30,185 तथा 9,816 हो गयी। व्यापक शाखा विस्तार के फलस्वरूप शाखा प्रणाली का विस्तार बढ़ गया जैसाकि प्रति कार्यालय जनसंख्या में दिखायी देता है, जो 1969 के 65,000 से घटकर 1985 में लगभग 14,000 हो गयी तथा उसके बाद मोटे तौर पर स्थिर बनी रही (सारणी 4.5)।

सारणी 4.5 : भारत में स्थित बैंक कार्यालयों की संख्या

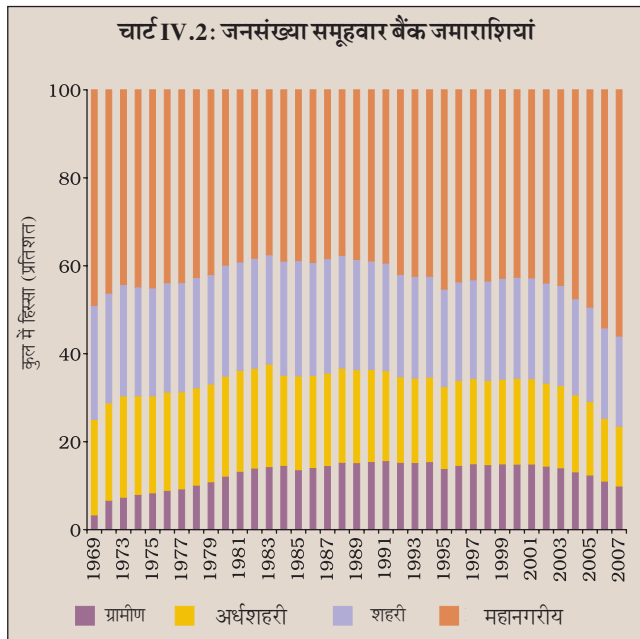
मार्च	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	प्रति कार्यालय जनसंख्या (हजार में)
1	2	3	4	5	6	7
1969	1,443	3,337	1,911	1,496	8,187	65
1970	4,817	4,401	2,504	1,900	13,622	41
1975	6,807	5,598	3,489	2,836	18,730	32
1980	15,105	8,122	5,178	4,014	32,419	20
1985	30,185	9,816	6,578	4,806	51,385	14
1990	34,791	11,324	8,042	5,595	59,752	14
1995	33,004	13,341	8,868	7,154	62,367	15
2000	32,734	14,407	10,052	8,219	65,412	15
2005	32,082	15,403	11,500	9,370	68,355	16
2007	30,551	16,361	12,970	11,957	71,839	15

टिप्पणी : 1969 के आंकड़े जून अंत से संबंधित हैं।

स्रोत : 1. भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, भारतीय रिजर्व बैंक।
2. वर्ष 1969 के आंकड़ों के लिए बैंकिंग सांख्यिकी, 1972।

4.20 फलस्वरूप, कुल जमाराशियों में ग्रामीण जमाराशियों का हिस्सा 1969 के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 1984 तक 14.4 प्रतिशत हो गया जो 1969-1984 की अवधि के दौरान समग्र जमा वृद्धि का विस्तार करने के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेवार था। इसी तरह, 1980 के दशक के मध्य तक अर्धशहरी और शहरी जमाराशियों का हिस्सा भी कुछ बढ़ गया। दूसरी ओर, कुल जमाराशियों में महानगरी जमाराशियों का हिस्सा 49 प्रतिशत से तेजी से गिरकर उसी अवधि में लगभग 39 प्रतिशत रह गया (चार्ट IV.2)।

4.21 बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ने से बैंकिंग के प्रवेश को सुधारने में मदद मिली। अखिल भारतीय स्तर पर, प्रति सौ व्यक्तियों पर एससीबी के पास बचत और चालू जमा खातों की संख्या 1973 के 5.8 से बढ़कर 1981 में 15.3 तथा और बढ़कर 1991 में 31.8 प्रतिशत हो गयी। यह 2001 में घटकर 28.9 रह गयी तथा पुनः बढ़कर 2007 में 34.9 हो गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में एससीबी के पास प्रति सौ व्यक्ति बचत और चालू जमा खातों की संख्या 1973 के 3.3 से बढ़कर 1981 में 11.4 तथा और बढ़कर 1991 में 25.5 हो गयी। यह घटकर 2001 में 23.8 रह गयी तथा सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन पर दिए गए बल के अनुरूप पुनः बढ़कर 2007 में 27.8 हो गयी। बैंकों के कुल बचत तथा चालू जमा खातों में ग्रामीण क्षेत्रों में जमाराशियों का हिस्सा, जिसमें 1991 तक वृद्धि हुई थी, हाल के वर्षों में कम रह गया (सारणी 4.6)। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि एससीबी के अलावा, जमाराशि की सुविधाएं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसएस), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा डाक घरों द्वारा भी प्रदान की जाती हैं, अतः भारत में वित्तीय सेवाओं के प्रवेश का मूल्यांकन करते समय इन्हें भी हिसाब में लिए जाने की जरूरत है (ब्यौरों के लिए अध्याय VII देखें)।



सारणी 4.6 : अनुसूचित-वाणिज्य बैंकों के जमा खातों का जनसंख्या समूह-वार वितरण

मार्चांत	कुल खातों में हिस्सा (प्रतिशत)		प्रति 100 व्यक्तियों के लिए खातों की संख्या		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6
बचत तथा चालू जमा खाता					
1973	45.1	54.9	3.3	16.0	5.8
1981	57.1	42.9	11.4	28.1	15.3
1991	59.5	40.5	25.5	50.0	31.8
2001	59.3	40.7	23.8	42.3	28.9
2007	56.0	44.0	27.8	51.4	34.9

टिप्पणी : 1. 1973 तथा 1980 के बैंक जमाराशियों के आंकड़े दिसंबर से संबंधित हैं।

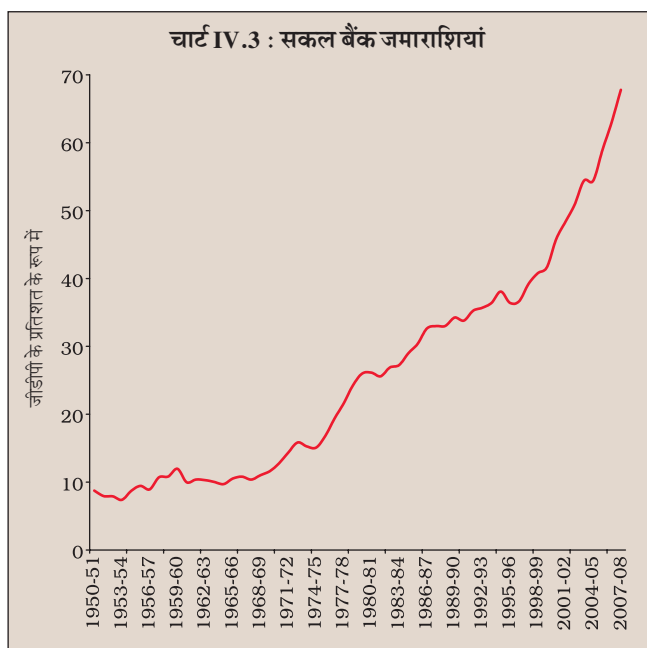
2. जनगणना के जनसंख्या समूह हैं 'ग्रामीण' और 'शहरी' जबकि बीएसआर आंकड़ों में दर्शाए गए जनसंख्या समूह हैं 'ग्रामीण', 'अर्ध-शहरी', 'शहरी' तथा 'महानगरीय'। अतः तुलना एवं सरलीकरण के लिए 'ग्रामीण' तथा 'अर्ध-शहरी' को 'ग्रामीण' के रूप में तथा 'शहरी' व 'महानगरीय' को जोड़कर 'शहरी' के रूप में दर्शाया गया है।

3. वर्ष 1973 के लिए प्रति 100 व्यक्तियों के बैंक खातों की संख्या की गणना के लिए, 1971 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया है; जबकि वर्ष 2007 के लिए ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को 2007 की शहरी जनसंख्या का अनुमान लगाते हेतु 2001 की जनगणना की चक्रवृद्धि दर लगाकर एवं उसे रजिस्ट्रार जनरल एवं सेन्सस कमिश्नर, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध जनसंख्या के कुल अनुमानित आंकड़ों से घटाकर निकाला गया है।

स्रोत : भारत के अनु. वाणिज्य बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, तथा रजिस्ट्रार जनरल व सेन्सस कमिश्नर, भारत सरकार की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां।

4.22 1962 में (बैंकों की विफलता की पृष्ठभूमि में) निक्षेप बीमा निगम की स्थापना, जिसने बैंक जमाकर्ताओं विशेषतः छोटे खातेदारों को संरक्षण प्रदान किया, द्वारा भी बैंकिंग की आदत की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाया गया। इसने बैंकिंग प्रणाली में बचतकर्ताओं के विश्वास को बहाल किया जैसाकि जीडीपी के प्रति समस्त बैंक जमाराशियों के अनुपात में दिखायी देता है, जो 1950 तथा 1960 के दशक के दौरान 9-10 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1970 के दशक के दौरान औसतन 18 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.3)।

4.23 घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचतों में बैंक जमाराशियों का हिस्सा भी 1970-71 के 35.7 प्रतिशत से बढ़कर 1983-84 में 42.5 प्रतिशत हो गया जो बैंक शाखा विस्तार के प्रभाव को दर्शाता है (सारणी 4.7)। बैंक जमाराशियों का हिस्सा मुख्यतः घरेलू क्षेत्र द्वारा पूंजी बाजार के लिखतों को तरजीह दिए जाने के कारण वित्तीय प्रणाली में विमध्यस्थता की वजह से 1994-95 तक घटकर 38.4 प्रतिशत रह गया। अल्पबचत योजनाओं पर सरकार की नीति में बल दिए जाने के कारण बैंक जमाराशियों का हिस्सा और गिरकर 2004-05 तक 36.4 प्रतिशत रह गया। तथापि, इस प्रवृत्ति में बदलाव आया और 2006-07 में बैंक जमाराशियों का हिस्सा बढ़कर 55.6 प्रतिशत हो गया, जो बैंकों द्वारा आक्रामक जमा संग्रहण को दर्शाता है, जिसे अंशतः विशेष जमायोजनाओं के लिए कर लाभों के विस्तार द्वारा सुसाध्य बनाया गया



जिसके ब्यौरे अगले खण्डों में दिए गए हैं। आवधिक जमाराशियों पर उच्चतर ब्याज दरों तथा अल्पबचतों पर अपरिवर्तित ब्याज दरों ने भी अल्पबचतों से निधियों का कुछ हिस्सा हटाकर बैंक जमाराशियों में रखे जाने में अंशदान किया।

4.24 बचत जमाराशियों के उपचार में परिभाषात्मक परिवर्तनों के कारण 1977-78 में बैंक जमाराशियों के घटकों में एक प्रमुख संरचनागत बदलाव आया। 1977-78 में, मांग जमाराशियों का हिस्सा तेजी से घट

गया, जो प्राथमिक तौर पर मार्च 1978 में बचत जमाराशियों के दो घटकों - मांग तथा मीयादी - में विभाजन के उपचार में परिवर्तन के कारण आवधिक जमाराशियों के प्रति घुमाव को दर्शाता है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, एससीबी से यह अपेक्षा की गयी कि वे ब्याज भुगतान के लिए पात्र बचत खातों में रखे गये मासिक न्यूनतम शेष के औसत को 'आवधिक' देयता के रूप में मानें, जबकि शेष भाग को बचत खाते की 'मांग' देयता के रूप में माना जाना था। इसके अलावा बैंकों को अनुदेश दिया गया कि वे जून के अंत तथा दिसंबर के अंत में साल में दो बार 'मांग' तथा 'आवधिक' देयताओं के बीच के अनुपातों की गणना करें। साथ ही 1978 में कोरे समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, नकद ऋण पर बैंकों की निर्भरता में काफी कमी आयी क्योंकि कंपनियों से अपेक्षा की गयी कि वे अपनी चालू आस्तियों के कम से कम 25 प्रतिशत का अंशदान अपनी निजी निधियों तथा दीर्घावधि संसाधनों से करें। जिस सीमा तक कंपनियों ने बैंक जमाराशियों पर अपनी निर्भरता कम की, इसके फलस्वरूप चालू जमाराशियों में गिरावट आयी (चार्ट IV.4)।

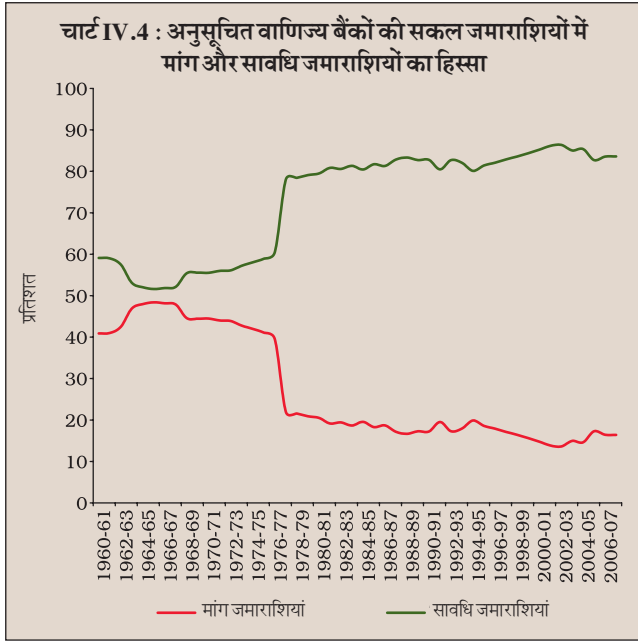
4.25 बैंक जमाराशियों के संरचनागत विश्लेषण से भी यह प्रकट होता है कि मीयादी जमाराशियों का हिस्सा, जो मार्च 1980 के अंत में 55.7 प्रतिशत था, घटकर 1981-82 में लगभग 51 प्रतिशत रह गया जो उस वर्ष के दौरान लागू किए गए नए 12 प्रतिशत वाले 6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (एनएससी) की ओर घुमाव को दर्शाता है। कंपनी क्षेत्र द्वारा शेयरों तथा डिबेंचरों, विशेष तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों, के निर्गम में भी भारी वृद्धि हुई।

4.26 दूसरे चरण (1984-1995) में, समस्त जमावृद्धि थोड़ी कम होकर 18.4 प्रतिशत रह गयी। इस चरण में मांग जमाराशियों की वृद्धि

सारणी 4.7 : घरेलू क्षेत्र की वित्तीय आस्तियां एवं देयताएं : वितरण का स्वरूप

मद	1970-71 1983-84 1994-95 2004-05 2006-07					(प्रतिशत)			
	1970-71 से 1983-84 (औसत)	1984-85 से 1994-95 (औसत)	1995-96 से 2004-05 (औसत)	2005-06 से 2006-07 (औसत)	7	8	9	10	
मुद्रा	16.8	14.8	10.9	8.5	8.6	13.4	11.3	9.3	8.7
बैंक जमाराशियां	35.7	42.5	38.4	36.4	55.6	44.6	36.5	36.9	50.9
गैर बैंकिंग जमाराशियां	3.2	5.4	7.9	0.8	0.1	3.6	5.2	4.6	0.6
जीवन बीमा निधि	9.8	7.3	7.8	15.7	15.0	8.6	8.2	12.9	14.5
भविष्य एवं पेन्शन निधि	23.2	16.2	14.7	13.0	9.2	19.0	17.5	17.7	9.9
सरकार पर दावे	5.0	10.5	9.1	24.5	5.2	5.7	10.4	15.2	9.9
शेयर व डिबेंचर (म्यूचुअल फंडों के यूनिट सहित)	3.9	4.1	11.9	1.1	6.3	2.6	11.3	3.8	5.6
व्यापार ऋण (निवल)	2.4	-0.9	-0.8	0.0	0.0	2.6	-0.5	-0.5	0.0
वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन (कुल)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
बैंक अग्रिम	86.1	85.3	87.3	92.6	96.8	82.9	82.2	83.4	96.6
अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण व अग्रिम	6.4	8.8	9.7	6.9	3.2	8.0	11.3	13.7	3.4
सरकार से ऋण व अग्रिम	11.7	3.9	1.7	0.2	-0.1	7.1	4.6	1.9	-0.1
सहकारी गैर ऋण सोसाइटियों से ऋण व अग्रिम	-4.2	2.0	1.3	0.3	0.1	2.0	2.0	1.0	0.1
वित्तीय देयताओं में परिवर्तन (कुल)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: हैडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07।



में तेजी आयी, जबकि आवधिक जमाराशियों में कमी आयी जिसके फलस्वरूप समस्त जमाराशि विस्तार में समग्र कमी हुई। आवधिक जमाराशि वृद्धि में हुई कमी निम्नलिखित का परिणाम थी (क) शाखा नेटवर्क के विस्तार में कमी, तथा (ख) बैंकों में रखी आवधिक जमाराशियों को अन्य बचत लिखतों द्वारा प्रतिस्थापित करना। एससीबी के कार्यालयों की संख्या, जिसमें 1969 तथा 1980 के बीच लगभग चार गुनी वृद्धि हुई, 1980 तथा 1995 के बीच दुगुने से भी कम बढ़ी। दूसरे, बैंक जमाराशियों को अन्य लिखतों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। म्यूच्युअल फंडों के यूनितों, शेयरों तथा डिबेंचरों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की जमाराशियों तथा अल्पबचतों में तेजी से वृद्धि हुई, जो घरेलू वित्तीय बचतों में उनके हिस्सों में हुई वृद्धि में दिखाई देता है (देखें सारणी 4.7)।

4.27 1980 के दशक के उत्तरार्ध में तथा कुछ सीमा तक 1990 के दशक के आरंभ में आय कर अधिनियम की धारा 18ए के तहत कर लाभ की उपलब्धता द्वारा विशेषकर म्यूच्युअल फंडों के यूनितों के पक्ष में निधियों के प्रतिस्थापन को सुकर बनाया गया। इस धारा के तहत, कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर से उस सीमा तक मुक्त रखा गया, जहां तक उनके द्वारा अदा किया गया लाभांश प्राप्त लाभांश से अधिक हो। फलस्वरूप कंपनियों ने भूतपूर्व भारतीय यूनित ट्रस्ट (यूटीआइ) के तत्कालीन यूनित स्कीम-64 (यूपएस-64) में बड़े पैमाने पर निधियों का निवेश किया। कंपनियों के अलावा, व्यक्तिगत निवेशक भी म्यूच्युअल फंडों के यूनितों की ओर आकृष्ट हो गये। यूटीआइ के अलावा, 1987-88 तथा 1995-96 के बीच 21 नए म्यूच्युअल फंडों की स्थापना की

गयी तथा उन्होंने लगभग 128 स्कीमें आरंभ कीं। नए स्थापित म्यूच्युअल फंडों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, यूटीआइ ने भी निवेशकों की आय एवं चलनिधि संबंधी विभिन्न जरूरतें पूरी करने के लिए विशेषतः 1980 के दशक के उत्तरार्ध में नयी स्कीमें आरंभ करने की आक्रामक नीति अपनायी। 1964 तथा 1992 के बीच आरंभ की गयी 41 स्कीमों में से, यूटीआइ ने 26 स्कीमें 1987 तथा 1992 के बीच आरंभ कीं। 1987-88 तथा 1991-92 के बीच, म्यूच्युअल फंडों की वित्तीय आस्तियों में 153 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई (राज, 1999)। यद्यपि, वित्तीय आस्तियों की वृद्धि का एक भाग निवेशों की मूल्यवृद्धि का परिणाम हो सकता है, ऐसी आस्तियों का बड़ा भाग निधियों के नये संग्रहण से प्राप्त हुआ था। इस चरण में पूंजी बाजार में भी (1970 के दशक में हुई मंदी की स्थिति की तुलना में) उछाल की स्थिति थी। फलस्वरूप, म्यूच्युअल फंडों के यूनितों तथा शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश से बैंक जमाराशियों की ब्याज दरों की तुलना में उच्चतर प्रतिलाभ मिला। इसने घरेलू वित्तीय बचतों को बैंक जमाओं से हटाकर शेयरों तथा डिबेंचरों और म्यूच्युअल फंडों की यूनितों में निवेश करने को प्रोत्साहित किया। इस चरण में एनबीएफसी द्वारा जमा संग्रहण में भी तेज वृद्धि हुई। एनबीएफसी की संख्या, जिसमें 1970 तथा 1980 के बीच दुगुनी वृद्धि हुई थी, 1980 तथा 1994 के बीच लगभग 8 गुनी बढ़ी। एनबीएफसी द्वारा बड़े पैमाने पर जमा संग्रहण का अंदाजा उनकी वित्तीय आस्तियों से लगाया जा सकता है, जिसमें 1990-94 के दौरान 44.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। अल्प बचतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई जैसाकि घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में सरकार पर दारों के हिस्से में हुई वृद्धि में दिखाई देता है। इस चरण के दौरान, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में बैंक जमाराशियों का हिस्सा तेजी से गिर गया (देखें सारणी 4.7)। भारत के लिए किए गए एक आनुभविक अध्ययन में भी यह पाया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आवधिक/मीयादी जमाराशियों को म्यूच्युअल फंडों की इकाइयों, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी), एलआइसी की जीवन बीमा पालिसियों तथा अल्पबचतों के पक्ष में प्रतिस्थापित किया गया (राज, उद्धरण देखें)।

4.28 बैंक जमा वृद्धि में तीसरे चरण (1995-2005) में और गिरावट होनी जारी रही तथा औसत समस्त जमा में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि आय के स्तर में और वृद्धि हुई जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि में सुधार के प्रभाव को दर्शाता है। तथापि, इस चरण में, गिरावट काफी सीमा तक मांग जमाराशियों में गिरावट का तथा कुछ सीमा तक मीयादी जमाराशियों में गिरावट का परिणाम थी। देशी मीयादी जमाराशियों की निर्धारित न्यूनतम परिपक्वताओं में क्रमिक कटौती के कारण मांग जमाराशियों की वृद्धि में तेज गिरावट आई। आवधिक जमाराशियों की न्यूनतम परिपक्वताओं को क्रमिक रूप से कम कर जुलाई 1996 में 46

¹ प्रतिस्थापन को संकीर्ण अर्थ में परिभाषित न किया जाए, जिसमें निधियों को एक लिखत से वस्तुतः दूसरे लिखत में अंतरित किया जाता है, अपितु इसे व्यापक अर्थ में परिभाषित किया जाए, जिसमें नई निधियां एक लिखत में निवेश किए जाने के बजाए अन्य लिखत/लिखतों में निवेश की जाती हैं।

दिन से 30 दिन, अप्रैल 1998 में 30 दिन से 15 दिन, तथा अप्रैल 2001 में 15 लाख रुपए तथा अधिक की थोक मीयादी जमाराशियों के लिए और अक्टूबर 2004 में 15 लाख रुपए के कम की खुदरा मीयादी जमाराशियों के लिए 15 दिन से 7 दिन कर दिया गया। इससे निधियों को बचत जमाराशियों (मांग देयता अंश) से हटाकर मीयादी जमाराशियों

में लगाया गया। बैंकों को उनके परिचालनों में लचीलापन प्रदान करने तथा दक्षता सुधारने के लिए, न सिर्फ मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि को कम किया गया, अपितु बैंकों को विशेष परिपक्वताओं के लिए उनकी देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने में क्रमिक रूप से स्वतंत्रता दी गई (बॉक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1

भारत में जमा ब्याज दरों का अविनियमन

देशी जमा ब्याज दरों के अविनियमन की प्रक्रिया उस समय शुरू हुई जब बैंकों को अप्रैल 1985 से 8 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन 15 दिन से एक वर्ष तक के बीच की परिपक्वताओं के लिए ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गई। तथापि, चल रहे कीमत युद्ध को देखते हुए मई 1985 के अंत तक इस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। अविनियमन की प्रक्रिया अप्रैल 1992 में पुनः शुरू की गई तथा परिपक्वतावार निर्धारणों की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर 46 दिन से अधिक की सभी जमाराशियों के लिए 13 प्रतिशत की एकल अधिकतम दर निर्धारित की गई। अधिकतम दर को कम कर नवंबर 1994 में 10 प्रतिशत कर दिया गया, परंतु उसे बढ़ाकर अप्रैल 1995 में 12 प्रतिशत कर दिया गया। बैंकों को अक्टूबर 1995 में दो वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गई जिसे जुलाई 1996 में और शिथिल कर एक वर्ष से अधिक परिपक्वता तक ला दिया गया। '30 दिन से एक वर्ष तक' की जमाराशियों के लिए अधिकतम दर को अप्रैल 1997 में बैंक दर घटाव 200 आधार अंक से संबद्ध कर दिया गया। अक्टूबर 1997 में, बैंक दर से संबद्धता समाप्त कर जमा दरों को पूर्णतः अविनियमित कर दिया गया। फलस्वरूप, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान की कि वे अपने संबंधित निदेशक मंडलों/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के पूर्वानुमोदन से विभिन्न परिपक्वताओं की देशी मीयादी जमाराशियों पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित कर सकते हैं। बैंकों को देशी मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण के लिए अपनी दांडिक ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गई तथा जमाराशि के आकार से निरपेक्ष होकर उसी परिपक्वता की जमाराशि पर समान दर का प्रस्ताव करने संबंधी बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों को इस संबंध में बैंकों के बोर्डों द्वारा निर्धारित की जानेवाली नीति के अनुसार अप्रैल 1998 में 15 लाख और अधिक रुपए की जमाराशियों के संबंध में हटा लिया गया। बैंकों को यथासंभव अप्रैल 2002 में व्यवहार में जमाराशियों पर लचीली ब्याज दर प्रणाली (स्थिर दर के विकल्प सहित) लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब देशी जमा दरों को निर्धारित करने के बारे में बैंकों के पास पूरी आजादी है, बचत जमाराशियों पर ब्याज दर इसका अपवाद है जो विनियमित बनी हुई है तथा वर्तमान में 3.5 प्रतिशत है।

देशी जमा दरों के विनियमन के अनुरूप विभिन्न एनआरई जमा योजनाओं पर ब्याज दरों को भी रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता था। अगस्त 1985 के पहले, प्रचलित एनआरआइ जमा योजना पर ब्याज दर निर्धारित देशी मीयादी जमा दरों की तुलना में 2 प्रतिशत अंक ऊपर निर्धारित की गई। बाद में, अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए एफसीएनआर (ए) पर ब्याज दरों को संशोधित किया गया। तथापि 1990 के दशक के आरंभ में अंतर बढ़ गया जो 1991 के बाह्य भुगतान संकट को देखते हुए इन जमाराशियों को आकृष्ट करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

वित्तीय क्षेत्र सुधार के अंग के रूप में, एनआरई जमाराशियों के लिए विस्तृत परिपक्वतावार निर्धारणों को युक्तियुक्त बनाया गया तथा उसे अक्टूबर 1992 में '13 प्रतिशत से अनधिक' तथा देशी जमाराशियों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अनुरूप अप्रैल 1993 में '12 प्रतिशत से अनधिक' के एकल निर्धारण के अधीन लाया गया। एनआरई तथा देशी जमाराशियों की परिपक्वता संरचना को संरेखित करने की दृष्टि से, दो वर्ष से अधिक की परिपक्वतावाली एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों को अप्रैल 1996 में मुक्त कर दिया गया, जबकि एक साल से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों को अप्रैल 1997 में मुक्त कर दिया गया। 13 सितंबर 1997 से, सभी परिपक्वताओं पर ब्याज दरों का निर्णय लेने के लिए बैंकों को पूरी आजादी दी गई। इसी तरह, एफसीएनआर(बी) योजना के संबंध में, बैंकों को 16 अप्रैल 1997 से प्रभावी निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन ब्याज दरें (छह महीने की ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि सहित स्थिर अथवा चल) निर्धारित करने की अनुमति दी गई। पहले, एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें एफसीएनआर (ए) जमाराशियों के लिए निर्धारित दरों के अनुरूप थीं। न्यूनतम परिपक्वता अवधि को भी अक्टूबर 1999 से छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया तथा 26 जुलाई 2005 से बैंकों को अनुमति दी गई कि वे पहले की तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के बजाए पांच वर्ष की अधिकतम परिपक्वता अवधि तक एफसीएनआर (बी) जमाराशियां स्वीकार कर सकते हैं। एनआर(एनआर)आरडी योजना के मामले में, बैंकों को देशी जमा दरों को मुक्त करने के भी पहले जून 1992 में योजना के आरंभ से ब्याज दरें निर्धारित करने के लचीलेपन की अनुमति दी गई।

तथापि, वित्तीय बाजारों में बदलती स्थितियों के प्रतिस्वाद में, एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों को 17 जुलाई 2003 से संबंधित परिपक्वताओं की यूएस डालर लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 250 आधार अंकों की अधिकतम सीमा के अधीन अंतरराष्ट्रीय दरों के साथ संबद्ध कर दिया गया। अधिकतम दरों को क्रमिक रूप से घटाया गया (15 सितंबर 2003 को लिबोर दरों के ऊपर 100 आधार अंक तथा और घटाकर 18 अक्टूबर 2003 को लिबोर दरों के ऊपर 25 आधार अंक) तथा उसे 17 अप्रैल 2004 को कारोबार की समाप्ति से संबंधित परिपक्वताओं के लिए लिबोर/स्वैप दरों तक नीचे लाया गया। बाद में, अधिकतम दर को पुनः कुछ चरणों में बढ़ाकर 18 अप्रैल 2006 तक लिबोर के ऊपर 100 आधार अंक तक लाया गया तथा 24 अप्रैल 2007 से उसे लिबोर दर पर निर्धारित किया गया। साथ ही, एनआरई बचत जमा दर को देशी बचत जमा दर से असंबद्ध किया गया तथा 17 अप्रैल 2004 से एनआरई बचत जमाराशियों पर अधिकतम दर को 6-माह की यूएस डालर लिबोर/स्वैप दर पर निर्धारित किया गया। तथापि, 17 नवम्बर 2005 को भारत में कारोबार की समाप्ति से, एनआरई बचत जमाओं पर ब्याज दरें देशी बचत जमाराशियों पर लागू दरों के समान थीं।

संसाधन संग्रहण का प्रबंधन

सारणी 4.8 : अल्प बचत वसूली

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल जमाराशियां		कुल प्रमाणपत्र		सार्वजनिक भविष्य निधि		कुल	
	प्राप्तियां	बकाया	प्राप्तियां	बकाया	प्राप्तियां	बकाया	प्राप्तियां	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1970-71	695	1,184	88	92	2	5	785	1,281
1975-76	1,445	3,179	99	455	9	30	1,553	3,664
1980-81	2,758	6,632	302	1,412	59	200	3,119	8,244
1985-86	5,285	11,772	3,187	9,873	122	720	8,594	22,365
1990-91	9,455	17,022	8,214	33,257	347	2,595	18,016	52,874
1995-96	15,920	30,248	16,828	62,452	0	1,028	32,748	93,728
2000-01	44,869	80,654	33,044	1,38,041	1,398	6,392	79,311	2,25,087
2001-02	51,746	1,05,078	28,078	1,49,667	1,929	8,111	81,753	2,62,856
2002-03	70,214	1,40,216	33,051	1,63,421	2,337	10,156	1,05,602	3,13,793
2003-04	94,272	1,88,907	39,170	1,74,563	2,528	12,267	1,35,970	3,75,737
2004-05	1,22,616	2,51,665	33,369	1,91,794	2,534	14,273	1,58,519	4,57,732
2005-06	1,30,447	3,06,968	39,812	2,03,771	3,024	16,872	1,73,283	5,27,611
2006-07अ	1,16,303	3,32,130	34,532	2,12,785	4,065	19,457	1,54,836	5,64,372

अ : अनंतिम

स्रोत : हैडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 ।

4.29 तथापि इस चरण में बैंक जमाराशियों को मुख्यतः डाक कार्यालय जमाराशियों और अल्प बचतों से, जिनमें वसूली चार गुने से अधिक बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा (सारणी 4.8)।

4.30 वित्तीय क्षेत्र सुधार के अंग के रूप में विभिन्न जमा दरों को अविनियमित करने के साथ, सभी परिपक्वताओं की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 1995-96 तथा 2003-04 के बीच 12-13 प्रतिशत से

गिरकर 4.00-5.50 प्रतिशत रह गईं। इस अवधि में अन्य बचत लिखतों पर ब्याज में भी गिरावट आई। तथापि, अन्य लिखतों पर ब्याज दर में हुई गिरावट मीयादी जमाराशियों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से न्यूनतर थी (सारणी 4.9)।

4.31 ब्याज दरों में नरमी तथा मीयादी जमाराशियों के परिपक्वता प्रोफाइल में कमी को दर्शाते हुए, बैंकों द्वारा संविदाकृत मीयादी जमाराशियों

सारणी 4.9 : बैंक जमाराशियों तथा अन्य अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की संरचना

(प्रतिशत)

वर्ष	मीयादी जमाराशियां			पीपीएफ (15 वर्ष की समयबंदी)	एनएससी पोस्ट ऑफिस एमआइएस (4 वर्ष की समयबंदी)	एमएफ कर बचत योजना#	
	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक				
1	2	3	4	5	6	7	8
1970-71	6.00-6.50	7.00	7.25	-	-	-	8.00
1975-76	6.75-8.00	7.75-9.00	8.00-10.00	-	-	-	8.75
1980-81	7.50-8.50	10.00	10.00	-	-	-	11.50
1985-86	8.50-9.00	10.00	11.00	-	-	-	15.25
1990-91	9.00-10.00	11.00	11.00	12.00@	11.00@	14.00@	19.50
1995-96	12.00	13.00*	13.00*	12.00	11.00	13.00	20.00
2000-01	8.50-9.50*	9.50-10.00*	9.50-10.00*	11.00	10.50	11.00	10.00
2001-02	7.50-8.50*	8.00-8.50*	8.00-8.50*	9.50	9.00	9.50	-
2002-03	4.25-6.00*	5.50-6.25*	5.50-6.25*	9.00	8.50	9.00	-
2003-04	4.00-5.25*	5.25-5.50*	5.25-5.50*	8.00	8.50	8.00	-
2004-05	5.25-5.50*	5.75-6.25*	5.75-6.25*	8.00	8.50	8.00	-
2005-06	6.00-6.50*	6.25-7.00*	6.25-7.00*	8.00	8.50	8.00	-
2006-07	7.50-9.00*	7.75-9.00*	7.75-9.00*	8.00	8.50	8.00	-
2007-08	8.25-9.25*^	8.00-9.00*^ +	-	8.00	8.50	8.00	-

एमआइएस : मासिक आय योजना

* : सार्वजनिक क्षेत्र के 5 प्रमुख बैंकों की मार्च के अंत की जमा दर से संबंधित।

@ : 1992-93 से संबंधित।

^ : मार्च 2008. + : 3 वर्ष से अधिक के लिए जमा दर।

: 2000-01 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआइ) के यूनिटों की लाभांश दरें।

- : उपलब्ध नहीं

स्रोत : हैडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 ।

सारणी 4.10 : मीयादी जमाराशियों का ब्याज दर दायरा-वार वितरण

(प्रतिशत)

ब्याज दर दायरा	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 प्रतिशत से कम	4.1	4.6	5.9	6.9	5.0	6.7	17.4	46.3	47.5	34.1	14.3
6 प्रतिशत और अधिक किंतु 8 प्रतिशत से कम	7.1	6.9	7.4	9.9	11.9	18.3	36.3	27.7	38.9	47.1	28.6
8 प्रतिशत और अधिक किंतु 10 प्रतिशत से कम	12.3	11.2	15.1	20.8	26.6	42.4	28.4	17.2	8.9	16.5	38.3
10 प्रतिशत और अधिक	76.5	77.3	71.6	62.4	56.5	32.6	18.1	9.0	4.8	2.4	19.5
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : भारत में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंक की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, भारतीय रिजर्व बैंक।

की ब्याज दरों में स्पष्ट बदलाव दिखाई दिया। एससीबी की कुल जमाराशियों में 10 प्रतिशत तथा अधिक की ब्याज दर पर संविदाकृत जमाराशियों का हिस्सा निरंतर गिरते हुए 1998 के 77.3 प्रतिशत से 2004 में 9.0 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, बैंकों की कुल जमाराशियों में 6 प्रतिशत से कम पर संविदाकृत जमाराशियों का हिस्सा 1997 के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 46.3 प्रतिशत हो गया। 8 प्रतिशत ब्याज दर तक पर संविदाकृत जमाराशियों का हिस्सा 1997 के 11.2 प्रतिशत की तुलना में 2004 में कुल जमाराशियों का 74 प्रतिशत था (सारणी 4.10)।

4.32 अल्प बचत दर सामान्यतः उसी परिपक्वता की आवधिक जमा दरों की तुलना में उच्चतर होती है तथा सरकार अल्प बचतों के लिए कर लाभ प्रदान करती है, इसे देखते हुए ऐसी बचतों पर प्रतिलाभ की वास्तविक दर मीयादी जमाराशियों पर प्रतिलाभ की तुलना में प्रायः उच्चतर होती है। 2003-04 में 5 वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों पर 5.25-5.50 प्रतिशत प्रतिलाभ की वार्षिक दर की तुलना में, 30 प्रतिशत के सीमांत कर ब्रैकेट वाले निवेशकों को एनएससी पर 14.6 प्रतिशत, पीपीएफ पर 12.5 प्रतिशत तथा डाक कार्यालय जमाराशियों पर 8.32-10.03 प्रतिशत की आय हुई (सारणी 4.11)।

सारणी 4.11 : विभिन्न आय कर वर्गों के लिए अल्प बचत लिखतों पर उपलब्ध प्रभावी प्रतिलाभ दर (किसी अधिभार के बिना)

(प्रतिशत)

लिखत	आइटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन छूट	अवधि	सामान्य आयकर दर	02.09.1993 से 14.01.2000 तक	15.01.2000 से 28.02.2001 तक	01.03.2001 से 28.02.2002 तक	01.03.2002 से 28.02.2003 तक	मार्च 2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. एनएससी (आठवां निर्गम)	88, 80एल	6 वर्ष	0	12.36	11.83	9.73	9.20	8.16
			10	20.27	19.56	16.75	14.36	13.04
			20	21.52	20.75	17.72	15.24	13.82
			30	22.77	21.95	18.70	16.12	14.60
2. सार्वजनिक भविष्य निधि	88, 10(12)	15 वर्ष	0	12.00	11.00	9.50	9.00	8.00
			10	15.82	14.72	13.07	11.81	10.72
			20	17.17	15.95	14.13	12.79	11.58
			30	18.52	17.19	15.20	13.77	12.45
3. सार्वजनिक भविष्य निधि (स्वीकार्य आहरण के साथ)	88, 10(12)	15 वर्ष	0	12.00	11.00	9.50	9.00	8.00
			10	17.44	16.92	16.13	14.37	13.90
			20	19.04	18.41	17.45	15.59	14.99
			30	20.62	19.88	18.75	16.78	16.07
4. डाक घर मीयादी जमाराशियां	80एल	1-5 वर्ष	0	10.92-13.09	8.24-10.92	7.71-9.31	7.45-8.78	6.40-7.71
			10	12.01-14.41	9.07-12.01	8.49-10.24	8.19-9.65	7.04-8.49
			20	13.11-15.72	9.89-13.11	9.26-11.17	8.94-10.53	7.68-9.26
			30	14.20-17.03	10.72-14.20	10.03-12.10	9.68-11.41	8.32-10.03
5. राहत / बचत (कर-मुक्त) बांड	10(15)	5 वर्ष	0	10.25	9.20	8.68	8.16	6.61
			10	11.28	10.12	9.55	8.98	7.27
			20	12.30	11.04	10.42	9.79	7.93
			30	13.33	11.96	11.28	10.61	8.59
6. एनएसएस	88	4 वर्ष	0	11.00	10.50	9.00	8.50	7.50
			10	16.35	15.87	14.40	12.20	11.25
			20	15.31	14.87	13.54	11.39	10.52
			30	14.24	13.84	12.65	10.56	9.79

स्रोत : नियंत्रित ब्याज दरों तथा बचत लिखतों को युक्तियुक्त करने के बारे में सलाह देने के लिए बनी सलाहकार समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष : डॉ रakesh मोहन), भारतीय रिजर्व बैंक, 2004।

4.33 तदनुसार, बैंक जमाराशियों की तुलना में अल्प बचत वसूली में हुई वृद्धि उल्लेखनीय रूप से उच्चतर थी। अल्प बचतों की वसूली 2000-01 से 2004-05 के दौरान दुगुनी से अधिक हो गई (चार्ट IV.5)। गिरावट के बावजूद, घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचतों में समग्र बैंक जमाराशियों का हिस्सा मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। सरकार पर किए गए जानेवाले दावों के हिस्से में वृद्धि के अलावा, इस चरण में जीवन बीमा निधि के हिस्से में भी तीव्र वृद्धि हुई। तथापि, सरकारी और जीवन बीमा निधियों पर दावों के हिस्सों में हुई वृद्धि मोटे तौर पर पूंजी बाजार लिखतों के हिस्से में हुई गिरावट से तुलनीय थी (देखें सारणी 4.7)।

4.34 डाक कार्यालयों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, जो मुख्यतः ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों से थी, के फलस्वरूप कुल जमाराशियों में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी जमाराशियों का हिस्सा 1980 के दशक तथा 1990 के दशक के आरंभ की ऊंचाइयों से गिर गया। सहवर्ती तौर पर, बैंकों की कुल जमाराशियों में महानगरीय जमाराशियों का हिस्सा 1990 के दशक के आरंभ से बढ़ गया, जो अंशतः निजी क्षेत्र के नए बैंकों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है जो अधिकांशतः शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं। जमा के प्रकार का अलग-अलग विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि कुल बैंक जमाराशियों में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा, जो 1980 के 12.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1990 के अंत तक 15.3 प्रतिशत हो गया था, मार्च 2004 के अंत तक गिरकर 12.9 प्रतिशत रह गया जो व्यापक तौर पर मीयादी जमाराशियों के हिस्से में गिरावट को दर्शाता है। अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में जमाराशियों के हिस्सों में इसी तरह की प्रवृत्तियां देखी गईं। दूसरी ओर, कुल बैंक जमाराशियों में महानगरीय क्षेत्रों का

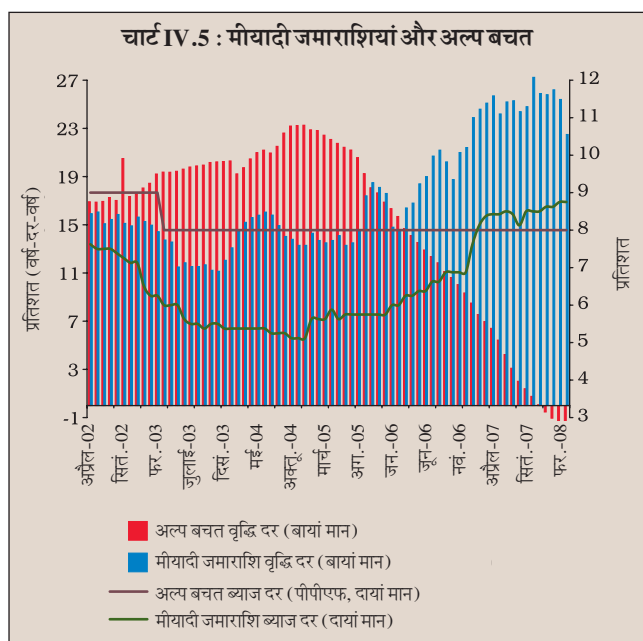
हिस्सा वर्तमान दशक में निरंतर बढ़ता रहा जिसका मुख्य कारण मीयादी जमाराशियों के हिस्से में हुई वृद्धि था। एक और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि शहरी और महानगरीय दोनों क्षेत्रों में कुल जमाराशियों में चालू जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आई (सारणी 4.12)। कुछ सीमा तक कुल ऋण में उद्योग के हिस्से में आई गिरावट इसका कारण थी, जैसाकि अध्याय VI में ब्यौरेवार बताया गया है। चूंकि उद्योग को

सारणी 4.12 : कुल जमाराशियों में जनसंख्या समूहों का हिस्सा

(प्रतिशत)

मार्चांत	चालू	बचत	मीयादी	कुल
1	2	3	4	5
ग्रामीण जमाराशियां				
1980	1.0	5.4	6.1	12.6
1990	0.9	5.9	8.5	15.3
1995	0.8	4.7	8.2	13.7
2000	0.8	4.7	9.2	14.7
2001	0.7	4.7	9.3	14.7
2002	0.7	4.7	8.8	14.2
2003	0.6	4.9	8.3	13.8
2004	0.6	5.0	7.3	12.9
2005	0.6	5.1	6.4	12.2
2006	0.6	4.9	5.3	10.8
2007	0.5	4.5	4.7	9.7
अर्ध-शहरी जमाराशियां				
1980	2.6	7.8	12.7	23.1
1990	2.0	6.9	12.3	21.2
1995	1.7	5.8	11.3	18.8
2000	1.6	5.8	12.3	19.7
2001	1.5	5.8	12.3	19.6
2002	1.4	5.8	11.9	19.1
2003	1.4	6.1	11.4	18.9
2004	1.4	6.2	10.1	17.7
2005	1.4	6.4	9.1	16.9
2006	1.3	6.0	7.2	14.5
2007	1.3	5.7	6.8	13.8
शहरी जमाराशियां				
1980	3.9	6.9	14.2	25.1
1990	3.7	7.0	13.9	24.7
1995	3.4	5.9	12.9	22.2
2000	2.8	5.9	14.3	23.0
2001	2.8	6.0	14.1	22.9
2002	2.6	6.0	14.1	22.7
2003	2.5	6.3	14.0	22.8
2004	2.6	6.5	12.8	21.9
2005	2.6	6.7	12.2	21.5
2006	2.5	7.0	11.1	20.6
2007	2.5	6.5	11.5	20.5
महानगरीय जमाराशियां				
1980	8.0	8.5	22.8	39.3
1990	8.5	8.5	21.9	38.9
1995	10.5	8.5	26.3	45.3
2000	7.7	7.8	27.1	42.6
2001	7.2	8.0	27.6	42.8
2002	6.5	7.7	29.7	43.9
2003	6.3	7.8	30.4	44.5
2004	7.4	8.3	31.8	47.5
2005	7.5	8.7	33.2	49.4
2006	7.9	10.2	36.0	54.1
2007	8.0	9.4	38.5	56.0

टिप्पणी : 1980 के आंकड़े कैलेंडर वर्ष से संबंधित हैं।
स्रोत : भारत में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंक की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, भारतीय रिजर्व बैंक।



ऋण का एक हिस्सा नकद ऋण के रूप में मिलता है, बैंक ऋण पर निर्भरता में कमी नकद ऋण सीमा तथा चालू खाता शेष में कमी की ओर ले जाती है। यह शायद उद्योग द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन को भी दर्शाता है। दूसरी ओर, कुल जमाराशियों में बचत जमाराशियों का हिस्सा सभी जनसंख्या समूहों में मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा।

4.35 स्वामित्व के पैटर्न के रूप में, बैंक की कुल जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा 1995 के 69.2 प्रतिशत से घटकर 2004 में 58.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.13)। एससीबी की कुल जमाराशियों में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 1995 के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2004 के अंत तक 14.5 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र की बचत दर में सुधार था जो बदले में गैर विभागीय सरकारी उद्यम के सुधरे हुए कार्यनिष्पादन का परिणाम था। सरकारी क्षेत्र के गैर विभागीय उद्यमों की औसत बचत दर 1991-92 से 1996-97 के दौरान जीडीपी के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 से 2006-07 के दौरान 4.1 प्रतिशत हो गई (मोहन, 2008)। कुल जमाराशियों में कंपनी क्षेत्र का हिस्सा (वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों) भी हाल के वर्षों में बढ़ गया, जो उनके कार्य-निष्पादन में सुधार को दर्शाता है। अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा संसाधन संग्रहण में वृद्धि से भी बैंकिंग क्षेत्र के पास निधियां जमा करने में वृद्धि हुई।

4.36 एससीबी की जमाराशियों के प्रकार के अनुसार स्वामित्व के पैटर्न का अलग-अलग विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू क्षेत्र के हिस्से में गिरावट का मुख्य कारण मीयादी जमाराशियों के हिस्से में गिरावट था। दूसरी ओर, सरकारी तथा कंपनी क्षेत्र की जमाराशियों में वृद्धि का मुख्य कारण मीयादी जमाराशियों में उनके हिस्से में वृद्धि

सारणी 4.13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में हिस्सा : क्षेत्र-वार

मार्चांत	सरकारी क्षेत्र	कारपोरेट क्षेत्र (गैर-वित्तीय)	कारपोरेट क्षेत्र (वित्तीय)	घरेलू क्षेत्र	विदेशी क्षेत्र	कुल जमा-राशियां
1	2	3	4	5	6	7
1995	9.2	4.2	6.7	69.2	10.7	100.0
1996	9.2	3.6	6.1	69.2	11.9	100.0
1997	8.6	4.0	7.7	67.4	12.4	100.0
1998	9.9	4.1	7.4	66.6	12.0	100.0
1999	10.2	4.1	8.8	65.3	11.5	100.0
2000	10.1	3.8	7.7	67.6	10.8	100.0
2001	10.0	4.6	7.3	67.2	11.0	100.0
2002	10.6	5.7	6.9	66.7	10.2	100.0
2003	11.8	5.1	6.7	65.4	11.0	100.0
2004	14.5	7.9	8.5	58.4	10.8	100.0
2005	14.6	8.7	7.8	60.7	8.3	100.0
2006	14.4	10.1	9.7	58.5	7.3	100.0

टिप्पणी : विदेशी क्षेत्र अनिवासियों, विदेशी वाणिज्य दूतावास, राजदूतावास, व्यापार मिशन, सूचना सेवाओं आदि तथा अन्य की जमाराशियां दर्शाता है।

स्रोत : भारत में स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां, भारतीय रिजर्व बैंक।

था। मीयादी जमाराशियों में विदेशी क्षेत्र के हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई (सारणी 4.14)। चालू जमाराशियों में, सरकारी तथा वित्तीय क्षेत्र के हिस्से में कुछ वर्षों में गिरावट आई, जबकि गैर वित्तीय कंपनी क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई, चालू जमाराशियों में घरेलू तथा विदेशी क्षेत्रों का हिस्सा मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। बचत जमाराशियों के भीतर, स्वामित्व के पैटर्न में कुछ वर्षों में कोई प्रमुख परिवर्तन दिखाई नहीं दिया तथा बचत जमाराशियों का बड़ा

सारणी 4.14: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों का विभिन्न प्रकारों में हिस्सा : क्षेत्र-वार

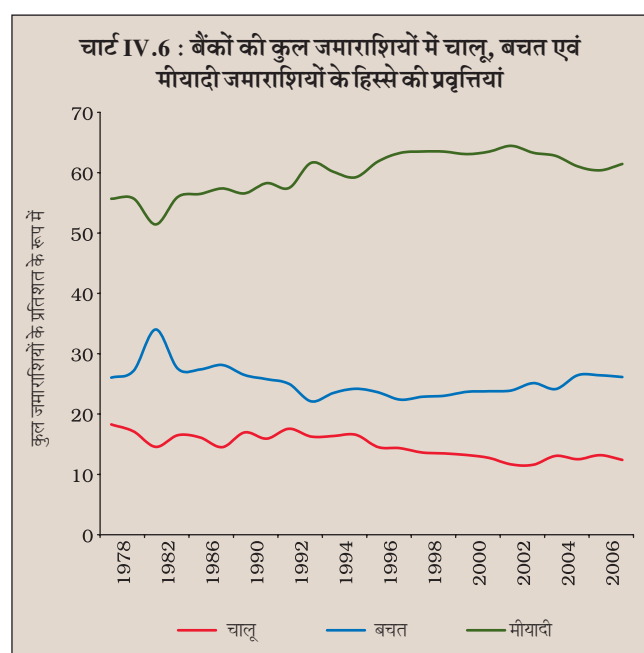
मार्चांत	सरकारी क्षेत्र	कारपोरेट क्षेत्र (गैर-वित्तीय)	कारपोरेट क्षेत्र (वित्तीय)	घरेलू क्षेत्र	विदेशी क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
चालू जमाराशियां						
1995	17.8	12.6	19.7	47.3	2.6	63,963
1996	17.0	11.3	18.7	50.7	2.4	63,656
1997	19.1	14.5	17.6	46.7	2.1	72,929
1998	17.5	13.7	19.4	46.6	2.8	82,370
1999	19.6	12.7	19.3	46.3	2.1	99,298
2000	19.4	12.3	17.0	47.9	3.4	1,12,657
2001	17.8	14.2	18.1	47.3	2.6	1,24,238
2002	17.8	16.1	16.4	46.3	3.3	1,30,903
2003	19.4	14.5	14.2	48.9	2.9	1,52,658
2004	16.2	22.3	12.9	45.9	2.7	2,05,776
2005	15.8	22.0	11.3	48.2	2.6	2,23,542
2006	14.1	22.4	14.5	45.4	3.6	2,85,081
बचत जमाराशियां						
1995	6.1	0.2	0.6	87.5	5.5	93,369
1996	7.1	0.2	1.0	86.8	4.9	1,03,443
1997	7.7	0.3	1.2	86.0	4.8	1,13,918
1998	8.4	0.2	1.4	84.8	5.3	1,38,293
1999	7.4	0.2	1.6	85.4	5.4	1,69,772
2000	6.7	0.1	0.8	87.3	5.1	2,02,089
2001	6.4	0.4	1.2	86.9	5.1	2,32,261
2002	6.4	0.2	0.7	87.3	5.3	2,68,866
2003	6.8	0.3	1.0	86.7	5.3	3,30,747
2004	7.3	0.6	1.2	83.6	7.3	3,80,098
2005	7.2	0.5	0.7	86.1	5.5	4,72,146
2006	6.5	0.5	1.0	86.4	5.6	5,71,020
मीयादी जमाराशियां						
1995	8.0	3.5	5.6	67.9	15.0	2,28,622
1996	8.1	3.1	5.1	66.9	16.8	2,70,904
1997	6.6	2.9	7.7	65.4	17.4	3,21,805
1998	8.9	3.4	7.0	64.3	16.4	3,84,147
1999	9.3	3.7	9.2	62.1	15.7	4,67,933
2000	9.5	3.4	8.3	64.3	14.4	5,38,067
2001	9.7	4.3	7.4	63.8	14.8	6,19,962
2002	10.8	5.8	7.4	62.8	13.2	7,24,606
2003	12.3	5.4	7.5	60.0	14.7	8,33,343
2004	17.0	7.7	10.3	51.3	13.8	9,88,384
2005	17.6	9.5	10.1	52.2	10.7	10,89,765
2006	18.0	11.6	12.4	49.1	8.8	13,04,899

स्रोत : भारत में स्थित बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां, भारतीय रिजर्व बैंक।

भाग घरेलू क्षेत्र द्वारा रखा गया था जिसका हिस्सा 1995 तथा 2004 के बीच 84-88 प्रतिशत के बीच के दायरे में था।

4.37 कुल मिलाकर मीयादी जमाराशियों का हिस्सा मार्च 1995 के अंत के 59.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2000 के अंत में 63.1 प्रतिशत हो गया तथा मार्च 2002 के अंत में वह 64.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया। बचत जमाराशियों का हिस्सा मार्च 1995 के अंत के 24.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2000 के अंत में 23.7 प्रतिशत रह गया। बाद में, बचत जमाराशियों का हिस्सा मार्च 2007 के अंत तक बढ़कर लगभग 26.1 प्रतिशत हो गया, जबकि मीयादी जमाराशियों का हिस्सा घटकर 61.5 प्रतिशत रह गया (चार्ट IV.6)।

4.38 तथापि मीयादी जमाराशियों के भीतर, 1990 के आरंभ से मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता का प्रोफाइल उल्लेखनीय रूप से कम हो गया। दीर्घतर परिपक्वतावाली जमाराशियों (5 वर्ष से अधिक) का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से कम हो गया, जबकि अल्पतर (एक वर्ष तक) परिपक्वतावाली जमाराशियों का हिस्सा बढ़ गया (सारणी 4.15)। 1-3 वर्ष की परिपक्वतावाली मीयादी



सारणी 4.15 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का परिपक्वता-वार स्वामित्व स्वरूप (मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपए)

परिपक्वता अवधि (मूल)	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
व्यक्तिगत							
1 वर्ष तक	5,258 (9.0)	37,477 (20.7)	95,647 (23.9)	1,91,392 (31.2)	1,99,102 (31.5)	1,87,737 (29.3)	1,81,743 (25.2)
1-3 वर्ष	27,931 (47.9)	84,745 (46.8)	1,58,130 (39.5)	2,22,687 (36.3)	2,25,634 (35.7)	2,40,450 (37.6)	2,99,958 (41.5)
3-5 वर्ष	10,796 (18.5)	35,146 (19.4)	95,900 (23.9)	1,42,798 (23.3)	1,41,282 (22.4)	1,42,451 (22.2)	(1,60,298) (22.2)
5 वर्ष से अधिक	14,339 (24.6)	23,699 (13.1)	51,107 (12.8)	56,701 (9.2)	64,811 (10.3)	69,791 (10.9)	79,703 (11.0)
उप-जोड़	58,324 (100.0)	1,81,068 (100.0)	4,00,784 (100.0)	6,13,577 (100.0)	6,30,829 (100.0)	6,40,429 (100.0)	7,21,703 (100.0)
अन्य							
1 वर्ष तक	3,744 (31.9)	20,376 (49.1)	53,657 (46.5)	1,64,729 (51.1)	2,19,889 (50.7)	3,04,767 (50.3)	4,15,683 (47.6)
1-3 वर्ष	5,121 (43.6)	16,008 (38.6)	39,099 (33.9)	96,636 (30.0)	1,37,199 (31.6)	2,08,208 (34.4)	3,37,568 (38.6)
3-5 वर्ष	1,038 (8.8)	3,384 (8.2)	17,992 (15.6)	40,567 (12.6)	51,331 (11.8)	58,776 (9.7)	85,095 (9.7)
5 वर्ष से अधिक	1,848 (15.7)	1,685 (4.1)	4,696 (4.1)	20,348 (6.3)	24,898 (5.8)	34,172 (5.6)	36,091 (4.1)
उप जोड़	11,752 (100.0)	41,453 (100.0)	1,15,444 (100.0)	3,22,279 (100.0)	4,33,317 (100.0)	6,05,924 (100.0)	8,74,437 (100.0)
जोड़							
1 वर्ष तक	9,002 (12.8)	57,853 (26.0)	1,49,304 (28.9)	3,56,120 (38.0)	4,18,991 (39.4)	4,92,504 (39.5)	(5,97,427) (37.4)
1-3 वर्ष	33,052 (47.2)	1,00,753 (45.3)	1,97,229 (38.2)	3,19,323 (34.2)	3,62,833 (34.1)	4,48,659 (36.0)	6,37,526 (39.9)
3-5 वर्ष	11,834 (16.9)	38,530 (17.3)	1,13,892 (22.1)	1,83,364 (19.6)	1,92,613 (18.1)	2,01,227 (16.1)	2,45,393 (15.4)
5 वर्ष से अधिक	16,188 (23.1)	25,384 (11.4)	55,803 (10.8)	77,048 (8.2)	89,709 (8.4)	1,03,963 (8.3)	1,15,794 (7.3)
जोड़	70,076 (100.0)	2,22,520 (100.0)	5,16,228 (100.0)	9,35,856 (100.0)	10,64,146 (100.0)	12,46,353 (100.0)	15,96,140 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े उप-जोड़ / जोड़ में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारत में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां, भारतीय रिजर्व बैंक।

जमाराशियों का हिस्सा भी उल्लेखनीय रूप से कम हो गया, जबकि 3-5 वर्ष की परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों के हिस्से में थोड़ी गिरावट आई। यह पैटर्न मोटे तौर पर व्यक्तियों तथा गैर व्यक्तियों दोनों में देखा गया। मीयादी जमाराशियों में ब्याज दरों में गिरावट तथा अन्य बचत लिखतों पर कर-समायोजित प्रतिलाभों में वृद्धि इस प्रवृत्ति में अंशदान करनेवाले दो प्रमुख कारक थे।

4.39 2005-06 से 2007-08 के चौथे चरण में, मांग तथा मीयादी दोनों जमाराशियों में वृद्धि के कारण जमाराशि वृद्धि में तेजी आई (देखें सारणी 4.4)। 2003-04 से वृद्धि की गति बढ़ने के साथ, बैंकों से ऋण की मांग में निरंतर आधार पर वृद्धि हुई, जिससे बैंकों को आक्रामक जमा संग्रहण के लिए रणनीतियां तैयार करनी पड़ीं। इस चरण में मांग जमाराशियों में हुई तेज वृद्धि ने कुछ सीमा तक चालू खाते में शेष राशियों में वृद्धि दर्शायी, जो बैंक ऋण के उठाव में वृद्धि तथा पूंजी बाजार की स्थितियों में उछाल को देखते हुए म्यूच्युअल फंडों और कंपनियों द्वारा निधियां रखे जाने के अनुरूप थी। जहां तक आवधिक जमाराशियों का संबंध है, 'लेवल प्लेइंग फील्ड' उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2006-07 के केंद्रीय बजट में धारा 80 सी के तहत कर लाभों का विस्तार 5 वर्ष और अधिक परिपक्वतावाली अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों तक भी कर दिया (बॉक्स IV.2)। 2004-05 से

उच्चतर स्तर पर बैंकों से ऋण के उठाव में वृद्धि बने रहने को देखते हुए, बैंकों ने विभिन्न परिपक्वता की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें अल्प बचतों पर लागू ब्याज दरों से ऊपर करनी शुरू कर दीं ताकि विभिन्न जमा योजनाओं की आकर्षकता में सुधार हो सके। तथापि, डाक घर जमाराशियों पर ब्याज की दरें अपरिवर्तित बनी रहीं (देखें सारणी 4.9)। तदनुसार, आरंभ में ब्याज दर अंतर कम हो गया तथा बाद में वह बैंक जमाराशियों के पक्ष में चला गया। फलस्वरूप, अल्प बचतों से निधियों का झुकाव बैंक जमाराशियों की ओर हुआ (देखें चार्ट IV.5)।

4.40 दीर्घावधि जमाराशियों पर मिलनेवाले कर लाभों के अलावा, उच्चतर ब्याज दरों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक जमा योजनाएं आरंभ करने से भी बैंकों द्वारा आवधिक जमा संग्रहण में सुधार हुआ। जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) की न्यूनतम परिपक्वता अवधि कम कर अप्रैल 2005 में 7 दिन कर दिए जाने से भी सीडी में रुचि बढ़ गई। जून 1989 में आरंभ किए गए सीडी अनिवार्य रूप से प्रतिभूतिकृत अल्पावधि आवधिक जमाराशियां हैं जो अल्पावधि अधिशेष निधियों का नियोजन करने के लिए निवेशकों को गुरुतर लचीलापन प्रदान करते हैं। उन्हें चलनिधि की सख्ती की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा मीयादी जमा दरों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर बट्टा दरों पर जारी किया जाता है। 1992 में सीडी पर जमा दरें अविनियमित किए जाने तथा 2002 में उनका

बॉक्स IV.2 अल्प बचत दरों का युक्तियुक्तकरण

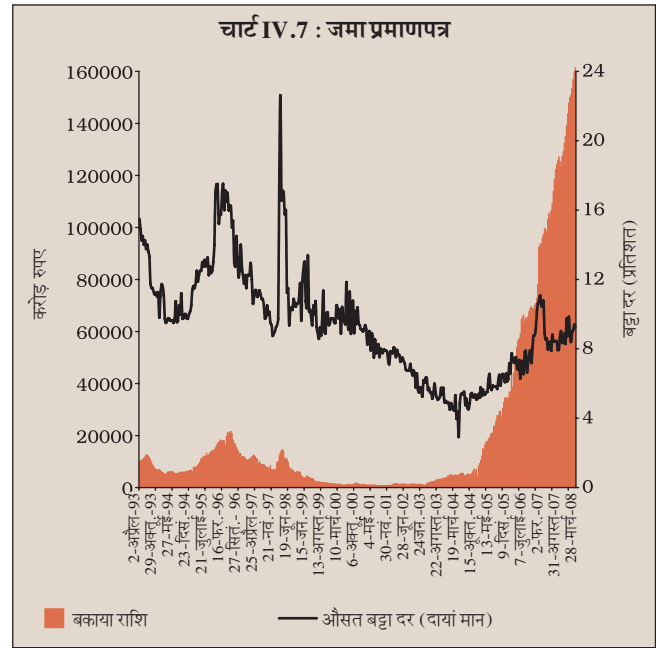
ब्याज दरों के अविनियमन की प्रक्रिया के अंग के रूप में, सरकार ने 1999-2000 में अल्प बचत पर ब्याज दरों को युक्तियुक्त बनाया। हाल के वर्षों में, सरकार ने उन विभिन्न वित्तीय बचत लिखतों पर लागू कर उपचार को और युक्तियुक्त करने का प्रयास किया, जो समरूप नहीं थीं। बचत योजनाओं में किए जाने वाले अंशदानों के करायान में, ऐसी योजनाओं में संचित राशि पर उगाहे जाने वाले कर में तथा आहरण के अंतिम चरण में कर उपचार में काफी अंतर है। एकरूपता में इस कमी के कारण विभिन्न वित्तीय लिखतों के बीच कृत्रिम विकृतियों तथा पूर्वाग्रह को प्रेरणा मिलती है। जहां कई बचत योजनाएं 'मुक्त-मुक्त-मुक्त' (ईईई) नामक सभी तीन चरणों में कर से मुक्त होती हैं, अन्य योजनाएं या तो संचय के स्तर पर अथवा अंतिम चरण में प्राप्त भुगतान के स्तर पर कर के अधीन होती हैं। 'मुक्त-मुक्त-करयुक्त' (ईईटी) पद्धति में वित्तीय बचतों के करायान संबंधी सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथा को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने भी 1 अप्रैल 2006 तक चरणबद्ध रूप में इस प्रणाली में अंतरण किया। पहले उपाय के रूप में, इसके लिए छूट पद्धति से आय आधारित कटौती पद्धति में अंतरण अपेक्षित था। अतः, केंद्रीय बजट 2005-06 के प्रस्ताव के अनुसार, विनिर्दिष्ट बचत योजनाओं में किए गए अभिदान-निवेश के लिए धारा 88 के तहत कर छूट प्रदान करने की उस समय लागू पद्धति को आय कर अधिनियम के अध्याय VI-क के तहत एक नयी धारा 80सी जोड़कर अभिदानों के लिए आय आधारित कटौती द्वारा प्रतिस्थापित

किया गया। तदनुसार, व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार को कतिपय विनिर्दिष्ट योजनाओं में कर योग्य आय में से पिछले साल प्रदत्त अथवा जमा की गयी राशि के संबंध में एक लाख रुपये से अनधिक राशि को आय से कटौती की अनुमति दी गयी, जिसे क्रमिक रूप से बढ़ाकर 2007-08 में 1,15,000 रुपए (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सहित) तथा और बढ़ाकर 2008-09 के बजट में 1,30,000 रुपए किया गया। आश्रित मातापिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 15,000 रुपए की अतिरिक्त राशि की अनुमति दी जाएगी। आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत नयी योजनाओं के अंतर्गत कर लाभ के लिए पात्र बचत लिखतें वे ही हैं जो धारा 88 के तहत आय कर से छूट के लिए पात्र थीं, तथा इसमें जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि के लिए अंशदान अथवा आस्थगित वार्षिकी की योजनाएं, मूलभूत संरचना बांडों की खरीद, शिक्षण शुल्क का भुगतान, आवास ऋणों की मूल राशि की चुकौती आदि भी शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 तथा डाक घर आवधिक जमा खाता को पात्र बचत लिखतों में शामिल कर 2008-09 के बजट में धारा 80 सी की व्याप्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव है। अल्प बचत दरें तथा सीमांत आय कर दरें मार्च 2003 से अपरिवर्तित बनी हुई हैं, जबकि धारा 80 सी के तहत कर छूट सीमाएं क्रमिक बजटों में संशोधित कर बढ़ा दी गयी हैं। पूंजी बाजार लिखतों के संबंध में, यद्यपि अल्पावधि पूंजी लाभ पर उच्चतर कर दरें लागू हैं, दीर्घावधि पूंजी लाभ की छूट इन लिखतों को मीयादी जमाराशियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बना देती है।

संसाधन संग्रहण का प्रबंधन

न्यूनतम निर्गम आकार कम कर एक लाख रुपया किये जाने और उन्हें सिर्फ अब भौतिक रूप में जारी किए जाने की अपेक्षा किए जाने के बावजूद 2004 तक इस बाजार खंड में, 1990 के दशक के मध्य के दौरान ऋण में वृद्धि के वर्षों को छोड़कर, शायद ही कोई कार्यकलाप हुआ हो। 2004-05 से लगभग 30 प्रतिशत पर बैंक ऋण वृद्धि बने रहने के साथ, बैंकों ने ऋण की तीव्र मांग का समर्थन करने के लिए अपने जमा संग्रहण की अनुपूर्ति हेतु सीडी के निर्गम का अधिकाधिक आश्रय लिया। बड़ी मात्रा में जमाराशियां आकृष्ट करने हेतु नकदी की तंगी वाले बैंकों द्वारा प्रस्तावित किए जा सकने वाले प्रतिलाभ के लचीलेपन ने विशेष रूप से सीमित शाखा नेटवर्क और खुदरा ग्राहक आधार वाले निजी एवं विदेशी बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण हेतु सीडी को पसंदीदा मार्ग बना दिया। तदनुसार, बैंकों द्वारा जारी किए गए सीडी की बकाया राशि मार्च 2005 के अंत के 12,078 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2007 के अंत तक 93,272 करोड़ रुपए तथा और बढ़कर 28 मार्च 2008 को 1,47,792 करोड़ रुपए हो गई। तदनुसार, एससीबी की सकल जमाराशियों में बकाया सीडी का हिस्सा 2004-05 के एक प्रतिशत से कम से बढ़कर 2007-08 के दौरान 4.6 प्रतिशत हो गया। सीडी पर औसत बट्टा दर, जो ब्याज दरों में सामान्य तेजी के अनुरूप मार्च 2005 के अंत के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 11.1 प्रतिशत हो गई थी, उसके बाद कुछ कम हो गई (चार्ट IV.7)।

4.41 इस चरण में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों की वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई। फलस्वरूप, एससीबी की समस्त



जमाराशियों में एनआरआई जमाराशियों का हिस्सा, जो मार्च 1993 के अंत में 15.5 प्रतिशत था, निरंतर घटकर (1997 को छोड़कर) मार्च 2004 के अंत में 9.5 प्रतिशत तथा मार्च 2007 के अंत में 6.4 प्रतिशत रह गया (सारणी 4.16)। फलस्वरूप, कुल जमाराशियों में विदेशी जमाराशियों का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से कम हो गया (देखें

सारणी 4.16 : अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मार्चांत	एनआर (इ) आरए	एफसी एनआर (ए)	एफसी एनआर (बी)	एनआर (एनआर) आरडी	एफसी (बीएंडओ) डी	एफसी (ओ) एन	कुल एनआरआई जमाराशियां	कुल जमा राशियों में एनआरआई का हिस्सा (प्रतिशत)	कुल एनआरआई जमाराशियों में वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1991	7,040	19,845	—	—	515	—	27,400	12.1	—
1992	7,833	30,576	—	—	1,895	—	40,304	15.2	47.1
1993	8,616	33,163	—	1,952	3,261	—	46,992	15.5	16.6
1994	11,053	29,176	3,476	5,501	1,672	38	50,916	14.6	8.4
1995	14,348	22,207	9,648	7,831	—	32	54,066	13.3	6.2
1996	13,452	14,616	19,648	12,166	—	45	59,927	13.1	10.8
1997	17,886	8,282	26,906	20,116	—	14	73,204	13.6	22.2
1998	22,267	4	33,445	24,735	—	9	80,460	12.5	9.9
1999	25,629	—	33,222	28,058	—	—	86,909	11.3	8.0
2000	29,465	—	35,632	29,447	—	—	94,544	10.5	8.8
2001	33,357	—	42,357	31,966	—	—	1,07,680	10.2	13.9
2002	41,205	—	47,175	34,392	—	—	1,22,772	10.2	14.0
2003	71,184	—	48,651	16,253	—	—	1,36,088	10.0	10.8
2004	92,977	—	49,572	7,895	—	—	1,50,444	9.5	10.5
2005	93,159	—	50,108	1,015	—	—	1,44,282	7.9	-4.1
2006	98,443	—	58,272	—	—	—	1,56,715	7.2	8.6
2007	1,06,786	—	65,955	—	—	—	1,72,741	6.4	10.2

स्रोत : हैडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 एवं भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति से संबंधित रिपोर्ट, 2006-07।

सारणी 4.13)। 2003-04 के आरंभ से देखी गई तीव्र गिरावट के कारण थे - विभिन्न एनआरआई जमा योजनाओं का युक्तियुक्तकरण तथा विदेश में न्यूनतर ब्याज दरों को देखते हुए पूंजी प्रवाहों के प्रबंधन तथा बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा उधारों के आश्रय में वृद्धि की रणनीति के अंग के रूप में विभिन्न जमा योजनाओं हेतु रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम ब्याज दरों में गिरावट। वर्तमान में 24 अप्रैल 2007 से सभी परिपक्वताओं की अधिकतम सीमा एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के संबंध में लिबोर/स्वैप दर घटाव 75 आधार अंक तथा एनआर(ई)आरए जमाराशियों के संबंध में लिबोर/स्वैप दर है। एनआरआई जमा योजनाओं को भुगतान संतुलन के समर्थन के लिए 1970 के दशक में तथा 1990 के दशक में शुरू किया गया (बॉक्स IV.3)।

4.42 तथापि एनआरआई जमाराशियों में गिरावट का समग्र जमा वृद्धि पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा। पूंजी बाजार लिखतों (शेयर/डिबेंचर/म्यूच्युअल फंडों के यूनिट) से बैंकों को प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बावजूद जमाराशियों में वृद्धि दर्ज की गई। यह उल्लेखनीय है कि जहां

पूंजी बाजार लिखतों पर लाभांश आय कर से मुक्त है, निवेशकों को भी दीर्घावधि पूंजी लाभ पर कर नहीं अदा करना पड़ता, जबकि अल्पावधि पूंजी लाभ पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाता है (2008-09 के बजट में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया)। म्यूच्युअल फंडों तथा नए पूंजी निर्गमों द्वारा जुटाई गई निधियों में तीव्र वृद्धि हुई जो पूंजी बाजार में तेजड़िया रख को दर्शाता है। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्चतर वृद्धि पथ पर अग्रसर होने तथा समग्र एवं क्षेत्रवार बचत दरों में तीव्र वृद्धि होने के साथ, बैंकों, गैर बैंकों तथा इक्विटी बाजार लिखतों के जरिए संसाधन संग्रहण में आम तौर पर सुधार हुआ (सारणी 4.17)

4.43 घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों के विभिन्न घटकों में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया। घरेलू क्षेत्र की बचतों में बैंक बचतों का हिस्सा 1995-96 से 2004-05 के दौरान 36.9 प्रतिशत था जो उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2005-06 से 2006-07 के दौरान 50.9 प्रतिशत हो गया। पूंजी बाजार लिखतों तथा जीवन बीमा निधि का हिस्सा भी बढ़ गया। दूसरी ओर, सरकार पर दावों का हिस्सा गिर गया (देखें सारणी 4.7)।

बॉक्स IV.3 अनिवासी जमाराशियां

कई अन्य विकासशील देशों की तरह भारत अपनी बाह्य पूंजी अपेक्षाओं का एक भाग विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय मुद्रा दोनों में बैंकों द्वारा अनिवासियों के लिए तैयार की गयी विशेष जमा योजनाओं के जरिए जुटा रहा है। 1970 के दशक के तेल आघातों की पृष्ठभूमि में तथा तेल संपन्न देशों में नियोजित अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की बचतों का दोहन करने के लिए, रिजर्व बैंक ने अनिवासी बाह्य रुपया खाता [एनआर(ई)आरए] आरंभ कर पहली बार फरवरी 1970 में विशेष जमा योजनाएं तैयार कीं जिनके बाद नवम्बर 1975 में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता [एफसीएनआर(ए)] आरंभ किया गया। एफसीएनआर(ए) योजना को, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी जोखिम का वहन आरंभ में रिजर्व बैंक द्वारा तथा बाद में सरकार द्वारा किया जाता था, केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र पर पड़ने वाले प्रभाव तथा सरकार के प्रति इसकी अर्द्ध-राजकोषीय लागत को देखते हुए अगस्त 1994 में हटा दिया गया। बाजार निर्धारित विनिमय दर युग के अंतर्गत जमाकर्ताओं को एफसीएनआर(ए) का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] आरंभ किया गया, जिसके तहत विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी जोखिम का वहन बैंकों द्वारा उनकी जोखिम अवधारणाओं के आधार पर किया जाता है। एक नयी रुपया मूल्यवर्गित योजना अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमा [एनआर(एनआर)आरडी] आरंभ की गयी, जो आरंभ में अप्रत्यावर्तनीय थी, परंतु बाद में उसमें सिर्फ ब्याज संबंधी आय के पुनःप्रत्यावर्तन की विशेषता उपलब्ध करायी गयी। अप्रैल 2002 में एनआर(एनआर)आरडी योजना को हटा लिया गया। इस प्रकार, वर्तमान में सिर्फ दो अनिवासी भारतीय जमायोजनाएं - एनआर(ई)आरए योजना, जिसे एनआरई योजना के रूप में भी जाना जाता है तथा एफसीएनआर(बी) योजना - परिचालन में हैं। जहां अनिवासी भारतीय जमाराशियां बाह्य वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बैंकों द्वारा इन

जमाराशियों की स्वीकृति के मौद्रिक निहितार्थ थे। अतः, 1990 के दशक से अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं की आकर्षकता बनाए रखने की नीति है, जबकि साथ ही ब्याज के बहिर्वाह तथा समष्टि आर्थिक प्रबंधन की लागत के रूप में उधार की प्रभावी लागत कम की जानी है। इन उद्देश्यों के अनुरूप, जहां इन जमाओं पर ब्याज दरों को क्रमिक रूप से अविनियमित किया गया था, वहीं आरक्षित निधि अपेक्षाओं तथा, हाल की अवधि में, ब्याज दर की अधिकतम सीमाओं को समग्र समष्टि आर्थिक प्रबंधन के अनुरूप इन प्रवाहों को अनुकूल बनाने की रणनीति के अंग के रूप में पूंजी प्रवाह चक्रों के संबंध में 'फाइन्-ट्यून्' किया गया है।

एनआरआई जमा योजनाओं के जरिए बाह्य संसाधनों तक पहुंच बनाने के अलावा, बैंकों ने समय-समय पर कतिपय गैर-अनुकूल बाह्य गतिविधियों के प्रतिसाद में विशेष जमा योजनाओं के जरिए भी निधियां जुटाने का आश्रय लिया है। 1991 से विनिमय दर गारंटियों के साथ बैंकिंग सरणियों के जरिए ऐसी तीन योजनाएं आरंभ की गयी हैं। भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट के बाद, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अक्टूबर 1991 में पांच वर्षीय इंडिया डेवलपमेंट बांड (आईडीबी) जारी कर 1.6 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटायी। पूंजी प्रवाहों, विशेषकर ऋण प्रवाहों, में प्रत्याशित कमी को देखते हुए एसबीआई ने अगस्त 1998 में पांच वर्षीय रिसर्जेंट इंडिया बांड (आरआईबी) जारी कर 4.2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटायी। तीसरी बार, एसबीआई ने दिसम्बर 2000 में पांच वर्षीय इंडिया मिलेनियम डिपोजिट (आईएमडी) जारी कर एक पूर्वक्रयात्मक उपाय के रूप में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटायी ताकि विश्वभर में पेट्रोल के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में किसी प्रकार की संभावित कमी को नियंत्रित किया जा सके।

संसाधन संग्रहण का प्रबंधन

सारणी 4.17 : बैंकों, गैर-बैंकों तथा इक्विटी बाज़ार द्वारा संसाधन संग्रहण (प्रवाह)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	एनबीएफसीकेसाथ जनता की जमाराशियां	अल्प बचत	म्यूच्युअल फंड	गैर सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा नए पूंजी निर्गम	एससीबी की कुल जमाराशियां
1	2	3	4	5	6
1970-71	—	323*	18	66	878
1980-81	—	1,266	52	164	6,229
1990-91	—	8,545	7,508	4,312	25,582
1995-96	—	10,391	-5,833	15,998	51,526
1996-97	—	12,383	-2,037	10,410	80,119
1997-98	—	20,644	4,064	3,138	1,06,305
1998-99	-3,392	28,541	2,695	5,013	1,27,061
1999-00	-1,087	32,214	22,117	5,153	1,25,567
2000-01	-1,257	37,577	11,135	5,818	1,58,691
2001-02	737	37,769	10,120	5,692	1,50,544
2002-03	1,278	50,937	4,583	1,878	1,49,724
2003-04	-456	61,944	47,873	3,722	2,22,796
2004-05	882	81,995	2,789	13,079	2,59,109
2005-06	2,316	69,879	52,482	21,154	3,26,918
2006-07	—	36,761	91,271	31,600	5,32,299

* : 1971-72 से संबंधित ।

— : उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : 1994-95 तक की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां भारिबैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणियों से तथा 1995-96 एवं आगे की जमाराशियां समेकित तुलन पत्रों से हैं।

स्रोत : हैडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, भारतीय रिजर्व बैंक।

4.44 बैंक जमाराशियां देशी बचतों का अकेला सबसे बड़ा स्रोत हैं। समय-समय पर हुए कुछ घटबढ़ के बावजूद, देशी बचतों में बैंक जमाराशियों का प्रमुख स्थान बना हुआ है तथा इसने सकल देशी बचतों में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों का हिस्सा 1950 के दशक के 1.9 प्रतिशत के औसत से बढ़ाकर 2000-2007 के दौरान 10.8 प्रतिशत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। घरेलू क्षेत्र ने निर्माण, मशीनरी

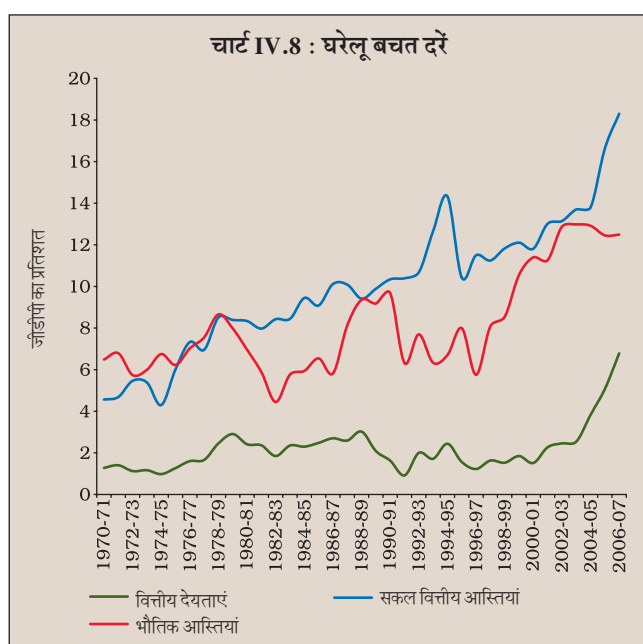
और उपस्कर, तथा हाल के वर्षों में स्टॉकों में परिवर्तन, जिनमें निवल घरेलू वित्तीय बचतों को कम करने की प्रवृत्ति थी, के रूप में भौतिक आस्तियों में निवेश करने के लिए अधिकाधिक वित्तीय देयताओं, विशेष तौर पर बैंक अग्रिमों के माध्यम से, का वहन किया है। तथापि यह नोट करना उल्लेखनीय है कि घरेलू क्षेत्र की भौतिक बचतें भी सकल वित्तीय बचतों में वृद्धि के अनुरूप रही हैं (सारणी 4.18 तथा चार्ट IV.8)।

सारणी 4.18: सकल देशी बचत दरें

(जीडीपी का प्रतिशत)

क्षेत्र	1950 का दशक	1960 का दशक	1970 का दशक	1980 का दशक	1990 का दशक	2000-01 से 2006-07 तक
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू क्षेत्र (1.1+1.2)	6.6 (68.2)	7.6 (61.7)	11.4 (66.5)	13.5 (71.0)	17.7 (77.0)	23.2 (80.9)
1.1 वित्तीय बचत	1.9 (18.8)	2.7 (21.8)	4.5 (26.0)	6.7 (35.4)	9.9 (43.3)	10.8 (37.9)
1.2 भौतिक बचत	4.7 (49.4)	4.9 (39.9)	6.9 (40.5)	6.8 (35.6)	7.8 (33.7)	12.3 (43.0)
2. निजी कारपोरेट क्षेत्र	1.0 (10.4)	1.5 (12.0)	1.5 (9.1)	1.7 (9.2)	3.8 (16.3)	5.3 (17.8)
3. सार्वजनिक क्षेत्र	2.0 (21.4)	3.2 (26.3)	4.2 (24.3)	3.7 (19.9)	1.5 (6.7)	0.7 (1.3)
4. सकल देशी बचत (1+2+3)	9.7 (100.0)	12.3 (100.0)	17.2 (100.0)	19.0 (100.0)	23.0 (100.0)	29.2 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सकल देशी बचतों के प्रतिशत हैं।



यद्यपि भौतिक आस्तियों में बचत का एक हिस्सा वास्तविक जरूरतों के लिए है, तथापि काफी बड़ा हिस्सा अनुत्पादक आस्तियों में अवरुद्ध है।

4.45 यद्यपि भारत में जीडीपी के प्रति बैंक जमा राशियों के अनुपात में (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा अपस्फीत) कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है, तथापि यह अभी भी लगभग सभी उन्नत देशों तथा नमूने में शामिल एशिया की कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में न्यूनतर था (सारणी 4.19)। यह इस तथ्य के बावजूद था कि कुछ उन्नत देशों में प्रधान तौर पर बाजार आधारित प्रणालियां हैं। विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करनेवाले 116 देशों के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि जीडीपी के प्रति बैंक जमा राशियों का अनुपात सामान्यतः आय स्तरों में वृद्धि के अनुरूप चलता है (चार्ट IV.9)।

4.46 भारत में जमा-जीडीपी अनुपात कम होने का प्रमुख कारण कुल बचतों में भौतिक बचतों का उच्च हिस्सा होना है, हालांकि भारत की बचत दर कई उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अनुकूल है (सारणी 4.20)।

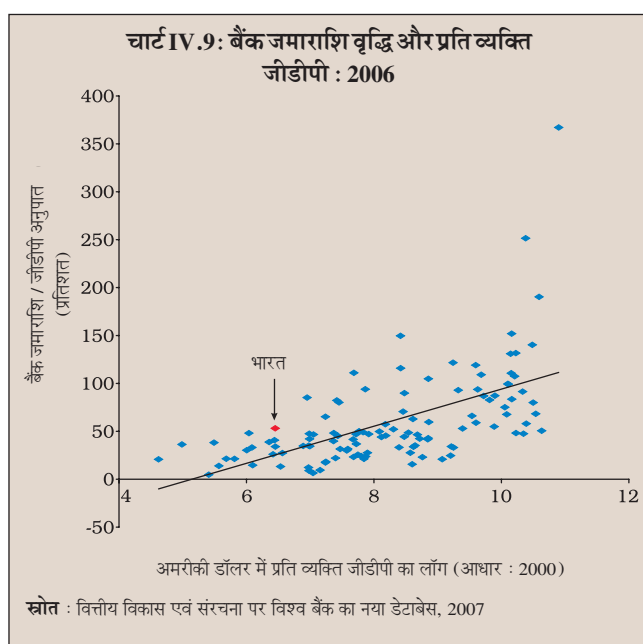
सारणी 4.19: जीडीपी की तुलना में बैंक जमा राशियों का अनुपात (सीपीआइ द्वारा अपस्फीत) : विभिन्न देशों के साक्ष्य

देश / वर्ष	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विकसित अर्थव्यवस्थाएं										
ऑस्ट्रेलिया	0.38	0.42	0.38	0.37	0.33	0.34	0.48	0.54	0.62	0.75
कनाडा	0.32	0.33	0.44	0.46	0.56	0.60	0.70	0.73	0.68	1.52
फ्रान्स	0.17	0.23	0.27	0.37	0.65	0.61	0.58	0.60	0.62	0.68
जर्मनी	0.32	0.40	0.48	0.54	0.55	0.58	0.54	0.58	0.90	0.99
जापान	0.40	0.65	0.78	1.13	1.32	1.54	1.77	1.97	2.30	1.90
न्यूजीलैंड	0.24	0.19	0.16	0.20	0.24	0.26	0.72	0.74	0.82	0.94
स्वीडन	0.53	0.48	0.50	0.48	0.47	0.44	0.41	0.37	0.37	0.48
स्विटजरलैंड	0.85	0.85	0.89	0.73	0.84	1.05	1.02	1.13	1.31	1.40
यूनाइटेड किंगडम	0.32	0.28	0.27	0.33	0.26	0.37	0.88	0.63	1.01	1.32
यूनाइटेड स्टेट्स	0.55	0.62	0.60	0.65	0.65	0.70	0.69	0.56	0.64	0.68
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं										
ब्राजील	—	—	—	—	—	—	0.18	0.25	0.40	0.52
चिली	—	—	—	0.07	0.19	0.23	0.28	0.30	0.49	0.47
भारत	0.12	0.11	0.13	0.17	0.26	0.31	0.31	0.33	0.43	0.53
इंडोनेशिया	—	—	—	—	—	0.17	0.30	0.39	0.45	0.35
इजराइल	—	—	—	—	0.12	0.68	0.57	0.58	0.78	0.87
कोरिया	—	—	—	0.24	0.25	0.29	0.33	0.33	0.61	0.66
मलेशिया	0.14	0.16	0.30	0.56	0.62	1.02	0.81	0.95	1.12	1.16
मेक्सिको	0.17	0.24	0.21	0.25	0.22	0.19	0.14	0.25	0.25	0.23
फिलीपीन्स	0.12	0.14	0.16	0.13	0.18	0.23	0.25	0.39	0.50	0.47
साउथ अफ्रीका	—	—	0.55	0.54	0.46	0.49	0.48	0.44	0.50	0.57
थाईलैंड	—	—	0.21	0.28	0.32	0.53	0.63	0.73	1.03	0.94

टिप्पणी : 1. चूंकि जमा राशि के आंकड़े स्टॉक में तथा जीडीपी के आंकड़े प्रवाह में हैं, जीडीपी की तुलना में जमा राशि के अनुपात की गणना विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित अपस्फीति पद्धति से की गई है: $\{(0.5) * [F/P_{et} + Ft - 1/P_{et-1}]\} / [GDP/P_{at}]$, जहां F मांग, आवधिक तथा बचत जमा राशियां हैं, P_e अवधि के अंतका सीपीआइ है, तथा P_a औसत वार्षिक सीपीआइ है।

2. 1990 के जर्मनी एवं ब्राजील के आंकड़े वर्ष 1992 से संबंधित हैं।

स्रोत : वित्तीय विकास एवं संरचना पर विश्व बैंक का नया डेटाबेस, अक्टूबर 2007।



बैंकों की देयता संरचना: जमाराशि बनाम उधार

4.47 कई देशों में जमाराशि बैंकों के लिए निधियों का मुख्य स्रोत है। तथापि कुछ देशों में बैंक उधार पर काफी निर्भर रहते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली की तरलता और शोधनीयता तथा उसकी समग्र स्थिरता का प्रश्न उत्पन्न होता है (बॉक्स IV.4)।

4.48 जमाराशियां भारत में बैंकों के लिए निधियों का मुख्य स्रोत हैं। कुछ वर्षों में बैंकों की कुल देयताओं में जमाराशियों का हिस्सा मोटे तौर पर स्थिर बना रहा है। कुल देयताओं में पूंजी और आरक्षित निधियों का हिस्सा, जो 1990-91 में बहुत कम था, 1992-93 से लागू किए गए बासेल I मानदंडों के तहत जोखिम भारित आस्तियों पर आधारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं पर दिए जा रहे बल के अनुरूप काफी बढ़कर मार्च 1995 के अंत तक 6.2 प्रतिशत हो गया। जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का अनुपात (सीआरएआर), जो शुरुआत में 8 प्रतिशत था, मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही, रिजर्व बैंक ने भी ऋण की तीव्र

सारणी 4.20: सकल देशी बचत दर : विभिन्न देशों के साक्ष्य

(जीडीपी का प्रतिशत)

देश	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विकसित अर्थव्यवस्थाएं										
ऑस्ट्रेलिया	—	—	31.2	26.1	26.1	24.3	23.1	22.5	22.4	25.2
कनाडा	22.0	25.6	24.1	23.2	24.8	23.2	21.0	22.0	26.0	25.3
फ्रान्स	—	—	26.7	23.9	22.2	18.3	21.2	19.7	21.4	19.6
जर्मनी	—	—	—	21.1	20.5	19.5	23.1	22.7	22.1	23.2
जापान	34.0	34.0	41.0	33.4	31.9	32.2	34.1	29.8	26.9	24.8
न्यूजीलैंड	—	—	—	20.6	19.4	23.8	20.3	24.1	23.2	22.1
स्वीडन	—	27.6	26.2	25.1	20.4	22.5	23.4	23.5	24.2	25.9
स्विटजरलैंड	—	34.8	35.8	30.3	28.7	29.1	31.9	28.5	28.9	28.3
यूनाइटेड किंगडम	17.6	19.4	21.1	17.7	19.9	19.3	17.6	16.6	15.5	13.6
यूनाइटेड स्टेट्स	19.6	21.2	18.4	18.4	19.8	17.5	16.3	16.9	16.6	13.5
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं										
ब्राजील	19.6	22.2	20.1	22.9	21.1	24.4	21.4	16.5	16.5	19.7
चिली	15.2	19.3	19.8	15.0	16.9	19.6	28.6	28.4	23.7	34.9
भारत	11.2	13.7	14.2	16.9	18.5	19.0	22.8	24.4	23.7	32.4
इंडोनेशिया	12.4	7.9	14.3	26.6	38.0	29.7	32.3	30.6	32.8	29.4
इजराइल	17.0	13.0	3.9	-3.4	6.8	5.7	14.4	16.9	20.6	18.3
कोरिया	1.9	8.0	15.2	20.2	23.9	30.6	36.4	36.6	34.2	30.9
मलेशिया	25.7	22.0	24.3	23.3	29.8	29.9	34.5	39.7	47.3	37.7
मेक्सिका	15.2	18.4	20.8	21.0	24.9	26.3	22.0	22.6	21.9	20.7
फिलीपीन्स	16.2	20.8	21.9	24.8	24.2	16.5	18.4	14.6	23.1	13.1
साउथ अफ्रीका	24.2	25.8	24.1	28.3	37.9	29.4	23.2	18.9	18.9	17.1
थाईलैंड	14.1	18.6	21.2	22.1	22.9	25.5	33.8	35.4	31.5	31.8

टिप्पणी : 1. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, स्विटजरलैंड, और यूनाइटेड स्टेट्स के 2006 के आंकड़े वर्ष 2005 से संबंधित हैं।

2. भारत के आंकड़े राजकोषीय वर्ष के आधार पर हैं।

स्रोत : वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स (डब्ल्यूडीआई) ऑनलाइन, विश्व बैंक तथा हैडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07, भारतीय रिजर्व बैंक।

बॉक्स IV.4 जमाराशि बनाम उधार राशि : कुछ मुद्दे

परंपरागत रूप से वित्तीय मध्यस्थता के लिए जमाराशियां बैंकों के निधायन का प्राथमिक स्रोत हैं, जबकि उन्हें उधार का आश्रय तब लेना पड़ता है जब जमाकर्ता वित्तीय बाजारों के विकास के अनुरूप वैकल्पिक लिखतों के प्रति अपनी वित्तीय आस्तियों का अंतरण करते हैं। चूंकि जमाराशियां सामान्यतः सरकार द्वारा निर्धारित एक श्रेयोल्ड सीमा तक बीमाकृत होती हैं, वे बिना किसी पूंजी हानि के मांग पर निधियां प्राप्त करने की अनुमति बचतकर्ताओं को देती हैं और इस प्रकार पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। दूसरी ओर, चूक संबंधी जोखिम तथा पहुंच पर प्रतिबंध दोनों के अभाव में बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं की तुलना में न्यूनतर दरों पर जमाराशियां जुटाते हैं क्योंकि जमा बीमा का लाभ बिना किसी प्रीमियम की अदायगी के बैंकों को उपलब्ध होता है। इस प्रकार, बीमाकृत जमाराशियां न सिर्फ निधियों का सब्सिडी-प्राप्त स्रोत हैं अपितु वे बैंकों के लिए पसंदीदा 'मूल' निधायन भी हैं। बीमाकृत जमाराशियों की तुलना में उधार राशियों का आश्रय न सिर्फ अधिक खर्चीला है अपितु यह बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक वित्तीय लिखतों पर उपलब्ध प्रतिलाभों के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है। जहां गैर-बीमाकृत निधियां प्रदान करनेवालों के सामने बैंक के विफल होने की स्थिति में अपनी राशि खोने की जोखिम रहती है, उनके द्वारा उच्चतर प्रतिलाभ की मांग किए जाने अथवा बैंक से कुछ राशि निकाले जाने की अधिक संभावना रहती है।

तरलता तथा सुरक्षा की निहित विशिष्टताओं के बावजूद, बचतकर्ताओं में अतिरिक्त निधियों के एक हिस्से को बैंक जमाराशियों से हटाकर म्यूच्युअल फंडों, इक्विटी, ऋण लिखतों तथा संविदात्मक बचत लिखतों यथा बीमा, और भविष्य निधि तथा पेंशन निधियों में अंतरित करने की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय बाजार की गतिविधियों के अलावा, कई अन्य कारक यथा जनसांख्यिकी और व्यक्तिगत अधिमानों में परिवर्तन भी ऐसे बदलाव में भूमिका निभाते हैं। जहां बुजुर्ग लोग निवेश आय पर निर्भर होते हैं तथा लम्बे समय के लिए अपनी राशि को आबद्ध करने के बजाय जोखिम से बचना चाहते हैं, कार्यशील (मध्यम आयु के) लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते समय उच्चतर प्रतिलाभ की मांग कर सकते हैं तथा दीर्घवधि के लिए निवेश करने के प्रति उनमें अधिक लचीलापन होता है। जनसांख्यिकी में बदलाव के बिना भी, यदि घरेलू क्षेत्र द्वारा अपनी पसंद को बदला जाए तथा वे बीमाकृत जमाराशियों की सुरक्षा के बजाय प्रतिलाभों को अधिक महत्व दें, तो भी बैंक जमाराशियों से लोग दूर भागेंगे। इसके अलावा, वैकल्पिक निवेश क्षेत्रों के प्रति घरेलू

क्षेत्र की गुरुतर पहुंच ने, जो सूचना प्रसंस्करण के विकास, दूर संचार प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय इंजिनियरिंग में प्रगति के कारण संभव हुई है, घरेलू क्षेत्र की निधियों का नियोजन गैर जमा आस्तियों में करते समय उनकी लेनदेन लागतों को कम किया है।

बैंकों द्वारा संसाधन प्रबंधन में इन परिवर्तनों के कई निहितार्थ हैं। पहला, सस्ती बीमाकृत जमाराशियों में कमी बैंकों की लागत को बढ़ा देगी क्योंकि वे उधार के जरिए अधिक खर्चीले निधायन पर निर्भर होंगे। अतः गैर जमा निधायन के प्रति बदलाव के लिए बैंकों को अधिक सक्रिय, जटिल तथा खर्चीले निधायन आधार प्रबंधन की ओर जाना पड़ेगा ताकि वे चुकौती संबंधी अपनी वचनबद्धताएं पूरी कर सकें। तदनुसार, बैंकों को राशि बनाए रखने के लिए जमाराशियों पर उच्चतर दर से ब्याज अदा करना पड़ सकता है, जो अन्यथा अन्य निवेशों की ओर जा सकती थी तथा जिसका प्रभाव बैंक की लाभप्रदता और निधि की स्थिरता पर पड़ता। दूसरा, कुछ परिस्थितियों में उधार अथवा थोक जमाराशियों जैसे गैर जमा स्रोतों के जरिए निधियां जुटाना बीमाकृत जमाराशियों की तुलना में मार्जिन पर सस्ता हो सकता है भले ही गैर जमा निधियों पर अदा की गयी दरें वस्तुतः उच्चतर हों। इसका कारण बीमाकृत जमाराशियां जुटाने के लिए अपेक्षित उच्चतर ब्याजेतर लागत यथा शाखाओं, स्टॉक तथा प्रौद्योगिकी का व्यय हो सकता है। साथ ही, नई जमाराशियां आकृष्ट करने के लिए दरें बढ़ाते समय इसके मौजूदा जमा आधार की लागत भी बढ़ सकती है, जबकि उधार इसकी मौजूदा जमाराशियों की लागत बदले बिना बैंकों द्वारा जुटाया जा सकता है। अतः, गैर जमा लिखतों के प्रति बढ़ती हुई पसंद को देखते हुए बैंक शाखा संबंधी अपने ढांचे को कम करना अथवा राशि जुटाने के लिए नई तकनीक का सहारा लेना किफायती पा सकते हैं। तथापि, निधायन के गैर जमा स्रोतों पर बढ़ती हुई निर्भरता के साथ, बैंकों को त्वरित और कम खर्चीली चुकौती अनुसूचियां तैयार करने, आपत्कालीन समर्थन निधियों के अतिरिक्त स्रोतों की स्थापना करने, तथा बिक्री योग्य और तरल प्रतिभूतियों का बफर स्टॉक निर्मित करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता हासिल करनी होगी।

इस प्रकार, इस नए माहौल में बैंकों के सामने मूल जमाराशियों में निहित भंडारित चलनिधि की तुलना में उधार ली गयी चलनिधि से जुड़ी जोखिमों के उचित मूल्यांकन की चुनौती है। उधार का आश्रय बढ़ने से उत्पन्न किसी प्रणालीगत जोखिम का उदय होने पर उससे निपटने के लिए विनियामकों को भी सक्रिय होने की जरूरत है।

वृद्धि के चरणों के दौरान बैंकों के तुलनपत्रों के संरक्षण हेतु एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में अग्रिमों की कतिपय श्रेणियों पर जोखिम भार का लगातार आकलन किया। इसने बैंकों को बाजार से संसाधन जुटाने तथा लाभ को पुनर्नियोजित करने के लिए भी प्रेरित किया (देखें अध्याय V)। तथापि, कुल देयताओं में पूंजी तथा आरक्षित निधियों का हिस्सा 1995 से मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। बैंकों ने नाबार्ड, एक्जिम बैंक तथा भूतपूर्व आइडीबीआई और रिजर्व बैंक जैसी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वित्त एवं पुनर्भाजन सुविधा के रूप में प्राप्त उधारों के जरिए अपने संसाधनों की अनुपूर्ति की।

रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को खाद्य ऋण पुनर्वित्त, निर्यात ऋण पुनर्वित्त, निधियों के स्रोतों तथा उपयोगों के बीच अंतर होने के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर सहायक (स्टैंडबाइ) पुनर्वित्त तथा अस्थायी वित्तीय संकटों से निपटने के लिए विवेकाधीन पुनर्वित्त के रूप में सुविधाएं प्रदान कीं। 1990 के दशक के दौरान, आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) 1991 के 15 प्रतिशत की ऊंचाई से कम कर नवंबर 1997 में 9.5 प्रतिशत किए जाने के साथ विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं को कुछ युक्तियुक्त बनाया गया जो 1990-91 तथा 1997-98 के बीच कुल देयताओं में उधार के हिस्से में गिरावट

में दिखाई दिया। बाद में, उधार का हिस्सा पुनः बढ़ गया, जो विदेशी मुद्रा उधार, विशेष रूप से निर्यातकर्ताओं को पोतलदानपूर्व विदेशी मुद्रा ऋण (पीसीएफसी) / निर्यात बिल पुनर्भाजन (ईबीआर) स्वीकृत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बैंकों को दिए गए लचीलेपन को दर्शाता है। बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सकल अंतराल सीमा के अधीन ऐसे ऋण स्वीकृत करने हेतु देशी विदेशी मुद्रा बाजारों में खरीद-बिक्री स्वैप के माध्यम से उत्पन्न निधियों का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई। बैंकों की समस्त जमाराशियों में समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार का हिस्सा क्रमिक रूप से मार्च 2001 के अंत में कुल जमाराशि के लगभग 0.1 प्रतिशत से बढ़कर नीतिगत लचीलेपन तथा विदेश में ब्याज दरों में आई नरमी के अनुरूप मार्च 2007 के अंत में लगभग 2.3 प्रतिशत हो गया। विदेशी उधार के अलावा, बैंकों ने वित्तीय संस्थाओं से मांग/मीयादी निधीयन के रूप में भी उधार लिया, जिनका कुल देयताओं में हिस्सा 1998-99 के प्रायः शून्य प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में लगभग 3.2 प्रतिशत हो गया। कुछ बैंकों ने गत टियर II पूंजी अपेक्षाओं के रूप में तथा मूलभूत सुविधा वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए पूंजी बाजार से ऋण लिखतों के जरिए भी निधियां जुटाईं। तथापि कुल मिलाकर बैंकों की कुल देयताओं में उधार का हिस्सा मोटे तौर पर 1992 जैसा बना रहा। दूसरी ओर, अन्य देयताओं और प्रावधानों के हिस्से में निरंतर गिरावट आई जो मुख्यतः बैंकों के कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में उनकी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में गिरावट (जो 1996-97 के 15.7 प्रतिशत से गिरकर 2006-07 में 2.5 प्रतिशत हो गया, और परिणामस्वरूप प्रावधानीकरण में गिरावट को दर्शाता है (सारणी 4.21)।

4.49 जमाराशियों की लागत, जो एक अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार और विभिन्न परिपक्वताओं की संविदाकृत जमाराशियों की औसत दर को दर्शाती है, 2003-04 तथा 2005-06 के बीच गिर गई तथा देशी ब्याज दरों में तेजी आने पर 2006-07 में थोड़ी बढ़ गई। उधार की लागत जमा की लागत की तुलना में न्यूनतर थी। तथापि, दोनों के बीच अंतर 2006-07 में उल्लेखनीय रूप से कम हो गया (सारणी 4.22)। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि जहां जमा दरें अंतर्निहित रूप से मंद हैं तथा चलनिधि की स्थितियों के साथ बाद में समायोजित होती हैं, प्रबंधित देयताओं (अर्थात् उधारों) पर ब्याज दरें निधियों की विकसित हो रही बाजार लागत के प्रति त्वरित रूप से रेस्पांड करती हैं जैसाकि अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से स्पष्ट है। निधियों की लागत में वृद्धि के साथ 2006-07 में निधियों पर प्रतिलाभ में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप, बैंक अपने अंतराल को कमोबेश बनाए रख सके।

4.50 कुल मिलाकर, भारत स्थित बैंकों ने जनता से जमाराशियां जुटाकर तथा बचत दर को बढ़ाकर वित्तीय मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक जमाराशियों में वृद्धि अलग अलग समय पर

सारणी 4.21: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताएं - प्रमुख घटकों का हिस्सा (आरआरबी को छोड़कर)

मार्चांत	पूंजी तथा आरक्षित निधि	जमाराशि	उधार	अन्य देयताएं तथा प्रावधान	कुल देयताएं (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6
1991	1.9	70.7	8.3	19.0	3,20,345
1992	2.6	77.7	6.6	13.0	3,41,524
1993	3.0	78.4	7.7	11.0	3,85,778
1994	5.1	80.3	3.4	11.2	4,34,949
1995	6.2	78.9	4.9	10.0	5,14,990
1996	6.2	76.4	7.1	10.4	5,99,168
1997	6.5	79.9	3.5	10.1	6,72,736
1998	6.7	81.0	3.2	9.1	7,95,412
1999	5.8	81.1	4.2	8.9	9,50,718
2000	5.6	81.1	4.1	9.2	11,05,464
2001	5.2	81.5	4.3	9.0	12,95,405
2002	5.5	78.5	6.7	9.4	15,36,424
2003	5.8	79.8	5.1	9.3	16,99,197
2004	5.9	80.0	4.8	9.3	19,74,017
2005	6.4	78.0	7.1	8.5	23,55,509
2006	6.6	77.7	7.3	8.4	27,85,863
2007	6.4	77.9	7.0	8.8	34,63,406

स्रोत : हैडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ दि इंडियन इकॉनॉमी, 2006-07 एवं भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति व प्रगति पर रिपोर्ट, 2006-07

अलग अलग रही है तथा प्रत्येक चरण में उसके साथ कुछ विशिष्ट लक्षण रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के तुरंत बाद शुरू हुए चरण में, बैंकों की जमाराशि वृद्धि में काफी तीव्रता आई क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बाद तेजी से शाखा विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों से बचत राशियां जुटाने में बैंकों को मदद मिली। दूसरे चरण (1984-1995) ने, बैंक जमाराशि वृद्धि में कमी आई क्योंकि बैंकों को वैकल्पिक बचत लिखतों, विशेषकर पूंजी बाजार लिखतों (शेयर/डिबेंचर/

सारणी 4.22 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिलाभ

सूचकांक	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
जमाराशि लागत	4.9	4.2	4.1	4.5
उधार की लागत	2.5	1.7	3.0	3.6
निधियों की लागत	4.8	4.0	4.0	4.4
निधियों पर प्रतिलाभ	8.2	7.1	7.4	7.7
स्प्रेड	3.4	3.1	3.3	3.3

टिप्पणी : 1. जमाराशि लागत = जमाराशि पर प्रदत्त ब्याज / जमाराशि
2. उधार की लागत = उधार पद प्रदत्त ब्याज / उधार
3. निधियों की लागत = (जमाराशि पर प्रदत्त ब्याज + उधार पर प्रदत्त ब्याज) / (जमाराशि+उधार)
4. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेश पर अर्जित ब्याज) / (अग्रिम + निवेश)

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति व प्रगति पर रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक।

म्यूच्युअल फंडों के यूनिट) तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह गैर मध्यस्थता का चरण था क्योंकि बचत राशियां बैंक जमाराशियों के रूप में नियोजित किए जाने के बजाए वैकल्पिक बचत लिखतों में अधिकाधिक नियोजित की जा रही थीं। 1995 और 2004 के बीच बैंक जमा वृद्धि में और कमी आई। इस चरण में, बैंकों को डाक घर जमाराशियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिनमें बैंक जमाराशियों की तुलना में कर समायोजित प्रतिलाभ काफी अधिक था। तथापि इसके बावजूद, घरेलू क्षेत्र की बचतों में बैंक जमाराशियों ने अपना हिस्सा बनाए रखा। इस चरण के दौरान स्वामित्व के पैटर्न तथा परिपक्वता पैटर्न दोनों में उल्लेखनीय बदलाव आया। सरकारी तथा कंपनी क्षेत्रों द्वारा धारित बैंक जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फलस्वरूप, घरेलू क्षेत्र द्वारा धारित जमाराशियों के हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई, हालांकि घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में बैंक जमाराशियों का हिस्सा मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। कुल जमाराशियों में मीयादी जमाराशियों का हिस्सा बढ़ गया। इसका मुख्य कारण सरकारी तथा कंपनी क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि था, क्योंकि मीयादी जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र की हिस्से में कमी आई थी। तथापि, मीयादी जमाराशियों के भीतर अल्पावधि जमाराशियों के पक्ष में परिपक्वता प्रोफाइल में उल्लेखनीय कमी आई।

4.51 चौथे चरण (2005-08) में, बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण के प्रबल प्रयासों के फलस्वरूप, बैंक जमा वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई। ऐसा डाकघर जमाराशियों को उपलब्ध लाभ बैंक जमाराशियों को भी प्रदान करने से संभव हुआ। डाकघर जमाराशियों तथा अल्प बचतों की वृद्धि में तेजी से कमी आई। इस चरण के दौरान, एनआरआई जमाराशियों की वृद्धि में तेजी से कमी आई। तथापि, बैंक जमा प्रमाणपत्रों द्वारा भी बड़ी मात्रा में निधियां जुटाने में समर्थ हुए। इस चरण के दौरान नए पूंजी निर्गमों के जरिए म्यूच्युअल फंडों तथा कंपनियों द्वारा जुटाई गई निधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फलस्वरूप, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों में बैंक जमाराशियों तथा पूंजी बाजार लिखतों का हिस्सा तेजी से बढ़ गया तथा सरकार पर दावों के हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई।

4.52 बैंकों की समग्र देयताओं में जमाराशियों तथा उधार राशियों का हिस्सा सुधारोत्तर अवधि में मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना रहा। 2003-04 तथा 2006-07 के बीच उधार की लागत जमा की लागत की तुलना में न्यूनतर थी। तथापि, उनके बीच अंतर 2006-07 में उल्लेखनीय रूप से कम हुआ।

4.53 कुल मिलाकर घरेलू क्षेत्र की बचत बढ़ाने में बैंकिंग क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, भौतिक बचतें घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों के अनुरूप बढ़ती रहीं तथा अनुत्पादक भौतिक बचतों को वित्तीय बचतों में परिवर्तित करना बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक चुनौती

है। अगले खंड में दिए गए विभिन्न देशों के अनुभवों के आलोक में इस मुद्दे पर खंड V में चर्चा की गई है।

IV. विभिन्न देशों के अनुभव

4.54 अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह दर्शाते हैं कि वित्तीय मध्यस्थता की भूमिका कुछ समय में विकसित हुई है तथा यह वित्तीय गतिविधि की अवस्था के अनुरूप विभिन्न देशों में अलग-अलग है। वित्तीय गतिविधि की विकासात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली एक विशिष्टता यह है कि लेनदेन एवं असममिति सूचना में क्रमिक रूप से कटौती हुई है। जिसके फलस्वरूप कुछ सीमा तक जमा लेने और ऋण देने संबंधी परंपरागत बैंकिंग व्यवसाय का महत्व कम हुआ है। दूसरा, इसके अनुरूप पेंशन निधि और म्यूच्युअल फंड जैसे अन्य वित्तीय मध्यस्थों का महत्व हाल की अवधि में बढ़ गया है। तीसरा, चूंकि वित्तीय गतिविधि ने वित्तीय फ्यूचर्स जैसे नए वित्तीय बाजार शुरू किए हैं, जो व्यक्तियों के बजाए मध्यस्थों के बाजार हैं, परंपरागत प्ररूपों की तुलना में वित्तीय मध्यस्थता के नए प्ररूपों की मांग बढ़ गई है। अतः हाल के वर्षों में मध्यस्थता के आधुनिक सिद्धांतों से यह प्रकट होता है कि तनाव जोखिम ट्रेडिंग, जोखिम प्रबंधन और सहभागिता लागत आधुनिक मध्यस्थता की मौजूदगी के प्रमुख कारण हैं। इस आधुनिक ढांचे के तहत, यद्यपि पेंशन निधियों और म्यूच्युअल फंडों जैसे बैंकेतर मध्यस्थों का महत्व काफी बढ़ गया है, बैंकों ने अपना कार्यकलाप वित्तीय मध्यस्थता के परंपरागत प्ररूप से विशाखीकृत करके एक उल्लेखनीय भूमिका निभाना जारी रखा है, जिसके द्वारा आय के स्रोत जमाराशि स्वीकारने एवं ऋण प्रदान करने के बजाए निधियों की मांग पूरी करने हेतु शुल्क आधारित कार्यकलापों से अधिक उत्पन्न होते हैं। इस वित्तीय मध्यस्थता प्रक्रिया के विकसित होने की प्रमुख विशिष्टताएं तथा बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसके सहयोजित प्रभाव यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी तथा जापान में वित्तीय प्रणालियों के विकास के अनुभव द्वारा उत्पन्न होते हैं (अलेन तथा सैंटोमेरो, 2001)।

4.55 यूनाइटेड स्टेट्स में, बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार के बावजूद बैंकिंग उद्योग में समेकन प्रक्रिया के फलस्वरूप वित्तीय बाजार अंश में अन्य प्रकार के वित्तीय मध्यस्थों के पक्ष में कमी आई है। कुल मध्यस्थ आस्तियों में बैंकिंग क्षेत्र के हिस्से में आई गिरावट 1970 के दशक के मध्य से, 1940-1970 की सापेक्ष स्थिरता की अवधि के बाद, दिखाई देती है। कुल वित्तीय मध्यस्थता आस्तियों में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 1970 के 42 प्रतिशत से गिरकर 2005 में 25 प्रतिशत के नीचे आ गया। मूल जमाराशियों के प्रति पहुंच खोने के साथ बैंक (क्योंकि बचतकर्ता वित्तीय प्रणाली के विकास के साथ बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं की ओर अग्रसर होते हैं), संबंधात्मक उधार के लाभ उधारकर्ताओं को प्रदान नहीं कर सके जिसके कारण वे बैंकों से हटकर न सिर्फ बैंक ऋण के निकट के स्थानापन्न का प्रस्ताव करनेवाली संस्थाओं की ओर अपितु प्रतिभूति जारी करनेवाली संस्थाओं की

ओर भी जाने के लिए प्रेरित हुए (मेस्टर, 2007)। तदनुसार, यूएस में 1990 के दशक के दौरान कुल वित्तीय मध्यस्थता आस्तियों में वित्तीय कंपनियों तथा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) के जारीकर्ताओं, तथा सरकार प्रायोजित उद्यमों (जीएसई), भूसंपदा निवेश न्यासों (आरईआइटी) और बंधक कंपनियों के हिस्से में तेज वृद्धि हुई (सारणी 4.23)। मध्यस्थों की आस्तियों की बाजार हिस्सेदारी में कमी के बावजूद, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आयी (शोल्टेन्स वैन वेन्सवीन, 1999)। यह वित्तीय आस्तियों के स्वामित्व के पैटर्न में परिवर्तन का सुझाव देता है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आस्ति धारण करनेवालों से बैंकेतर मध्यस्थों द्वारा धारित आस्तियों के पक्ष में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार अन्य मध्यस्थों की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र के आकार में कमी हुई है परंतु वह अर्थव्यवस्था की कुल वित्तीय आस्तियों की तुलना में नहीं है। यह यूएस में कंपनियों की इक्विटी के व्यक्तिगत स्वामित्व में गिरावट की दीर्घावधि प्रवृत्ति के अनुरूप है।

4.56 तथापि, यूएस में बैंक व्यवसाय तथा उपभोक्ता उधार में अपनी साझेदारी अन्य बैंकेतर मध्यस्थों के पक्ष में खो रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र की बाजार साझेदारी के कम होने का निहितार्थ यह है कि बैंक तुलनपत्र की देयता और आस्ति पक्ष के बीच सहक्रियाएं कम हो गयी हैं। बैंकों की बाजार साझेदारी में गिरावट तुलनपत्र के आस्ति पक्ष के बजाय देयताओं से शुरू हो सकती है, जो संबंधात्मक उधार की मांग में गिरावट के बजाय जमाराशियों की मांग में गिरावट को दर्शाता है। अध्ययन से यह पाया गया है कि बैंक की देयता संबंधी संरचना तथा इसके स्पष्ट उधार व्यवहार के बीच स्पष्ट संपर्क का आनुभविक साक्ष्य

है (बेर्लिन तथा मेस्टर, 1999)। अधिकांश बैंक संबंधात्मक उधार का कार्य करते हैं, जो प्रतिरूपी तौर पर न्यूनतर ऋण दरों, संपार्श्विक अपेक्षाओं में कम सख्ती, ऋण राशनिंग की कम संभावना, अधिक संविदात्मक लचीलेपन तथा उधारकर्ता फर्मों के लिए वित्तीय संकट की कम लागत से जुड़ा होता है। संबंधात्मक उधार की नींव जमाराशि जुटाने की बैंक की योग्यता पर निर्भर होती है। मूल जमाराशियां दर निरपेक्ष स्वरूप की होती है तथा बैंकों की निधियों की लागत को आर्थिक आघातों से सुरक्षित रखकर संबंध उधार प्रस्तावित करने में बैंकों को समर्थ बनाती हैं। अतः बैंक उधारकर्ताओं को बहु अवधिवाली संविदाएं देकर प्रतिकूल ऋण आघातों से उन्हें बीमाकृत करने में समर्थ होते हैं। तथापि, जब बैंक बचतकर्ताओं द्वारा उनकी वित्तीय बचतें म्यूच्युअल फंडों में अंतरित किए जाने पर मूल जमाराशियों तक पहुंच खो देते हैं, वे उधारकर्ताओं को कम बीमा (ऋण दर समकारी) प्रस्तावित करते हैं। इसके फलस्वरूप बैंक अपनी बाजार हिस्सेदारी उन मध्यस्थों के पक्ष में खो देते हैं जो ऋण के बजाय प्रतिभूतियां रखते हैं। यह प्रक्रिया इस बात को स्पष्ट करती है कि बैंकों ने किस प्रकार अपनी बाजार साझेदारी न सिर्फ उन संस्थाओं के पक्ष में खो दी है जो बैंक ऋणों के निकट स्थानापन्न का प्रस्ताव करती हैं अपितु प्रतिभूति जारी करने वाली संस्थाओं के पक्ष में भी हिस्सेदारी खो दी है। जमाराशियों घटती हुई मांग के कारण न सिर्फ बैंकों की निधियों की लागत बढ़ जाती है अपितु इससे बैंक ऋणों के लिए फर्मों की मांग को कम कर, क्योंकि वे कम प्रभेदी हो जाते हैं, बैंकों द्वारा संबंध उधार की साध्यता भी कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग क्षेत्र का दायरा कम हो रहा है क्योंकि उनका ऋण कम 'विशिष्ट' हो

सारणी 4.23 : यूनाइटेड स्टेट्स में कुल वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की आस्तियों का सापेक्ष हिस्सा

(प्रतिशत)

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं	1960	1970	1980	1990	2000	2003	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
बीमा कंपनियां							
जीवन बीमा	20.6	15.0	10.9	11.5	9.4	9.6	9.4
संपत्ति तथा दुर्घटना	3.0	2.7	3.5	3.5	2.5	2.4	2.6
पेंशन निधि							
निजी	3.9	3.2	4.3	4.7	3.2	2.7	2.2
सार्वजनिक (फेडरल, राज्य तथा स्थानीय सरकार)	3.7	4.3	4.2	4.1	4.1	3.4	2.6
वित्तीय कंपनियां तथा एबीएस निर्गमकर्ता	4.8	4.7	5.1	7.5	12.2	12.9	14.0
म्यूच्युअल फंड							
स्टॉक व बांड	1.1	1.3	0.8	6.4	8.5	9.2	10.2
मुद्रा बाजार	0.0	0.0	1.2	3.8	6.3	5.4	4.6
जीएसई, आरईआइटी, बंधक कंपनियां	2.5	5.1	9.0	14.8	21.2	23.8	22.2
डिपॉजिटरी संस्थाएं (बैंक)							
वाणिज्य बैंक	39.1	42.1	39.1	30.2	25.4	23.7	24.6
बचत और ऋण एवं म्यूच्युअल सेविंग्स बैंक	20.4	20.4	20.5	11.9	5.3	5.0	5.5
क्रेडिट यूनियन	0.9	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.0
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण हो सकता है कुल 100 प्रतिशत न हो।

स्रोत : फेडरल रिजर्व सिस्टम निधि प्रवाह खाते।

गया है, जो सूचना की प्रोसेसिंग तथा संप्रेषण की लागत में गिरावट को दर्शाता है जिसके कारण बैंक सेवाओं की अनुलिपि की लागत कम हो गयी है।

4.57 बैंक अपने तुलनपत्र के देयता पक्ष में आधार खो रहे हैं। विशेष रूप में, जब यूएस तथा अन्य औद्योगिक देशों में निर्भरता का स्तर बढ़ा, उपभोक्ता की मांग ऋण उत्पादों से हटकर बचत उत्पादों की ओर अंतरित हो गयी। सेवानिवृत्ति की आशा में आस्ति का संचय अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है तथा घरेलू धन संचय के लिए बाजार की यह वृद्धि तीव्रतम रही है। तथापि, परंपरागत बैंक जमाराशियां - आवधिक तथा बचत खाते - म्यूच्युअल फंडों, जिनकी लागत संरचना काफी क्षीण है तथा जो उल्लेखनीय रूप से उच्चतर प्रतिलाभ का प्रस्ताव करते हैं, की तुलना में आकर्षण खोती जा रही हैं। तदनुसार, 1980 से स्थिर आय वाले म्यूच्युअल फंडों की तुलना में बैंकों की आवधिक तथा बचत जमाराशियों में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके अलावा बैंकेतर संस्थाओं द्वारा नयी प्रौद्योगिकी शुरू किए जाने के साथ बैंक भी भुगतान सुकर बनाने की अपनी मूलभूत भूमिका खोते जा रहे हैं। क्रेडिट कार्डों के व्यापक उपयोग ने भी बैंकों की मांग जमाराशियों द्वारा भुगतान प्रणाली में अदा की जानेवाली केंद्रीय भूमिका कम कर दी है। भुगतान वाहनों को अधिकाधिक प्राथमिक तौर पर मोनोलाइन संगठनों द्वारा जारी किया जा रहा है अथवा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक डाक द्वारा जारी किया जा रहा है जो बहु-प्रॉडक्ट वाले सामान्य बैंकिंग संबंध से अलग है तथा इसने बैंकों की पिछली अद्वितीय भूमिका तथा इसके जमा प्रॉडक्टों की मांग को और कम कर दिया है। परंपरागत मध्यस्थता व्यवसाय की भूमिका कम होने के साथ बैंकिंग क्षेत्र तथा पूरी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए यूएस में निवल ब्याज आय का महत्व कम हो गया है। चूंकि मूल मध्यस्थता व्यवसाय में यह गिरावट आर्थिक रूप से प्रेरित है तथा प्रौद्योगिकीय रूप से चालित है, इसे संभवतः अनुत्क्रमणीय माना जाता है (एफ.अलेन आदि, उद्धरण देखें)।

4.58 यद्यपि मध्यस्थता का व्यवसाय कम हो गया है, यूएस में बैंकों ने परंपरागत मध्यस्थता कार्य से हटकर शुल्क-उत्पादक कार्यकलाप यथा न्यास, वार्षिकी, म्यूच्युअल फंड, बंधक बैंकिंग, बीमा, दलाली तथा लेनदेन सेवाएं शुरू कर दी हैं। अतः, जहां स्प्रेड संबंधी आय 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कुल बैंक आय का 80 प्रतिशत होती थी, क्षेत्र तथा मुद्रा केंद्र बैंकों ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपनी आय के आधे से अधिक शुल्क तथा ट्रेडिंग आय से प्राप्त किया। फलस्वरूप, यूएस में बैंकों की संरचना कुछ वर्षों में बदल गयी है जिसके द्वारा वे वित्तीय प्रणाली के लिए तरल बचत के मुख्य आधान तथा व्यवसाय और उपभोक्ता वित्त के लिए प्राथमिक स्रोत अब नहीं हैं।

4.59 यूएस स्थित बैंकों से संबंधित प्रवृत्तियों की अधिकाधिक नकल अन्य अर्थव्यवस्थाओं यथा फ्रांस, जर्मनी तथा यूके में की जा

रही है। बैंकों के कुल वित्तीय दावों के अनुपात के रूप में उन पर घरेलू दावों का अनुपात इन सभी देशों में गिर गया है, जो बैंकों पर सभी वित्तेतर क्षेत्रों में भी दिखायी दे रहा है। कुल वित्तीय देयताओं की तुलना में बैंकेतर वित्तीय मध्यस्थों के प्रति बैंकों की देयताओं का अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। साथ ही, कुल वित्तीय देयताओं के प्रति बैंकों की प्रतिभूति देयताओं का अनुपात 1981-1996 की अवधि के दौरान फ्रांस के लिए कुछ, जर्मनी के लिए थोड़ा बढ़ गया है परंतु यूके के लिए मोटे तौर पर उसी स्तर पर है (स्मिड्ट, आदि, 1998)।

4.60 सभी देशों के अनुभव से उभर रही विशेषता यह है कि घरेलू बचत आकृष्ट करने की बैंकों की योग्यता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू क्षेत्रों द्वारा अंततः धारित कुल आस्तियों के अलग-अलग धारण पैटर्न को दर्शाती है। उदाहरण के लिए 1994 में यूएस में घरेलू क्षेत्र द्वारा उनकी आस्तियों का सिर्फ 19 प्रतिशत नकद समतुल्य राशियों में, जमाराशि सहित, रखा गया, जबकि यूके में यह हिस्सा 24 प्रतिशत पर थोड़ा अधिक था। यूएस में 31 प्रतिशत का उल्लेखनीय हिस्सा स्थिर आय वाली आस्तियों यथा देशी और विदेशी बांडों, ऋणों और बंधकों में रखा गया, जबकि 46 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा जोखिमपूर्ण आस्तियों, देशी एवं विदेशी इक्विटी तथा भूसंपदा सहित, में रखा गया। तथापि यूके में घरेलू क्षेत्र द्वारा स्थिर आय वाली आस्तियों में 13 प्रतिशत की उल्लेखनीय रूप से निम्नतर राशि रखी गयी तथा 52 प्रतिशत की उल्लेखनीय रूप से उच्चतर राशि जोखिमपूर्ण इक्विटी तथा भूसंपदा आस्तियों में रखी गयी। दूसरी ओर, जापान में घरेलू क्षेत्र जोखिम से अपेक्षाकृत बचा हुआ है। वे अपनी आस्तियों का 52 प्रतिशत नकदी एवं नकदी समतुल्य राशियों में रखते हैं, 19 प्रतिशत स्थिर आय वाली आस्तियों में तथा सिर्फ 13 प्रतिशत जोखिमपूर्ण इक्विटी तथा भूसंपदा संबंधी आस्तियों में रखते हैं। फ्रांस तथा जर्मनी में भी घरेलू क्षेत्र में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति देखी गयी जहां वे 33 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत आस्ति धारिताएं क्रमशः नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में रखते हैं। यह भी नोट किया जाए कि जर्मनी, फ्रांस तथा जापान की तुलना में यूएस तथा यूके में घरेलू क्षेत्र द्वारा न सिर्फ उनके आस्ति संविभाग का उच्चतर हिस्सा जोखिमपूर्ण आस्तियों में रखा जाता है, अपितु वे अधिक राशि वित्तीय आस्तियों में रखते हैं। इस प्रकार, वित्तीय आस्तियों की मात्रा बढ़ने के साथ घरेलू क्षेत्र द्वारा रखी जाने वाली जोखिमपूर्ण आस्तियों का हिस्सा भी बढ़ जाता है।

4.61 यूएस तथा यूके की तुलना में जापान, फ्रांस तथा जर्मनी में बैंक जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र की आस्तियों का अपेक्षाकृत उच्चतर हिस्सा रखने को स्पष्ट करने वाला एक और कारक यह है कि देशों के पिछले समूहों में वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। अपूर्ण वित्तीय बाजारों की मौजूदगी में, बैंकों जैसी दीर्घावधि वित्तीय संस्थाएं उन जोखिमों के प्रभावी अंतर-कालिक समकरण की अनुमति देती हैं

जिन्हें एक निश्चित समय पर विशाखीकृत नहीं किया जा सकता, उसके द्वारा घरेलू क्षेत्र को विकसित वित्तीय प्रणाली वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बैंकों के पास अपनी वित्तीय बचतें रखने के लिए अधिक प्रेरित किया जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक अच्छे समय पर अल्पावधि तरल आस्तियों का 'सुरक्षित भंडार' प्राप्त करते हैं तथा खराब समय आने पर इस सुरक्षित भंडार का उपयोग करते हैं। फलस्वरूप, बैंक खातों तथा अन्य स्थिर आय वाली आस्तियों में अपनी अधिकांश आस्तियां रखनेवाले परिवार जोखिम से सुरक्षित रहते हैं तथा वे उपभोग प्रवाह को आसान करने में समर्थ होते हैं। दूसरी ओर, विकसित वित्तीय बाजार वाली अर्थव्यवस्था में, वित्तीय बाजारों से बैंकों द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा दीर्घावधि में बैंकों द्वारा अंतर-कालिक समकरण को अर्थक्षम नहीं बना सकती। इसका कारण यह है कि अच्छे वर्षों में घरेलू क्षेत्र द्वारा बेहतर प्रतिलाभ पाने के लिए बैंकिंग प्रणाली से अपनी बचत राशियां हटाकर उनका निवेश बाजार में किया जाता है और इस प्रकार बैंक आरक्षित निधियों के संचय को टाला जाता है। अतः जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसी बैंक आधारित प्रणालियों में अंतर-कालिक समकरण के जरिए जोखिम का प्रबंधन किया जा सकता है क्योंकि बैंक अल्पावधिक तरल आस्तियों में निवेश कर जोखिम समाप्त कर लेते हैं। जोखिम प्रबंधन के अन्य प्रकार अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिम विभाजन अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर, बाजार आधारित वित्तीय प्रणाली में वित्तीय बाजारों से आने वाली प्रतिस्पर्धा द्वारा वित्तीय मध्यस्थों के अंतर-कालिक समकरण को नकार दिया जाता है। वित्तीय बाजार अच्छे समय में अच्छा प्रतिलाभ देते हैं तथा घरेलू क्षेत्र के पास बैंकों से अपनी जमाराशियां हटाकर बाजार में निधियों का निवेश करने के लिए प्रोत्साहन रहता है। ऐसी वित्तीय प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिम विभाजन की स्थापना करना अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना रहता है कि जोखिम का प्रबंधन और उसकी लेनदेन इस तरह से की जाए ताकि जोखिम सहने की अधिक क्षमता रखने वाले अंततः उसका सहन करें। ऐसे देशों में वित्तीय प्रणालियां अधिक बाजार उन्मुख हो जाती हैं तथा डेरिवेटिव एवं उसी प्रकार अन्य तकनीक के उपयोग के जरिए जोखिम प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अमरीका में वित्तीय प्रणाली के विकास की प्रक्रिया में भी दिखायी देता है। 1970 के दशक के मध्य तक, यूएस में बैंक वित्तीय संस्थाओं में प्रमुख स्थान रखते थे तथा उनकी संरचना अधिकांशतः जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसी थी, जिसके द्वारा बैंक अंतर-कालिक समकरण करते थे। तथापि, बाद में वित्तीय नवोन्मेष आने पर वित्तीय प्रणाली का प्ररूप बैंक आधारित से बदलकर यूएस में बाजार आधारित हो गया तथा बैंकों ने बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अधिकाधिक इच्छा दर्शायी। तदनुसार, उन्होंने नए बाजारों में प्रवेश किया है तथा नए प्रॉडक्ट विकसित किए हैं, जबकि जमाराशि स्वीकार करने तथा उधार देने की उनकी परंपरागत

भूमिका निरंतर क्षीण होती जा रही है। इसके साथ अंतर-कालिक समकरण से विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिम विभाजन की ओर बदलाव आया है। उत्तरजीवी मध्यस्थकों की भूमिका जोखिमों का अंतर-कालिक समकरण अपनाने के बजाय डेरिवेटिव आदि के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच जोखिमों का प्रबंधन सुकर बनाने की रही है।

4.62 आस्ट्रेलिया में, 1995 से बैंकिंग प्रणाली का कार्यनिष्पादन काफी सीमा तक घरेलू क्षेत्र की गतिविधियों द्वारा चालित है। घरेलू क्षेत्र ने अपनी वित्तीय आस्तियों के अधिकाधिक हिस्से का निवेश इक्विटी के प्रत्यक्ष धारण, यूनिट ट्रस्टों में निवेश तथा अधिवर्षिता एवं अन्य प्रबंधित निधियों में आस्तियों के धारण के जरिए बाजार-संबद्ध प्रॉडक्टों में किया है। कुछ हद तक यह आस्ट्रेलिया में सेवानिवृत्ति बचत व्यवस्थाओं में किए गए परिवर्तनों में भी दिखायी दिया, अनिवार्य नियोक्ता अधिवर्षिता अंशदान लागू करना उल्लेखनीय है जिसे 2002 में बढ़ाकर कर्मचारी की आय का 9 प्रतिशत कर दिया गया। जिस सीमा तक घरेलू क्षेत्र द्वारा बाजार संबद्ध आस्तियों में निवेश किया गया, उस सीमा तक बैंकों तथा जमा स्वीकार करने वाली अन्य संस्थाओं के पास जमाराशियों में रखी गयी घरेलू क्षेत्र की बचतों का हिस्सा कम हो गया। वित्तीय बाजारों की गतिविधियों ने बैंकिंग के माहौल को बदल दिया तथा बैंकों के परंपरागत व्यवसाय, उल्लेखनीय रूप से जमा स्वीकारने और घरेलू उधार देने, में प्रतिस्पर्धी दबाव पैदा हो गया। आरंभ में बैंकों को आशा थी कि वे सेवानिवृत्ति संबंधी बचतों का एक बड़ा भाग 1996 में इन उत्पादों के लिए प्राप्त सरकारी अनुमोदन के अनुसरण में विशेष रूप से नामोद्दिष्ट सेवानिवृत्ति बचत खातों (आरएसए) में आकृष्ट कर सकते हैं। आरएसए अनिवार्य रूप से मीयादी जमाराशियां हैं जो सेवानिवृत्ति की आय तक रखे जाने पर रियायती दरें आकृष्ट करती हैं। तथापि, इन उत्पादों में घरेलू क्षेत्र द्वारा बचत संबंधी अधिक रुचि नहीं दिखायी जा सकी क्योंकि यद्यपि उनमें पूंजी की गारंटी थी तथापि 1990 के दशक में शेयर बाजार में चल रहे उछाल के दौरान इक्विटी आधारित निधियों में निवेश पर मिलने वाले अच्छे प्रतिलाभ की तुलना में ब्याज दर कम आकर्षक थी। इस संबंध में प्राप्त सीमित सफलता को दर्शाते हुए, कुछ बड़े बैंकों ने आस्ति/धन प्रबंधन निधियों के बड़े अधिग्रहण की श्रृंखला शुरू कर एक वैकल्पिक ऋण नीति अपनायी ताकि बढ़ रहे धन प्रबंधन क्षेत्र से संबद्ध शुल्क एवं आय प्राप्त किया जा सके। फलस्वरूप, आस्ट्रेलियाई स्वामित्ववाले लगभग सभी बैंक कुछ प्रकार के धन प्रबंधन उत्पाद का प्रस्ताव करते हैं। इस विस्तार के फलस्वरूप बैंकों ने 1990 के दशक के मध्य के 20 प्रतिशत से कम की तुलना में 2005 में आस्ट्रेलिया में प्रबंधनाधीन खुदरा निधियों के अनुमानित 40 प्रतिशत का नियंत्रण किया। यद्यपि, अधिग्रहण के बाद उनके शेयरों का रखरखाव करने में इन बैंकों को कठिनाइयां थीं, तथापि धन प्रबंधन बैंकिंग क्षेत्र के लिए राजस्व का अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ऋण के लिए घरेलू क्षेत्र की मांग सुदृढ़ है, घरेलू बचत दर में गिरावट आयी है तथा एक वृद्धिशील हिस्सा जमा से इतर उत्पादों के क्षेत्र में गया है। इस

प्रकार, बैंक के उधार में वृद्धि कम लागत वाली खुदरा जमाराशि की वृद्धि से अधिक है। साथ ही, इन जमाराशियों के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गयी है तथा उनमें से कुछ ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध से उच्च प्रतिलाभ वाले ऑनलाइन बचत खाते आरंभ किए जिनमें परंपरागत लेनदेन एवं मीयादी जमाराशि की तुलना में जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दरें प्रस्तावित की गयीं।

4.63 आस्ट्रेलिया स्थित बैंकों ने भी प्रतिभूतिकरण तथा ऋण प्रतिभूति निर्गम सहित अपनी देशी उधार वृद्धि का निधीयन करने के लिए कई वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाए। जहां कुछ छोटे बैंकों ने अपने ऋणों के प्रतिभूतिकरण की रणनीति का व्यापक उपयोग किया, वहीं बड़े बैंकों ने कमी का निधीयन देशी थोक बाजारों में पहुंचकर तथा अधिकाधिक मात्रा में विदेश से निधियां प्राप्त करके किया। फलस्वरूप, आस्ट्रेलिया के बैंकों की समस्त विदेशी देयताएं खुदरा जमाराशियों के मूल्य से अधिक हो गयीं तथा वे 1990 के दशक के मध्य के 15 प्रतिशत की तुलना में 2005 में उनकी कुल देयताओं का 27 प्रतिशत थीं। आस्ट्रेलिया के बैंकों की विदेशी देयताएं दिसम्बर 2005 में लगभग 370 बिलियन डालर थीं, तथा इनमें से लगभग दो तिहाई बेचानयोग्य ऋण प्रतिभूतियों के रूप में थीं। शेष विदेशी देयताओं में अनिवासी जमाराशियां तथा अंतःसमूह अंतरण शामिल थे। आस्ट्रेलिया में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाओं के लिए अंतःसमूह अंतरण निधियों का अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्रोत था। बैंकिंग प्रणाली की कुल देयताओं में खुदरा जमाराशियों तथा थोक जमाराशियों का हिस्सा क्रमशः 23 प्रतिशत और 50 प्रतिशत था। आस्ट्रेलिया के बैंकों ने अनेक बाजारों तथा मुद्राओं में प्रतिभूतियां जारी कीं, तथा बकाया अपतटीय ऋण प्रतिभूतियों का 80 प्रतिशत से अधिक यूएस एवं यूके के बाजारों में जारी किया गया और शेष 10 प्रतिशत हांगकांग और जापान में जारी किया गया। अपतटीय ऋण प्रधान तौर पर (80 प्रतिशत) विदेशी मुद्रा में होने के बावजूद आस्ट्रेलिया के बैंकों के सामने विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी जोखिम के प्रति एक्सपोजर थोड़ा था जिसे क्रॉस-करेंसी स्वैप तथा विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं का उपयोग करके प्रतिरूपी तौर पर हेज किया (अर्थात् बचाया) गया था। आस्ट्रेलिया के बैंकों के तुलनपत्रों में मार्च 2005 में 186 बिलियन डालर (चार वर्ष पहले 117 बिलियन डालर) का निवल विदेशी मुद्रा ऋण था, जिसमें से 168 बिलियन डालर का बचाव डेरिवेटिव बाजारों में किया गया था। तथापि, विदेशी निधीयन पर बैंकों की निर्भरता के बारे में कभी-कभी यह चिंता प्रकट की जाती है कि तनाव के समय में ऋण के रोल-ओवर की संभावना रहती है। इसके बावजूद कि उभरते बाजार के कुछ प्रभुतासंपन्न राष्ट्रों ने उनके विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋण का वित्तपोषण करने में कठिनाइयों का अनुभव किया था, इस बात का कम साक्ष्य था कि विकसित पूंजी बाजारों तथा फ्लोटिंग विनिमय दरों वाले देशों में देशी निवेशकों की तुलना में विदेशी निवेशकों द्वारा उनकी ऋण प्रतिभूतियों का रोल-ओवर करने की कम संभावना थी (हाल तथा वेरयार्ड, 2006)।

4.64 उन्नत देशों की तुलना में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में (ईएमई) बचत दरें सामान्यतः उच्चतर बनी रही हैं; बैंकिंग प्रणालियों ने बचत दरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कोरिया में, आधुनिक वित्तीय प्रणाली की स्थापना 1950 के दशक के आरंभ में उस समय की गयी थी जब केंद्रीय तथा वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणालियों को बैंक ऑफ कोरिया अधिनियम एवं बैंकिंग अधिनियम द्वारा प्रदत्त नए संस्थागत आधारों के तहत पुनः संरचित किया गया। 1960 के दशक में पूंजी संग्रहण सुकर बनाने के लिए तथा कम विकसित अथवा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वित्तीय समर्थन सुदृढ़ करने के लिए विशेषीकृत बैंकों की स्थापना की गयी। 1970 के दशक में कई बैंकेतर वित्तीय संस्थाएं आरंभ की गयीं ताकि वित्तीयन स्रोतों का विशाखीकरण किया जा सके, मुद्रा बाजार के विकास का संवर्धन किया जा सके तथा संगठित बाजार में निधियां आकृष्ट की जा सकें। आर्थिक नीति में 1980 के दशक के आरंभ से सरकार उन्मुख रुख से बाजार उन्मुख रुख की ओर बदलाव के साथ, वित्तीय उदारीकरण तथा अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ाने हेतु व्यापक उपायों की श्रृंखला के अंग के रूप में वाणिज्य बैंकों तथा बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं की संख्या और बढ़ गयी। 1997 में आई मुद्रा संकट के उपरान्त, व्यापक वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू करने के दौरान कोरियाई वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विशेष रूप से, समेकन के फलस्वरूप बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की संख्या में कमी आयी। कोरिया की वित्तीय प्रणाली में संरचनागत परिवर्तन दर्शाते हुए, कुल आस्तियों में बैंकों का हिस्सा 1995 के लगभग 67 प्रतिशत से घटकर 2006 में लगभग 60 प्रतिशत रह गया। कुल आस्तियों में व्यापारी बैंकिंग निगमों का हिस्सा लगभग 5 प्रतिशत से घटकर उसी अवधि में लगभग 1 प्रतिशत रह गया। इसकी वजह से बीमा कंपनियों का हिस्सा लगभग 7 प्रतिशत बढ़कर 13 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया तथा निवेश न्यास प्रबंधन कंपनियों का हिस्सा उसी अवधि के दौरान लगभग 8 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया। जून 2007 के अंत में, कोरिया के वाणिज्य बैंकों में 7 राष्ट्रव्यापी वाणिज्य बैंक तथा 6 स्थानीय बैंक (कुल 4,900 शाखाओं सहित) और 36 विदेशी बैंक शाखाएं थीं। तथापि, व्यावसायिक वर्गीकरण सुस्पष्ट था तथा वाणिज्य बैंकों को बहुत सीमित प्रतिभूति व्यवसाय करने की अनुमति थी। अगस्त 2003 तक उन्हें बीमा व्यवसाय करने की भी अनुमति नहीं थी, जिसके बाद बैंक बीमा शुरू करके उन्हें बीमा उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति दी गयी। बैंकों की निधियों का प्रमुख स्रोत जमाराशियों के रूप में बना रहा, जो जून 2007 के अंत में लगभग 60 प्रतिशत था, जबकि उधार राशियों का अंशदान निधियों के कुल स्रोतों में लगभग 25 प्रतिशत था। निधियों के उपयोग के संबंध में, बैंकों ने सबसे बड़े हिस्से का उपयोग ऋण प्रदान करने में किया जो जून 2007 के अंत में लगभग 71 प्रतिशत था।

4.65 थाईलैंड में बाजार प्रतिभागियों की संख्या तथा उनके बाजार कार्यकलापों की मात्रा दोनों रूपों में वित्तीय प्रणाली की संरचना में

उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। 1980 के दशक के मध्य तक, 30 वाणिज्य बैंकों के पास 1,526 शाखाएं थीं जो थाईलैंड में अधिकांश लेनदेनों का निपटान करती थीं। 16 सबसे बड़े बैंकों के पास वाणिज्य बैंकों की आस्तियों, जमाराशियों तथा ऋणों का 90 प्रतिशत से अधिक भाग था, जो उच्च संकेंद्रण तथा बैंकिंग उद्योग में कम प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है (बरबरा, 1987)। 1980 के दशक के मध्य में वैश्वीकरण बढ़ने के साथ, थाईलैंड में वित्तीय क्षेत्र का क्रमिक अविनियमन शुरू हो गया। ब्याज दर के क्षेत्र में, प्राधिकारियों ने क्रमिक रूप से ब्याज दर की अधिकतम सीमाएं समाप्त कर दीं ताकि जमा संग्रहण को प्रोत्साहित किया जा सके तथा वित्तीय प्रणाली को अधिक गतिशील बनाया जा सके। दीर्घावधि आवधिक जमाराशियों पर जून 1989 में, अल्पावधि आवधिक जमाराशियों पर मार्च 1990 में बचत जमाराशियों पर जनवरी 1992 में तथा ऋण दरों पर जून 1992 में ब्याज दर की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गयी। इसके अलावा, 1992-93 में नयी शाखाएं खोलने के लिए सरकारी बांड धारिता रखने की पूर्वापेक्षा को शिथिल बनाकर केंद्रीय बैंक ने वाणिज्य बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान किया। अधिक संबद्ध व्यवसायों तथा व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए ग्रामीण उधारकर्ताओं अथवा पास रहनेवालों को ऋण प्रदान करने संबंधी वाणिज्य बैंकों के दायित्व को भी शिथिल किया गया। बैंकों की देयताओं के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि कुल देयताओं में जमाराशियों का हिस्सा, जो 77 प्रतिशत से घटकर 1996 में 70 प्रतिशत रह गया था, बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया जो संकटोत्तर सुधार को दर्शाता है। उसके बाद, 2007 में जमाराशियों का हिस्सा पुनः घटकर लगभग 72 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, कुल देयताओं में उधार का हिस्सा, जो 1991 के 9 प्रतिशत से बढ़कर 1996 में 9.3 प्रतिशत हो गया था, 2003 में गिरकर 3.4 प्रतिशत रह गया तथा पुनः बढ़कर 2007 में 8.5 प्रतिशत हो गया। स्वामित्व का पैटर्न यह दर्शाता है कि थाईलैंड में बैंक जमाराशियां प्रधान तौर पर घरेलू क्षेत्र द्वारा रखी गयी हैं। तथापि, कुल जमाराशियों में व्यक्तियों का हिस्सा 1999 के लगभग 69 प्रतिशत से घटकर मार्च 2008 में लगभग 61 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, कुल जमाराशियों में व्यवसाय क्षेत्र का हिस्सा 16 प्रतिशत से बढ़कर उसी अवधि में 20 प्रतिशत हो गया।

4.66 1990 के दशक के आरंभ से जमाराशियों में हुई सामान्य गिरावट थाईलैंड की सकल देशी बचत दर 1991 में जीडीपी के 36.3 प्रतिशत के शिखर से निरंतर गिरकर 1997 (संकट वर्ष) में 35.1 प्रतिशत हो जाने में दिखाई देती है। 1998 में सुधरकर संकटपूर्व की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, बचत दर में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही तथा 2006 में 31.8 प्रतिशत रह गयी। बचत दर में यह गिरावट मुख्यतः घरेलू क्षेत्र के कारण आयी, जिसका कारण 3 प्रमुख कारक थे, यथा - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्धि, उपभोग में उछाल

तथा कंपनी एवं घरेलू बचतों के बीच बदलाव। 1990 के दशक के प्रारंभ से, बचत संग्रहण के प्रयास में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा जाल कार्यक्रम के प्रति बहुस्तंभीय दृष्टिकोण अपनाया ताकि वृद्ध एवं सेवानिवृत्त लोगों का उपयुक्त कल्याण सुनिश्चित किया जा सके और देशी बचत का संवर्धन किया जा सके। दूसरी ओर, सार्वजनिक और कंपनी क्षेत्र की बचत दरों ने प्रचक्रिय तौर पर व्यवहार किया। सकल बचत में निवल सार्वजनिक बचत का हिस्सा 1980 के दशक के आरंभ के एक अंकीय कम स्तर से बढ़कर आर्थिक उछाल की संकटपूर्व अवधि के दौरान मोटे तौर पर 25-28 प्रतिशत हो गया तथा संकट के ठीक बाद वह गिरकर 10 प्रतिशत रह गया। तथापि, 2002-03 में यह सुधरकर सकल राष्ट्रीय बचत का 18 प्रतिशत हो गया। निवल कंपनी बचत का हिस्सा निरंतर बढ़कर 1980 के दशक के आरंभ में सकल राष्ट्रीय बचत के 9 प्रतिशत से संकट से ठीक पहले 25 प्रतिशत हो गया, जो उस समयावधि के दौरान अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कंपनी क्षेत्र आय में उच्चतर वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, इस संकट के बाद इसका हिस्सा अस्थायी तौर पर गिरकर 6 प्रतिशत रह गया परंतु बाद में 2002-03 में बढ़कर लगभग 26 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गया जो संकट के बाद की अनुकूल आर्थिक स्थितियों तथा बढ़ते कंपनी लाभ का परिणाम था (पूत्राकूल आदि, 2005)।

4.67 चीन में, 1970 के दशक के उत्तरार्ध के पहले, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीसी) वस्तुतः एकमात्र ऐसी वित्तीय संस्था थी जिसने विनियामक होने के अलावा सभी प्रकार के वित्तीय सेवा कारोबार (यद्यपि उसकी किस्म तथा आकार बहुत सीमित था) किए। केंद्रीय बैंकिंग से वाणिज्यिक बैंकिंग को अलग किए जाने के साथ 1984 में द्वैध बैंकिंग प्रणाली का उदय हुआ (शियू आदि 2006)। इंडस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को पीबीसी से अलग करने के अलावा, तीन अन्य विशेषीकृत बैंकों का उदय हुआ। तथापि, उनके व्यावसायिक परिचालन योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के ढांचे के भीतर सीमित थे। समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की ओर सुधार के अनुरूप इन विशेषीकृत बैंकों को 1993 में वास्तविक वाणिज्यिक बैंकों के रूप में रूपांतरित किया गया। ऐसा नीति वित्तपोषण तथा वाणिज्यिक वित्तपोषण को अलग करने के लिए 1994 में 3 बड़े नीतिगत बैंकों के उदय से संभव हुआ। वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कानून तैयार किया गया जिसके द्वारा विशेषीकृत बैंकों को राज्य द्वारा स्वाधिकृत वाणिज्यिक बैंकों के रूप में स्थापित किया गया परंतु उन्हें उनके व्यावसायिक परिचालनों के लिए जवाबदेह बनाया गया। 2004 के अंत तक चार राज्य-स्वाधिकृत वाणिज्यिक बैंकों तथा तीन नीतिगत बैंकों के अलावा, कुछ अन्य प्रकार के बैंकों का उदय हुआ, यथा 12 शेरधारक वाणिज्य बैंक, 112 नगर वाणिज्य बैंक, 681

शहरी ऋण सहकारिताएं (यूसीसी), 32,854 ग्रामीण ऋण सहकारिताएं (आरसीसी), 8 ग्रामीण सहकारी बैंक, 7 ग्रामीण वाणिज्य बैंक, 211 विदेशी वित्तीय संस्थाएं, 220 विदेशी बैंक प्रतिनिधि कार्यालय, 4 आस्ति प्रबंधन कंपनियां, 59 न्यास और निवेश कंपनियां, 74 वित्त कंपनियां, 12 वित्तीय पट्टादायी कंपनियां, 3 ऑटो वित्त कंपनियां तथा बड़ी संख्या में डाकघर बचत संस्थाएं। वित्तीय प्रणाली के विस्तार को दर्शाते हुए, जमाराशि में निरंतर वृद्धि हुई तथा वह 1978 में जीडीपी के 31.1 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में जीडीपी का 176.2 प्रतिशत हो गयी। संस्थाओं एवं बाजारों के रूप में वित्तीय प्रणालियों के विशाखीकरण के बावजूद, बैंकों की प्रधानता जारी रही जो अन्य बाजार आधारित संस्थाओं की तुलना में बैंकों में अधिक सार्वजनिक विश्वास को दर्शाता है। ऐसा राज्य द्वारा प्रदान किए गए अव्यक्त बीमा कवर द्वारा सुसाध्य हुआ। यद्यपि सरकार ने पूंजी बाजार में इसी तरह का संरक्षण और हस्तक्षेप प्रदान करने का प्रयास किया है, पूंजी बाजार के स्वरूप ने उसमें जनता के विश्वास को कम किया है। अतः, चीन में बाजार आधारित वित्तीय कार्यकलाप की प्रक्रिया अभी स्थिर अथवा महत्वपूर्ण होनी है (लिपिंग हे, 2005)।

4.68 कुल मिलाकर, विभिन्न देशों के अनुभव यह सुझाते हैं कि वित्तीय क्षेत्र का विकास होने के साथ, बचतकर्ता परंपरागत बैंक जमाराशियों से दूर नई वित्तीय लिखतों के प्रति आकृष्ट हुए। ऐसा पूंजी बाजार में अनुकूल स्थिति आने पर और भी संभव हुआ। तथापि घरेलू क्षेत्र द्वारा रखी जमाराशियों में हुई गिरावट की क्षतिपूर्ति बैंकेतर मध्यस्थों की जमाराशियों द्वारा की गई। इस प्रकार, बैंकिंग क्षेत्र का आकार अन्य मध्यवर्तियों की तुलना में कम होता है, परंतु अर्थव्यवस्था की कुल वित्तीय आस्तियों की तुलना में नहीं। वस्तुतः, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का वर्तमान चरण कमोबेश इस पैटर्न का अनुकरण कर रहा है। तथापि, बैंक अपनी संसाधन संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए आक्रामक जमा संग्रहण के साथ कम खर्चीले गैर जमा संसाधन जुटाने के नए तरीकों का उपयोग करते हैं। पर, यह बैंकों तथा विनियामकों दोनों के समक्ष कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है क्योंकि इसका असर बैंकों की तरलता और शोधनीयता पर तथा वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता पर पड़ता है। उभरते बाजारों में, बैंकों द्वारा संसाधन संग्रहण ने उच्च देशी बचत दरें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि हाल के वर्षों में, बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियों में कुछ कमी आई जो गैर मध्यस्थता, उपभोग में उछाल तथा बदलती जनसांख्यिकी द्वारा आवश्यक हुए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि की जरूरत को दर्शाता है।

V. उभरते मुद्दे तथा भावी दिशा

4.69 जैसा कि भारतीय अनुभव से प्रकट होता है, आर्थिक वृद्धि में तेजी मोटे तौर पर घरेलू बचतों के स्तर में निरंतर वृद्धि, जिसे जीडीपी के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, से संभव हुई है।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल देशी बचतों में घरेलू बचतों का मुख्य स्थान है। तथापि हाल के वर्षों में, निजी कंपनी बचतों और सरकारी क्षेत्र की बचत दरों में तीव्र वृद्धि हुई है, जो राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन के कारण कंपनियों की लाभप्रदता और राजकोषीय विवेक में सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, यह नोट किया जाए कि उच्चतर लाभप्रदता के कारण कंपनी क्षेत्र की बचतों में सुधार मोटे तौर पर कई वर्षों से किए जा रहे सुधार का परिणाम है, जिसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा सहायक नीतिगत वातावरण की शक्तियों से उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार हुआ। आनेवाले वर्षों में निजी कंपनी क्षेत्र की बचत दरों में वृद्धि उसी पैमाने पर जारी नहीं रह सकेगी क्योंकि कंपनी क्षेत्र की द्वारा उठाए गए सुधारों के आरंभिक लाभ, विशेष तौर पर तुलनपत्रों को डीलिवरेज करके प्राप्त लाभ, भविष्य में उसी पैमाने पर उपलब्ध नहीं हो सकेंगे (मोहन, 2008)। इसी तरह, केंद्र सरकार द्वारा बजट में 2008-09 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के तहत यथानिर्धारित जीडीपी के शून्य प्रतिशत के बजाए जीडीपी का 1 प्रतिशत राजस्व घाटा अनुमानित किए जाने तथा छोटे वेतन आयोग के निर्णय के कार्यान्वयन से प्रत्याशित दबावों सहित विभिन्न कारकों से वित्तीय समेकन को होनेवाले और अधिक जोखिमों को देखते हुए, अल्पावधि में सरकारी क्षेत्र की बचत दरों को और अधिक बढ़ाने की अपनी सीमाएं होंगी। अतः, भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र देशी बचत बनाए रखने के लिए घरेलू क्षेत्र की बचत दर में सुधार लाने को मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए।

4.70 इस संबंध में, यह नोट किया जाए कि कुल घरेलू बचतों में वित्तीय बचतों (वित्तीय देयताओं को घटाकर) का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत अंक कम होकर चालू दशक में लगभग 47 प्रतिशत रह गया है जो भौतिक आस्तियों में उच्चतर बचतों को दर्शाता है। तदनुसार, वित्तीय बचत दर को बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती होगी जो ऐसी नई लिखतों, जिनमें जोखिम-प्रतिलाभ एवं परिपक्वता प्रोफाइल के अनुरूप घरेलू क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने की विशिष्टताएं हों, को लागू कर तथा बीमा एवं पेंशन सुधार जारी रखकर वित्तीय क्षेत्र को और गहरा करने पर निर्भर होगी। इसके अलावा, एक चुनौती यह होगी कि विभिन्न वित्तीय आस्तियों में बचत की वास्तविक अपेक्षा के ऊपर भौतिक आस्तियों के रूप में रखे गए घरेलू क्षेत्र के संसाधनों को निर्मोचित किया जाए। यद्यपि घरेलू क्षेत्र द्वारा उनकी वित्तीय बचतें मुख्यतः बैंक जमाराशियों के रूप में रखी जा रही हैं, कुल वित्तीय बचतों में इसका हिस्सा उल्लेखनीय रूप से घटकर 1970-1984 के लगभग 45 प्रतिशत के औसत से 1995-2005 के दौरान लगभग 37 प्रतिशत रह गया तथा पिछले दो वर्षों में यह बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया। यह सुधार आंशिक रूप से 2005-06 के बाद से उच्च ऋण की मांग पूरी करने के लिए बैंकों द्वारा आवधिक जमा संग्रहण के आक्रामक प्रयासों को तथा आंशिक रूप से विशेष बैंक जमा योजनाओं पर कर प्रोत्साहन लागू करने के सरकारी उपायों को दर्शाता है। अल्प बचत/डाकघर

जमा एवं बैंक जमा के बीच ब्याज दर अंतर, जो आरंभ में कम हो गया था, बाद में अल्प बचतों / डाकघर जमाराशियों पर ब्याज दरों में परिवर्तन न होने के कारण बैंक जमाराशियों के पक्ष में हो गया, जिससे बैंक जमाराशियां अधिक आकर्षक हो गईं। तदनुसार, आवधिक जमाराशियों की वृद्धि में हुई तीव्र उछाल ने एक सीमा तक अल्प बचतों से अलगाव को दर्शाया, जो संविभाग में सिर्फ बदलाव का संकेत देता है तथा विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान प्रवृत्ति को जारी रखा जा सकेगा। अतः, जमाराशियों की हाल की प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे विभिन्न जोखिम और प्रतिलाभ प्रोफाइल वाले जमाकर्ताओं के लिए उपयुक्त जमा योजनाएं शुरू कर अब तक अदोहित बचत राशियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, का दोहन करें।

4.71 उच्च वृद्धि का वर्तमान चरण सकल घरेलू वित्तीय बचत दर में वृद्धि द्वारा समर्थित है, जिसकी अगुवाई बदले में बैंकों द्वारा आक्रामक जमा संग्रहण द्वारा की गई है। यह देखा गया है कि वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 1992-93 से 2002-03 के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 से 2006-07 में 8.8 प्रतिशत हो जाना सकल घरेलू वित्तीय बचत दर जीडीपी के 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 15.6 प्रतिशत हो जाने द्वारा समर्थित था। उसी अवधि के दौरान, सकल घरेलू वित्तीय बचतों के प्रति बैंक जमाराशियों का अनुपात 36.7 प्रतिशत से बढ़कर 44.0 प्रतिशत हो गया। इन प्रवृत्तियों पर आधारित संवेदनशीलता विश्लेषण यह दर्शाता है कि जीडीपी में 1 प्रतिशत अंक की वास्तविक वृद्धि करने के लिए आर्थिक वृद्धि के वर्तमान चरण में सकल घरेलू वित्तीय बचत दर (सकल वित्तीय बचत/सांकेतिक जीडीपी) में 1.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि करना अपेक्षित होगा। इसके लिए, बदले में, सकल वित्तीय बचतों के प्रति बैंक जमाराशियों का अनुपात 2.5 प्रतिशत अंक बढ़ाना अपेक्षित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि की गति बनाये रखने के लिए संसाधन की बढ़ती हुई अपेक्षाओं के आलोक में, बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र सहित संसाधन संग्रहण की अपनी परंपरागत रणनीतियों का पुनराकलन करना होगा।

बैंक जमाराशियों के बदलते पैटर्न का प्रभाव

4.72 1990 के दशक के आरंभ से वित्तीय उदारीकरण के फलस्वरूप, बैंक जमाराशियों के स्वामित्व के स्वरूप में कुछ बदलाव हुआ है। सकल जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा निरंतर गिरा है, जबकि सरकारी और कंपनी क्षेत्रों के हिस्सों में वृद्धि हुई है। घरेलू क्षेत्र के हिस्से में हुई गिरावट मुख्यतः मीयादी जमाराशियों में उनके हिस्से में हुई तेज गिरावट को दर्शाती है। कंपनी तथा सरकारी क्षेत्रों से बढ़ी हुई रूचि आवधिक जमाराशियों की निर्धारित न्यूनतम परिपक्वता में क्रमिक कमी तथा थोक मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरों का प्रस्ताव करने की अनुमति बैंकों को दिए जाने के अनुकूल प्रभाव को दर्शाती है। आवधिक जमाराशियों के बारे में एक और

उल्लेखनीय विशेषता यह है कि सभी क्षेत्रों में पांच वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आयी है, जो आकर्षक प्रतिलाभ वाली वैकल्पिक बचत लिखतों की उपलब्धता को दर्शाती है। यह प्रवृत्ति भारत तक ही सीमित नहीं है तथा कई अन्य देशों में भी ऐसा देखा गया है, जिसका संकेत पहले दिया जा चुका है।

4.73 वित्तीय क्षेत्र का विकास होने के साथ जमा से इतर बचत संबंधी लिखतों के हिस्से में बैंक जमाराशियों की क्षति पर वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है। आने वाले वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ने की आशा है। अतः बैंकों के सामने इस बात की चुनौती है कि वे अब तक अदोहित बचत राशियां जुटाएं तथा न सिर्फ मौजूदा जमाकर्ताओं को बनाए रखने के लिए अपितु नए जमाकर्ताओं को आकृष्ट करने के लिए भी अपनी सेवाओं में सुधार करें। उन्हें समावेशक वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन पर हाल में दिए गए बल द्वारा नए अवसरों की तलाश कर अपने जमा आधार को व्यापक बनाना होगा। वृद्धि की प्रक्रिया सुदृढ़ तथा अधिक समावेशक होने के साथ, ऐसी आशा की जा सकती है कि वित्तीय उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप बैंकिंग सेवाओं का अधिक विस्तार आवश्यक हो जाएगा।

बदलती जनसांख्यिकी तथा वित्तीय सेवाएं

4.74 बैंकों को बदलती जनसांख्यिकी रूपरेखाओं से जुड़े बचत के बदलते स्वरूप को भी स्वीकार करना होगा। 15-64 वर्ष की कार्यशील आयु समूह में आबादी का अनुपात निरंतर बढ़कर 2006 के 62.9 प्रतिशत से 2026 में 68.4 प्रतिशत होने की आशा है। तदनुसार, निर्भरता अनुपात (कार्यशील आयु वाली आबादी के प्रति निर्भर लोगों का अनुपात), जो 1991 के 0.80 से गिरकर 2001 में 0.73 हो गया था, और गिरकर 2011 तक 0.59 रह जाने की आशा है (भारत सरकार, 2008)। भौतिक आस्तियों के प्रति घरेलू बचत की संरचना में हुए बदलाव, जो विशेषतः आवास की मांग को दर्शाता है, में बदलती हुई जनसांख्यिकी की भूमिका प्रतीत होती है। तदनुसार, बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे बचतकर्ताओं के क्रमिक रूप से युवा आयु प्रोफाइल से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अभिनव रणनीतियां विकसित करें। भारत में उभर रही एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि सरकारी क्षेत्र के रोजगार में, जिसमें 1983-1994 के दौरान 1.53 प्रतिशत वार्षिक की औसत वृद्धि हुई थी, 1994-2005 के दौरान 0.70 प्रतिशत की गिरावट आयी। दूसरी ओर, संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र का रोजगार उसी अवधि में 0.44 प्रतिशत से बढ़कर 0.58 प्रतिशत हो गया। संगठित रोजगार में हुई वृद्धि में निजी क्षेत्र की अग्रणी भूमिका को देखते हुए, अलग-अलग वित्तीय उत्पादों यथा बीमा और संविदात्मक बचत लिखतों की मांग में कार्यशील आयु वाली आबादी के जोखिम-प्रतिलाभ प्रोफाइल में बदलाव के साथ वृद्धि होगी। जनसांख्यिकी तथा रोजगार के बदलते हुए स्वरूप से कई प्रकार की वित्तीय सेवाओं की मांग उत्पन्न होगी यथा बीमा, आवास

तथा अभिनव विशिष्टताओं वाले अन्य वित्तीय उत्पाद। बदलती जनसांख्यिकी तथा रोजगार के स्वरूप का लाभ उठाने के लिए, बैंकों को ग्राहकों द्वारा मांगी गयी वित्तीय सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराकर निष्क्रिय जमासंग्रहण एवं उधार देने जैसी परंपरागत सीमाओं के बाहर जाकर वित्तीय मध्यस्थों के रूप में अपनी भूमिका का पुनर्निर्माण करना होगा। इसी बात से, ग्राहक बैंकों में अपनी जमा राशियां रखेंगे।

ग्रामीण जमासंग्रहण - नवोन्मेष की जरूरत

4.75 1990 के दशक से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियों में ग्रामीण जमा राशियों के हिस्से में आयी गिरावट की पृष्ठभूमि में, बैंकों के समग्र जमासंग्रहण में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण बचत तक पहुंच के प्रयास तेज करने की जरूरत है। यद्यपि अनेक चुनौतियां हैं, तथापि कम लागत वाले बड़े जमा आधार का लाभ उठाने के लिए, जो अन्य वित्तीय मध्यस्थों को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, ग्रामीण क्षेत्र द्वारा बैंकों को व्यापक अवसर उपलब्ध कराया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव इस संबंध में कुछ उपयोगी पाठ प्रस्तुत करता है।

4.76 ग्रामीण क्षेत्र घरेलू बचतों की छोटी राशि प्रदान कर सकता है जिसका संग्रहण करके बैंक उसे ग्रामीण एवं कृषि उद्यमों के उत्पादक उपयोगों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों के सामने प्रमुख चुनौती यह है कि जमा लेनदेनों में प्रायः छोटी राशियां शामिल होती हैं तथा उनका स्वरूप अनियमित होता है जो छोटे पैमाने के आय अर्जक कार्यक्रमों के मौसमीपन तथा अनियमित स्वरूप को दर्शाता है। इस मांग को पूरा करने के लिए, फिलीपीन्स में कई बैंकों ने 'पिग्गी बैंकिंग' की संकल्पना को अपनाया है, जिसके द्वारा बचतकर्ताओं को छोटे तालाबंद बाक्स उपलब्ध कराये गये जिसे वे न्यूनतम जमा राशि के साथ बचत खाते खोलने के बाद अपने घरों में रख सकते थे। चाबियां बैंकों के पास रहती थीं। इसने ग्राहकों को अपने बाक्सों में दैनिक आधार पर छोटी राशियां बचाने तथा उनकी इच्छानुसार उनके बचत खातों में जमा करने के लिए बैंकों के पास लाने की अनुमति दी। इससे वसूली संबंधी बैंकों के समय में कमी आयी (यूएसएआइडी, 2005)। एक और प्रमुख चुनौती उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान की है, ताकि आबादी के कम घनत्व तथा खराब भौतिक मूलभूत संरचना वाले ग्रामीण व्यवसाय की लागत में उल्लेखनीय कमी की जा सके। जहां इस चुनौती को निभाने के लिए प्रौद्योगिकीय एवं प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) समाधान आवश्यक हैं, बैंकों की दक्षता, सेवा की गुणवत्ता, लाभ और पहुंच की संभाव्यता पर उनके प्रभाव का सतर्कतापूर्वक मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, फिलीपीन्स में स्थानीय प्रौद्योगिकी फर्मों ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तैयार किया ताकि बहुल शाखाओं और इकाइयों एवं केंद्रीय बैंक की डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं संबंधी विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर ने ग्रामीण

बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी के कस्टमाइजेशन तथा उत्पादों में वृद्धि या परिवर्तन के अनुरूप उसके लचीले समायोजन की अनुमति प्रदान की। यह उच्च गुणवत्तावाली तथा कम खर्चीली प्रणाली साबित हुई, जिसने अनेक लेनदेनों तथा कई ग्राहकों की जरूरतें तुरंत और कारगर तरीके से पूरी करने की बैंकों की योग्यता में सुधार कर दिया। इस प्रकार यद्यपि ग्रामीण बचतों को जुटाने में चुनौतियां हैं, अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह दर्शाते हैं कि कुछ नवोन्मेषी पद्धति अपनाकर इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। उपयुक्त अनुकूलन के साथ अन्य देशों का अनुभव ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने तथा ग्रामीण बचतों में तेजी लाने का प्रयास करने वाले बैंकों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।

अन्य मध्यस्थों/बाजारों से प्रतिस्पर्धा

4.77 निधियों के विनियोजन के गुरुतर क्षेत्रों तथा बाजारों के विकास की सहायता से उच्चतर प्रतिलाभ की संभावना सहित, निवेशक क्रमिक रूप से लिखतों तथा संस्थाओं के बीच अपने संविभागों को विशाखीकृत करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न खण्डों की जोखिमों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सेवाओं की मांग करते हैं। इससे मध्यस्थता सेवाओं की मांग के स्वरूप में परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा निवेशक अपनी अतिरिक्त निधियों का निवेश करते समय बैंक जमा द्वारा प्रस्तावित स्थिर प्रतिलाभों से अधिक की अपेक्षा करते हैं। इससे, बदले में, अनेक विशेषीकृत मध्यस्थों/बाजारों का उदय होता है जो निवेशकों की विकसित हो रही जरूरतें पूरी करने में समर्थ होते हैं। 1990 के दशक के आरंभ में भारत में वित्तीय उदारीकरण अपनाने के अनुसरण में चल रहे वित्तीय नवोन्मेषों की पृष्ठभूमि में, इक्विटी शेयरों तथा म्यूच्युअल फंडों के यूनितों जैसी इक्विटी बाजार संबद्ध लिखतों का महत्व, उनमें निहित उच्चतर जोखिम के बावजूद, उन पर मिलने वाले उच्चतर प्रतिलाभों के कारण बढ़ता जा रहा है। एक सीमा तक यह प्रवृत्ति वित्तीय बाजार के विकास की नैसर्गिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके तहत लेनदेन लागत में गिरावट और असममित जानकारी के साथ नयी लिखतें लोकप्रिय होती हैं। जोखिम-प्रतिलाभ संबंधी अवधारणाओं के बेहतर मूल्यांकन में निवेशकों को समर्थ बनाकर, इसने निवेशों का चुनाव व्यापक बना दिया है। इन गतिविधियों सहित बैंकों का परंपरागत जमा आधार कम होने के साथ, अलग-अलग व्यक्तियों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों को रिपैकेज और रिडिजाइन करके उनके द्वारा प्रदान की जा रही विशिष्ट वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाकर भावी जमाकर्ताओं/निवेशकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है।

4.78 तथापि, अपने कार्यक्रमों को विशाखीकृत करते समय बैंकेतर संस्थाओं की तुलना में बैंकों के सामने कई अवरोध हैं। पहला, बैंकेतर संस्थाएं निम्नतर लागत ढांचा रखकर तथा नयी प्रौद्योगिकी को तुरंत अपनाकर उच्चतर प्रतिलाभ का प्रस्ताव करके अपने संसाधनों का प्रबंधन अधिक कारगर तरीके से कर सकती हैं।

इसके अलावा बैंकेतर मध्यस्थ संस्थाएं यथा दलाल, आस्ति प्रबंधन फर्म और म्यूच्युअल फंड उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों सहित विभिन्न निवेशकों के लिए नकदी प्रबंधन तथा धन प्रबंधन जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। दूसरा, बैंकेतर संस्थाओं से भिन्न, बैंकों पर प्रायः आरक्षित निधि अपेक्षाओं, निदेशित उधार, विवेकपूर्ण विनियमन चालित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं तथा पूंजी बाजार एक्सपोजर पर सीमा संबंधी सांविधिक विनिर्देशों जैसी विभिन्न विनियामक अपेक्षाएं लागू होती हैं। जहां इन उपायों से वित्तीय स्थिरता का संवर्धन होता है, वे विकासशील वित्तीय प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए विशाखीकरण संबंधी अवसरों को अवरुद्ध करते हैं। तीसरा, सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित विशेष जमा योजनाएं, जो न सिर्फ उच्चतर प्रतिलाभ का प्रस्ताव करती हैं अपितु कर संबंधी प्रोत्साहन भी प्रदान करती हैं, परंपरागत बैंक जमा राशियों की तुलना में प्रभावी प्रतिलाभ को बढ़ावा देती हैं तथा इस प्रकार जमा संग्रहण संबंधी बैंकों के प्रयास को अवरुद्ध करती हैं। जहां प्रणाली में बैंकों द्वारा अदा की जाने वाली विशेष भूमिका से बैंकों पर लागू विभिन्न प्रतिबंध तथा विवेकपूर्ण अपेक्षाएं न्यायोचित हो सकती हैं, कर लाभों से उत्पन्न नीतिगत अनियमितता को दूर करने की जरूरत है ताकि बैंकों को एक 'लेवल प्लेइंग फील्ड' मिल सके।

जमा राशियों पर निरंतर ध्यान देने की जरूरत

4.79 बैंकों को कम लागत वाली जमा राशि के आधार का लाभ मिलता है जो एक सीमा तक उन्हें दिन प्रतिदिन की बाजार अस्थिरताओं से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार, मूल जमा आधार 'भंडारित चलनिधि' के स्रोत का कार्य करता है जो बाजार से उत्पन्न 'उधार ली गयी चलनिधि' की तुलना में टिकाऊ होता है। एक अन्य भेदकारी विशिष्टता यह है कि जहां जमा दरें अपेक्षाकृत जटिल होती हैं, उधार राशि पर ब्याज दरें बाजार स्थिति के अनुरूप अधिक लचीलेपन के साथ बदलती रहती हैं। प्रचुर चलनिधि तथा कम सांकेतिक दरों की विशिष्टता से युक्त अनुकूल समष्टि आर्थिक स्थितियों के दौरान, वित्तीय जोखिम की कम अवधारणा प्रायः वित्तीय बाजार के प्रतिभागियों को क्रमिक रूप से उच्चतर जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी ओर, न देखी गयी घटना द्वारा कारित उथल-पुथल की अवधि में, निवेशकों द्वारा जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यन बाजार में अत्यधिक अनिश्चितता को उत्प्रेरित करते हैं तथा इस प्रकार अत्यधिक लीवरेजवाली संस्थाओं के सामने चूक संबंधी जोखिम पैदा हो जाती है। अतः, जहां उधार ली गयी चलनिधि के लिए बाजार में पहुंचना लाभप्रद हो सकता है, उधार के साथ जुड़ी अत्यधिक लीवरेजिंग की संभाव्यता अप्रत्याशित घटनाओं से निधि आधार के संरक्षण हेतु पर्याप्त सुरक्षोपायों की मांग करती है। ऐसा यूकेआधारित नार्दन रॉक नामक बैंक के संकट में देखा जा चुका है, जिसके पास भंडारित चलनिधि की तुलना में उधार ली गयी चलनिधि का हिस्सा उच्चतर था। ऋण स्थितियों

की सख्ती के कारण बाजार से निधियां जुटाने की समस्या से ग्रस्त, बैंक का कार्यनिष्पादन प्रतिकूल तौर पर प्रभावित हुआ जिससे जमाकर्ता बड़ी संख्या में अपनी राशि का आहरण करने के लिए उत्प्रेरित हुए और अंततः बैंक में भगदड़ मच गयी।

4.80 भारत स्थित बैंक अपनी निधायन संबंधी अपेक्षा के लिए परंपरागत रूप से जमा राशियों पर निर्भर रहे हैं। उधार राशि पर उनकी निर्भरता नगण्य है। अर्थव्यवस्था का विस्तार होने तथा निधियों की मांग बढ़ने के साथ, बैंक कभी-कभी बढ़ती मांग की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने जमा संसाधनों को अपर्याप्त पा सकते हैं, इस प्रकार, वे उधार के जरिए निधियां जुटाने हेतु प्रोत्साहित होते हैं। नार्दन रॉक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान भारी मात्रा में लिए गए उधार का बैंकों पर गंभीर असर पड़ सकता है, अतः उधार पर अत्यधिक निर्भरता को टाले जाने की जरूरत है। बैंकों द्वारा इस प्रकार के उधार का आश्रय लिए जाने की स्थिति में, उन्हें उपयुक्त आंतरिक जोखिम प्रबंधन रणनीतियां भी अपनानी चाहिए। विशेष रूप से, जहां हाल के वर्षों में भारत में बैंकों को दिया गया अधिक लचीलापन संसाधन जुटाने के नए अवसर प्रदान करता है, उससे जुड़ी जोखिमों में वृद्धि लागतों को न्यूनतम करके उनकी देयताओं के उपयुक्त प्रबंधन की मांग करती है तथा जोखिमों का शमन ब्याज दरों तथा विनिमय दरों में प्रतिकूल गतिविधियों से उत्पन्न होता है। उन्हें अपनी कारोबारी रणनीतियों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि वे दीर्घावधि अर्थक्षम वित्तपोषण को परिचालनों में लाभप्रदता के साथ संयुक्त कर सकें।

बैंकों में कौशल के विकास की आवश्यकता

4.81 देश तथा विदेश दोनों में बैंकेतर संस्थाओं तथा पूंजी बाजार लिखतों से मिलनेवाली प्रतिस्पर्धा, जो भविष्य में बढ़ सकती है, का सामना करने के लिए बैंकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा तथा उसे सही तरीके से पैकेज करना पड़ेगा, जिसके लिए बैंकों के स्तर पर उपयुक्त कौशल विकास की आवश्यकता पड़ेगी। जहां बैंकों के पास संभाव्यता है, उन्हें अभिनव उत्पाद विकसित करने तथा बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को देखते हुए नयी सेवा पद्धतियां तैयार करने के लिए सभी स्तरों पर कौशल संवर्धन में बड़ी मात्रा में निवेश करना होगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सामने निजी और विदेशी बैंकों की तुलना में अनम्य मुआवजा संरचना के आलोक में नए कार्मिक आकृष्ट करने तथा बनाए रखने के लिए और अधिक चुनौतियां हैं।

मौद्रिक नीति के निहितार्थ

4.82 आगे चलकर उच्च वृद्धि क्षेत्र में संक्रमण के अनुरूप संसाधन संग्रहण के कारण बैंकों तथा बैंकेतर संस्थाओं दोनों के स्तर पर अधिक उत्पाद नवोन्मेष की संभावना है। बैंकों तथा बैंकेतर संस्थाओं

के बीच अंतर अस्पष्ट होते जाने तथा अन्य बचत लिखतों के साथ बैंक जमाराशियों की अधिक उपयुक्तता को देखते हुए, नीतिगत परिप्रेक्ष्य तैयार करते समय मौद्रिक समुच्चयों का मूल्यांकन सतर्कतापूर्वक करना होगा। साथ ही, वित्तीय लिखतों में नई विशिष्टताएं शामिल करने का प्रभाव मुद्रा की अभिज्ञेय विशिष्टताओं पर आधारित लेखांकन की परंपरागत पद्धति पर पड़ेगा। विकास की प्रक्रिया सुदृढ़ तथा अधिक समावेशक होने के साथ आवास, शहरी सेवाओं, खुदरा तथा उपयोगी वस्तुओं की मांग खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होने के साथ बढ़ने की संभावना है। ऐसे परिदृश्य में यह संभव है कि बैंक ऋण तथा मौद्रिक समुच्चय में वृद्धि चल रहे संरचनागत परिवर्तनों को देखते हुए, ऐतिहासिक संबंधों तथा लचीलेपन से आशा किए गए स्तर की तुलना में विसामान्य हो तथा ऐसी बनी रहे। इससे मुद्रा/ऋण विस्तार से मुद्रास्फीति, आस्ति मूल्यों तथा प्रणालीगत तरलता के संकेत पढ़ने में स्पष्टता के महत्वपूर्ण मुद्दे उभरकर आते हैं।

VI. सारांश

4.83 ऐतिहासिक रूप से भारत स्थित बैंकों ने वृद्धि की प्रक्रिया के समर्थन के लिए संसाधन जुटाने और उनका आबंटन करने में केंद्रीय भूमिका निभायी है। 1969 में निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर था। उसके बाद बड़े पैमाने पर हुए शाखा विस्तार के कारण ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों का जमा आधार बढ़ गया। यद्यपि 1980 में हुए राष्ट्रीयकरण के एक और दौर ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पूंजी बाजार की उछाल की पृष्ठभूमि में म्यूच्युअल फंडों तथा एनबीएफसी की निधि संग्रहण संबंधी आक्रामक रणनीतियों ने घरेलू बचतों की कुछ विमध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की। अविनियमित बाजार माहौल के तहत बचत अधिमानों की परिपक्वता के अनुरूप 1995-2005 के दौरान बैंक जमा वृद्धि में पुनः कुछ कमी देखी गई। तथापि, ऋण में सुदृढ़ उठाव को देखते हुए बैंकों द्वारा किए जा रहे जमा संग्रहण संबंधी प्रबल प्रयासों के कारण 2005-08 के दौरान बैंक जमाराशियों की वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आई। ऐसा शेरयों एवं म्यूच्युअल फंडों के यूनितों जैसी अन्य लिखतों में तेज वृद्धि के बावजूद हुआ।

4.84 भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक जमाराशियां हमेशा बचत प्रक्रिया का मुख्य अंग रही हैं। यद्यपि बैंकों ने वित्तीय बचत दर बढ़ाने में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि भौतिक बचतों में वित्तीय बचतों के अनुरूप बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। इस प्रकार, अनुत्पादक भौतिक बचतों को वित्तीय बचतों में परिवर्तित करना एक प्रमुख चुनौती है। बैंकों के लिए यह भी जरूरी है क्योंकि एक वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में जमा संग्रहण की पूरी संभाव्यता के दोहन में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार की वैकल्पिक बचत लिखतों की उपलब्धता, जिनके द्वारा बचतकर्ताओं को उच्चतर प्रतिलाभों का प्रस्ताव किया जाता है, के कारण घरेलू क्षेत्र के लिए बैंक जमाराशियां अपेक्षाकृत कम आकर्षक हो गयी हैं। इसके अलावा, बचतकर्ताओं को अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा प्रस्तावित विशेषीकृत सेवाओं के उपयोग के माध्यम से उनके संविभाग के जोखिम प्रबंधन की जानकारी भी बढ़ गई है। भविष्य में इस व्यवहार में तीव्रता आने की आशा है। कुल जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र की जमाराशियों के सिकुड़ते हुए हिस्से को देखते हुए, इस बात की जरूरत है कि बैंक जमाकर्ता आधार व्यापक करने तथा साथ ही अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए सेवाओं में सुधार लाने के उपायों की तलाश करें। अतः यह आवश्यक है कि बैंक जमाराशियों के नए स्रोतों की खोज करें। ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काफी संभावना है तथा बैंकों द्वारा इन स्रोतों का उपयोग किए जाने की जरूरत है। तथापि इसके लिए यह अपेक्षित होगा कि बैंक कस्टमाइज्ड उत्पाद लाएं जो अलग-अलग व्यक्ति की जोखिम-प्रतिलाभ अपेक्षाओं के अनुकूल हों तथा साथ ही वे अपने कार्यकलापों को विशाखीकृत करके परिचालन लागत को कम करें। इस संदर्भ में, वित्तीय समावेशन पर हाल में दिए गए नीति संबंधी बल में अपना जमा आधार बढ़ाने के लिए बैंकों के लिए काफी गुंजाइश है। इसके अलावा, बदलती हुई जनसांख्यिकी तथा रोजगार के स्वरूप ने भी बैंकों को अपने दायरे में युवा आयु वर्ग के जमाकर्ताओं को लाकर उनकी भूमिका व्यापक बनाने के अवसर खोल दिए हैं। निधियों का बैंकों से बैंकेतर लिखतों तथा इसके विपरीत प्रतिस्थापन हाल में देखा गया है तथा भविष्य में भी ऐसी प्रवृत्तियां जारी रह सकती हैं। इसके लिए मौद्रिक समुच्चयों के आकलन और इनकी व्याख्या में गुरुतर सावधानी की जरूरत होगी।